



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253510
CG-DL-E-05042024-253510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 86]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली 28 मार्च, 2024

मामला सं. ए.डी. (ओआई) – 03/2023

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया में उत्पन्न या निर्यात किये गए 'सोडियम साइनाइड' के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच।

फा.सं. 6/03/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण), नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

मामले की पृष्ठभूमि

- हिंदुस्तान कैमिकल कंपनी (एचसीसी) और यूपीएल लिमिटेड (यूपीएल) ("इसके बाद इन्हें 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग'" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे 'प्राधिकारी' के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और पाटनरोधी

नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे 'नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया गणराज्य (इसके बाद इन्हें 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) से "सोडियम सायनाइड (एनएसीएन)" के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र-असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. 6/03/2023-डीजीटीआर के महत् एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया है।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र-असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
 - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देशों से निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। संबद्ध पक्षकारों से जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध करने के लिए अनुरोध किया गया था।
 - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
 - v. उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे संबंधित संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए परामर्श दें।
 - vi. हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आवेदन को परिचालित करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो उत्पादक नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था।
 - vii. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर इनपुट की मांग करते हुए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग सहित हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (इसके बाद इसे 'ईआईक्यू' के रूप में कहा गया है) भी जारी की।
 - viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी, जिनके संपर्क ब्यौरे आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए थे।

क्र.सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक
1	चीन जन.गण.	i. हेबेई चेंगसिन कं. लिमिटेड ii. झेजियांग केमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट

		iii. जेएसएम (शेनझेग) इंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड iv. ऐसम्बली केमिकल्स कंपनी लिमिटेड v. अनहुई एन्विंग शनचुआंग केमिकल
2	यूरोपीय संघ	i. साइप्लस जीएमबीएच (इवोनिक सब्सिडयरी) ii. इवोनिक इंडस्ट्रीज एजी iii. द्रासलोवका होल्डिंग बी.वी. iv. यूनियन ग्रुप केमिकल कंपनी एस.एल.
3	जापान	i. सोजिटज कार्पोरेशन
4	कोरिया गणराज्य	i. हन्वा कार्पोरेशन ii. यूनिड ग्लोबल कार्पोरेशन iii. डीके मेटल वर्ल्ड लिमिटेड

- ix. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक
1	चीन जन.गण.	i. हेबेई चेंगसिन कं. लिमिटेड
2	यूरोपीय संघ	i. साइप्लस जीएमबीएच ii. लुसेबनी जावोदी द्रासलोवका ए.एस. कोलिन
3	जापान	ii. निप्पन सोडा कं. लिमिटेड iii. सोजिटज कार्पोरेशन
4	कोरिया गणराज्य	i. ताइकवांग इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड

- x. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों को, जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा जिन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है, जांच में असहयोगी माना गया है।
- xi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1.	अरशिया लॉजिस्टिक्स सर्विस लिमिटेड
2.	एससेंट फिनकेम प्राइवेट लिमिटेड
3.	अशोका मेटा केम इंडस्ट्रीज
4.	एशियन केमटेक प्राइवेट लिमिटेड

5.	बेंजो केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
6.	भारत रसायन लिमिटेड
7.	केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड
8.	केमप्लास्ट इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10.	डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
11.	डाइविस लैबोरेट्रीज लिमिटेड
12.	एमेन्नर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
13.	यूरोफाइन केमिकल्स
14.	घरदा केमिकल्स लिमिटेड
15.	गरायुएर एंड वेली(आई) लिमिटेड
16.	हेमानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
17.	हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18.	हिकाल लिमिटेड
19.	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
20.	हॉनर लैब लिमिटेड
21.	इन्वेंटिज रिसर्च कंपनी लिमिटेड
22.	जागो ओवरसीज
23.	एम.बी. सेल्स कापॉरेशन
24.	महावीर एक्सपोकेम लिमिटेड
25.	मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड
26.	प्रीमियर इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	राठौर ट्रेडिंग कंपनी
28.	सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	संजय केमिकल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड
30.	श्री गणेश केमिकल्स
31.	श्यामल केमिकल इंडस्ट्रीज
32.	टैग्रोस केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

33.	टेक्नो कमर्शियल ट्रेडर्स
34.	टेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35.	यमुना मेटा केम

- xii. भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1	एशियन केमटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	भारत रसायन लिमिटेड
3	केमटेक इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
5	यूरोफाइन केमिकल्स लिमिटेड
6	एममेनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
7	हेमानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	एम बी सेल्स कॉर्पोरेशन
9	मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड
10	प्रीमियर इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

- xiii. वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध जांच के लिए उस पर भरोसा किया है।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 (12 माह) तक की है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल है।
- xv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 7 दिसंबर, 2023 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, उन्हें अपने मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) अनुरोध यदि कोई हो, दायर करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।
- xvi. क्षति रहित कीमत (इसके बाद इसे 'एनआईपी' के रूप में कहा गया है) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभों के आधार पर किया गया है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे।

- xvii. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की गई है और आवश्यकता के अनुसार स्थल सत्यापन के दौरान सत्यापन किया गया है तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए भरोसा किया गया है।
- xviii. संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की आवश्यकता के अनुसार डेस्क सत्यापन के माध्यम से भी जांच की गई थी और वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए भरोसा किया गया है।
- xix. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के माध्यम से, निर्धारित तरीके से विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठन उपलब्ध कराया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की ऐसे गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी।
- xx. प्राधिकारी ने इस अवस्था में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और उठाए गए सभी तर्कों के संबंध में साक्ष्य और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए जाने के अनुसार विचार किया है।
- xxi. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, इच्छुक पार्टियों को 19 मार्च, 2024 को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 24 मार्च 2024 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम खोज अधिसूचना में, इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर प्रासंगिक और गैर-दोहरावीय सीमा तक विचार किया गया है।
- xxii. इस दस्तावेज में *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 7 के तहत उस पर विचार किया है।
- xxiii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई जांच की अवधि (अक्तूबर 2022 – सितंबर 2023) के लिए विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 77.48 रुपए है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:-

“3 वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम सायनाइड है, जो कि मध्यम रूप से मजबूत बेस है। यह फार्मूला एनएसीएन के साथ एक जहरीला कंपाउंड है। यह सफेद रंग में है और पानी में घुलनशील ठोस है सायनाइड की धातुओं के साथ अधिक सादृश्यता है और इस प्रकार इस बेस के लिए अधिक विषाक्तता होती है।

4. उपयोग: विचाराधीन उत्पाद का उपयोग उनके संबंधित अयस्कों से सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, धातुओं के ताप उपचार (केस हार्डनिंग), कीटनाशकों, रंजकों, रंगद्वयों पिगमेंट, थोक दवाओं के निर्माण और कई कार्बनिक संश्लेषणों, कृषि रसायनों, नाइलोन मध्यवर्तियों, जेलेटिंग यौगिकों, अयस्क फ्लोटेशन और दवा मध्यवर्तियों के लिए किया जाता है।

5. टैरिफ वर्गीकरण: विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 283711 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विगत में विचाराधीन उत्पाद को अन्य उप शीर्षों जैसे 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 और 28371910 के अंतर्गत भी आयात किया गया है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है-

- क. विचाराधीन उत्पाद सोडियम सायनाइड (एनएसीएन) पाउडर या सिलेंड्रिकल टेबलेट के रूप में मौजूद है। यूपीएल द्वारा केवल लिक्विड सोडियम सायनाइड का एक उप उत्पाद के रूप में उत्पादन किया जाता है। याचिका और जांच शुरुआत अधिसूचना उत्पाद, बिक्री और आयातित किए जाने वाले सोडियम सायनाइड के

विभिन्न रूपों का पता लगाने में विफल रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण ब्यौरे की अनदेखी की है।

- ख. उत्पाद की बिक्री बाजार में पाउडर, टेबलेट और लिक्विड रूप में की जाती है और उसकी सान्द्रता भिन्न है। उत्पाद की कीमतें, जिस रूप में इसकी बिक्री होती है, उसके आधार पर अलग अलग हैं।
- ग. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति की जरूरत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां नहीं मांगी।
- घ. यूपीएल के समक्ष उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में समस्याएं आई हैं, क्योंकि उत्पाद की शुद्धता का स्तर 98% के स्तर पर नहीं रहा है।

ग.2 आवेदकों की ओर से किए गए अनुरोध

6. आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद सोडियम सायनाइड है, जो कि एक मध्यम रूप से मजबूत बेस है। यह फार्मूला एनएसीएन के साथ एक जहरीला कंपाउंड है। यह सफेद है और पानी में घुलनशील ठोस है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 283711 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, विगत में उत्पाद को अन्य उप शीर्षों जैसे 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 और 28371910 के अंतर्गत भी आयात किया गया है।
- ग. उत्पाद के सभी उत्पादक पहले लिक्विड रूप में उत्पादन करते हैं। तथापि, इसे उत्पाद की प्रकृति, व्यापार और लिक्विड रूप में उत्पाद की बिक्री करने में कठिनाई को देखते हुए ठोस रूप में लाने ले जाने को तरजीह दी जाती है।
- घ. उत्पाद को 30% साल्यूसन बनाने के लिए पानी में मिलाए जाने के बाद अंतः लिक्विड रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि उत्पाद का ठोस या लिक्विड रूप में लेन देन किया जाता है, तो यह पूरी तरह से असंगत है।
- ड. केवल यह तथ्य कि सोडियम सायनाइड भी लिक्विड रूप में भी लाया ले जाया और प्रयोग किया जाता है, इससे सोडियम सायनाइड ठोस और लिक्विड रूप के विभिन्न उत्पाद नहीं बनते।
- च. आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के “समान वस्तु” हैं।
- छ. एमेन्नर फार्मा प्रा. लि. का यह दावा कि आवेदक अपेक्षित शुद्धता प्रदान नहीं कर सकता, इसका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया शुद्धता का अंश 98% से अधिक है, जो आयातों की गुणवत्ता के अनुकूल है। यद्यपि प्रयोक्ता ने पहले कोई सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने हाल ही में घरेलू उद्योग को आंशिक रूप से अपनी मांग भेजनी शुरू की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 7. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें इस प्रकार शामिल किया है।
- 8. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि आवेदक प्रयोक्ता उद्योग की अपेक्षा के अनुसार 98% शुद्धता स्तर के साथ उत्पाद प्रदान करने में असमर्थ है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने बिक्री इनवायंस और 98% की शुद्धता के साथ उत्पाद की बिक्री दर्शाते हुए विश्लेषण प्रमाण-पत्र प्रदान किए हैं। आवेदकों ने अतिरिक्त रूप से यह उल्लेख किया है कि एमेन्नर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी जरूरत आयात की बजाय घरेलू उद्योग से पूरी करनी शुरू की है और यद्यपि प्रतिवादी पहले अपनी समग्र जरूरत आयातों से पूरी कर रहा था लेकिन अब घरेलू उद्योग को अपनी

जरूरत का कुछ हिस्सा भेजना शुरू कर दिया है। उपरोक्त के आलोक में, हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क कि आवेदक उत्पाद को अपेक्षित मानक के साथ प्रदान नहीं करता, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9. घरेलू बाजार में बिक्री किए जा रहे उत्पाद के साथ के संबंध में, यह देखा गया है कि सोडियम सायनाइड को शुरू में उत्पादित करके अंततः लिक्विड रूप में खपाया जाता है। तथापि, उत्पाद की प्रकृति, लाने ले जाने में आसानी और उसमें शामिल व्यापार को ध्यान में रखते हुए, इसे यातायात के प्रयोजन से ठोस रूप में, अर्थात् टेबलेट/ब्रिकेट के रूप में परिवर्तित करने को तरजीह दी गई। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के लिए दिनांक 6 अगस्त, 2023 को जारी अपने स्पष्टीकरण पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि विचाराधीन उत्पाद सोडियम सायनाइड है, चाहे इसका रूप कुछ भी हो। सोडियम सायनाइड का लिक्विड रूप कुछ भी नहीं है, केवल पानी के साथ मिश्रित उत्पाद है। लिक्विड रूप को ठोस में बदला जा सकता है और ठोस रूप को पुनः लिक्विड रूप में आसानी से और उत्पाद के रासायनिक गुणों में बिना कोई बदलाव किए परिवर्तित किया जा सकता है। सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित ठोस रूप और लिक्विड रूप उत्पाद के सभी अनिवार्य गुणों के संदर्भ में तुलनीय है।
10. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने पीसीएन की जरूरत पर टिप्पणियां नहीं मांगी, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को पत्र भेजे गए थे, जो विभिन्न अनुरोधों की समय सीमा को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, जिसमें पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय शामिल है। तथापि, एक हितबद्ध पक्षकार, हेबेई चेंगसिन लि., जिसने यह अनुरोध किया कि इस मामले में पीसीएन-वार विश्लेषण आवश्यक नहीं है, को छोड़कर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने जांच में उपरोक्त अवसर का लाभ नहीं लिया और निर्धारित समय सीमा के भीतर पीसीएन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। अतः प्राधिकारी इस तर्क को पूरी तरह से निराधार मानते हैं।
11. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम सायनाइड है, जो कि मध्यम रूप से मजबूत बेस है। यह फार्मूला एनएसएन के साथ एक जहरीला कंपाउंड है। यह सफेद रंग में है और पानी में घुलनशील ठोस है। सायनाइड की धातुओं के साथ अधिक सादृश्यता है और इस प्रकार इस बेस के लिए अधिक विषाक्तता होती है।
12. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग उनके संबंधित अयस्कों से सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, धातुओं के ताप उपचार (केस हार्डनिंग), कीटनाशकों, रंजकों, रंगद्रव्यों (पिगमेंट), थोक दवाओं के निर्माण और कई कार्बनिक संश्लेषणों, कृषि रसायनों, नाइलोन मध्यवर्तियों, जेलेटिंग यौगिकों, अयस्क फ्लोटेशन और दवा मध्यवर्तियों के लिए किया जाता है।
13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा सोडियम साइनाइड है, चाहे इसका स्वरूप कुछ भी हो। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण के उप शीर्ष 283711 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को अन्य उप शीर्षों जैसे 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 और 28371910 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और यह विचाराधीन उत्पाद अथवा पाटनरोधी शुल्क के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।
14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आयात किया गया उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद के तुलनात्मक है। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों को बदल बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद में नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देशों से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु शामिल है।

घरेलू उद्योग का दायरा और आधार**घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. एचसीसी, यूपीएल और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचसीसी की मूल कंपनी जांच की अवधि से पूर्व, इसके दौरान और इसके बाद पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुओं की स्वाभाविक/नियमित आयातक और ट्रेडर हैं।
- ख. आवेदकों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और इसका व्यापार किया है, क्योंकि पर्यावरणीय मामलों, तकनीकी मामलों तथा समय-समय पर उन पर लगाए गए विनियामक प्रतिबंध के चलते उत्पादन की नियमित रुकावट के कारण वे उत्पादन और आपूर्ति के लिए असमर्थ रहे हैं।

घ.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में आवेदकों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं।
- ख. एचसीसी (विगत में सायनाइड एंड कैमिकल कंपनी के रूप में ज्ञात) हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है और यह 35 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल रही है।
- ग. यूपीएल लिमिटेड ने 500 करोड़ रु. के निवेश के साथ हाल ही में भारत में एक नया संयंत्र स्थापित किया है और अप्रैल, 2021 से विचाराधीन उत्पाद का अपना उत्पादन शुरू किया है।
- घ. दोनों ही उत्पादकों ने विगत में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया था। जबकि यूपीएल ने वाणिज्यिक उत्पाद शुरू होने से पूर्व कैप्टिव खपत के लिए आयात किया है, हिंदुस्तान कैमिकल कंपनी ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार के प्रयोजन के लिए आयात किया है।
- ड. एचसीसी द्वारा आयात 2019-20 में किए गए थे, जब इसका संयंत्र बंद था। ये आयात गैर-संबद्ध देशों से थे।
- च. आवेदकों ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- छ. आवेदक संबद्ध देशों में किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. यह आवेदन हिंदुस्तान कैमिकल कंपनी और यूपीएल लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है।

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस तरह से परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

19. जहां तक आवेदकों के नियमित आयातक और ट्रेडर रहने का संबंध है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए सौदा-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि एचसीसी द्वारा समग्र आयात 2019-20 और 2020-21 की अवधि में हैं। जांच की अवधि में एचसीसी द्वारा कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, एचसीसी की मूल कंपनी ने जांच की अवधि में किसी उत्पाद का आयात नहीं किया है।

20. नीचे दी गई तालिका में एचसीसी द्वारा विगत वर्षों के दौरान किए गए आयातों को दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	***	***	कोई आयात नहीं	
2	गैर-संबद्ध देशों से आयात	एमटी	***	***		
3	संबद्ध देशों के आयातों के संदर्भ में आयात	%	***	***		
4	उत्पादन के संदर्भ में आयात	%	***	***		

21. इसके अलावा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि एचसीसी की मूल कंपनी ने जांच की अवधि में उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सौदा-वार आयात के आंकड़ों में जांच की अवधि में हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए किसी आयात को नहीं दर्शाया गया है।
22. यह अनुरोध किया गया है कि यूपीएल ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 में आयात किया था। ये आयात यूपीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पूर्व किए गए थे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि में यूपीएल द्वारा कोई आयात नहीं किया गया है।
23. नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों के दौरान यूपीएल द्वारा किए गए आयातों को दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	***	***	कोई आयात नहीं	
2	गैर-संबद्ध देशों से आयात	एमटी	***	***		
3	संबद्ध देशों के आयातों के संदर्भ में आयात	%	***	***		
4	उत्पादन के संदर्भ में आयात	%	कोई उत्पादन नहीं			

24. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह वर्णन कि केवल शट डाउन के कारण ही आवेदकों द्वारा आयात किए जा रहे थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेदकों ने मुख्य रूप से मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने और अपने ग्राहकों को रखने के लिए विगत में भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कोई पाटन नहीं था और आवेदकों द्वारा अपाटित कीमतों पर आयात किए गए थे।
25. प्राधिकारी को यह जांच करने की जरूरत होती है कि क्या किसी आवेदक ने इतनी बड़ी मात्रा में आयात किया है कि उसकी प्रकृति एक आयातक या ट्रेडर की हो गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही आवेदकों ने मुख्यतः भारतीय मांग को पूरा करने के लिए विगत में आयात किए थे। तथापि, एक आवेदक ने तो यहां तक कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रु. का पर्याप्त निवेश किया है। प्राधिकारी को यह जांच करनी भी अपेक्षित है कि क्या आवेदक ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। आवेदकों ने यह भी प्रमाणित किया कि वे भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
26. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एचसीसी और यूपीएल ही भारत में उत्पादक हैं और वे मिलकर कुल भारतीय उत्पादन का 100% उत्पादन करते हैं और प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करते हैं।

गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. आवेदकों के समक्ष अत्यधिक गोपनीयता की समस्या है क्योंकि संगत सूचना को गोपनीय रखा गया है। संगत सूचना को सूचीबद्ध रूप में भी नहीं दिया गया है।
- ख. कास्टिंग फॉर्मेट, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, प्रतिशतता में लाभप्रदता और पाटन मार्जिन के पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ग. आवेदकों ने जांच की अवधि में स्वयं के आयातों पर सूचना को नष्ट कर दिया है।
- घ. रोके जा रहे उत्पादन के व्यौरों के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है।

ड.2 आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

28. आवेदकों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदकों ने किसी अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है। समग्र सूचना को दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के तहत प्रकट किया गया है।
- ख. कास्टिंग फॉर्मेट में दी गई सूचना, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता के संबंध में सूचना कारोबारी संवेदनशील सूचना है और इसका सारांश नहीं दिया जा सकता।
- ग. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदकों ने जांच की अवधि में स्वयं के आयातों के संबंध में सूचना को नष्ट कर दिया है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच की अवधि में कोई भी आयात नहीं हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के तहत और व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 (प्राधिकारी द्वारा अगली सूचना तक विस्तारित) के तहत सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम में 7 के तहत यह प्रावधान है:-

गोपनीय सूचना : (1) नियम के उपनियमों 6(2), (3) और (7) के उपनियम 12 नियम, (2) के उपनियम 15 नियम, (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम के उपनियम 5 (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

31. रिलायंस इंडस्ट्रीज में माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में अपने निर्णय पर भरोसा किया है। स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज ने गोपनीयता के महत्व पर बल दिया था। उस निर्णय के पैरा 3 में, यह पुष्टि की गई थी कि:

3.....नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वचालित रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए। निस्संदेह, ऐसे मामलों में, गोपनीयता की जरूरत होती है, अन्यथा व्यापार प्रतिस्पर्धी गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेंगे, जो वे अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या प्रदान की गई सूचना को गोपनीय रखे जाने की जरूरत है, उस पर

मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी पर है कि वे यह निर्णय लें कि क्या कोई विशेष सामग्री गोपनीय रखे जाने की जरूरत है।

32. प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना की समीक्षा की। दावों को प्रमाणित पाए जाने पर, प्राधिकारी ने गोपनीय अनुरोधों के लिए, आवश्यकता के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी संवेदनशील सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अप्रकट रहे। ऐसी स्थितियों में, जहां ऐसा संभव था, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले संस्थानों को, गोपनीय रूप से प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ के वितरण में सुविधा प्रदान की और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने अनुरोधों के इन अगोपनीय पाठों को साझा करने का निदेश दिया।
33. जहां तक एचसीसी के रोके जा रहे उत्पादन के गोपनीय होने के दावे के संबंध में अनुरोध का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसे आवेदन में और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोध में प्रकट कर दिया गया था। अतः यह तर्क गलत है।
34. जहां तक कॉस्टिंग फॉर्मेट में दी सूचना कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता की सूचना में गोपनीय होने का दावा किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन मापदंडों के संबंध में सूचना कारोबारी संवेदनशील सूचना है, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता। आवेदकों को दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 08/2018 के तहत गोपनीय सूचना को प्रकट करने की जरूरत थी और आवेदकों ने इस अपेक्षा को पूरा किया।

विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मामलों के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:-

- क. दिनांक 23 मई, 2012 की व्यापार सूचना सं. 04/2012 के तहत, आवेदकों को एक दिन पहले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत सूचना को परिचालित किए जाने की जरूरत थी। आवेदकों ने सूचना परिचालित नहीं की थी।
- ख. प्राधिकारी ने टिप्पणियों अथवा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था।
- ग. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति का सुझाव देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को कोई अवसर नहीं दिया है।
- घ. चूंकि उत्पाद को ठोस और लिक्विड, दोनों रूपों में बेचा जाता है, अतः उन्हें पीसीएन का आधार बनाना चाहिए और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण पीसीएन पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ड. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एचसीसी के संयंत्र को बंद किए जाने के संबंध में सूचना को आवेदकों द्वारा जान-बूझकर छिपाया गया है।
- च. वास्तव में, जब कीमतों में कोई वास्तविक गिरावट नहीं है, तो आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए -'प्राइम कॉस्ट' नामक एक नई संकल्पना लाई गई है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, आवेदक एचसीसी विचाराधीन उत्पाद से भारी योगदान/लाभप्रदता के साथ जांच की अवधि से पूर्व और बाद में अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा है। इस योगदान/लाभप्रदता में जांच की अवधि में मामूली गिरावट आई क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, बुनियादी कच्ची सामग्रियों की कीमतों में अस्थायी वृद्धि हुई थी, जिसे जान बूझकर एक अवधि छांट कर पाटित आयातों के प्रभाव के रूप में दिखावटी रूप से छिपाया जा रहा है।
- छ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के रूप में इस अवधि का छांट कर चयन किया है ताकि क्षति की एक ऐसी तथ्यरचना बनाई जा सके, जहां कुछ भी नहीं था। इस अवधि के दौरान, अमोनिया और कॉस्टिक सोडा की कीमतों में अस्थायी वृद्धि हुई थी, जिससे भी आयात कीमतों में काफी वृद्धि हुई थी।

- ज. क्रेच रिपब्लिक के पास भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का तीन प्रतिशत से भी कम है। अनुच्छेद 5.8/नियम 14(घ) के तहत न्यूनतम परीक्षण किसी विशेष 'देश' के लिए लागू किया जाना चाहिए न कि किसी परिक्षेत्र के लिए। अतः यूरोपीय संघ में केवल दो उत्पादकों (क्रेच रिपब्लिक से प्रतिवादी, जिसके आयात ही क्रेच रिपब्लिक के ही आयातों के न्यूनतम से अधिक हैं और 'साइप्लस जीएमबीएच' जर्मनी, जिसके आयात ही न्यूनतम सीमा से अधिक हैं) में क्रेच रिपब्लिक के ही आयातों पर विचार किया जाना चाहिए।
- झ. संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय आयातों में क्रेच रिपब्लिक का हिस्सा कुल आयातों के 3% से भी कम है। जांच को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, यदि एक देश से आयातों का हिस्सा भारत में कुल आयातों का 3% से भी कम है।
- ञ. यह आवेदन मूल रूप से चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य के खिलाफ दायर किया गया था, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 8 से स्पष्ट है न कि क्रेच रिपब्लिक के खिलाफ।

च.2 आवेदक की ओर से किए गए अनुरोध

36. आवेदकों ने विविध मामलों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. सार्वजनिक सुनवाई में आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना की समग्रता प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए लिखित अनुरोधों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित अनुरोधों का भाग है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों के पास उस पर टिप्पणियां देने का अवसर था।
- ख. वर्ष 2019-20 को छोड़कर, जब एचसीसी का संयंत्र सरकारी प्रतिबंधों के चलते बंद था, आवेदकों पर कोई अन्य नियामक प्रतिबंध नहीं रहा।
- ग. एचसीसी द्वारा संयंत्र बंद होने के संबंध में सूचना आवेदन का भाग है। सूचना को छिपाया नहीं गया है।
- घ. इसकी खतरनाक प्रकृति होने के कारण अस्थायी प्रकृति के कारण उत्पाद को इसके लिक्विड रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता और उत्पाद का लिक्विड रूप में कोई आयात नहीं है। अतः पीसीएन पद्धति की कोई जरूरत नहीं है।
- ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि को छांट कर चुना गया है, पाटन और क्षति की जांच के लिए वैश्विक जांच प्राधिकारियों द्वारा एक 12 माह की अवधि उपयुक्त मानी गई है। आवेदकों ने जांच की अवधि और इसके तत्काल पूर्व के वित्तीय वर्ष में भी वास्तविक क्षति का सामना किया है और यह नहीं माना जा सकता कि यह एक अस्थायी स्थिति थी।
- च. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क में प्रयुक्त शब्द 'देश या परिक्षेत्र' हैं। नियम अधिनियम से ऊपर नहीं हो सकते अथवा अधिनियम के दायरे को सीमित नहीं कर सकते। नियमों को अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। पाटनरोधी नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत बनाया गया है। नियमों और कानून को पूरा पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान को दूसरे प्रावधानों के संदर्भ में आशय लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे नियम को एक संगत अधिनियम बनाया जा सके। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में प्रयुक्त शब्द देश अथवा परिक्षेत्र है, तो इसे इस तरह से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि नियमों में 'देश' शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे कानून का दायरा सीमित हो जाता है।
- छ. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने "प्राइम कॉस्ट" की एक नई संकल्पना शुरू की है। यह देखा गया है कि प्राइम कॉस्ट की गणना विगत वर्षों की कीमत संबंधी प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए की गई है। यह दावा किया गया है कि आयात कीमत उत्पादन की लागत में परिवर्तनों के अनुसार नहीं की गई है। कीमत के मूल्यांकन की एक जांच को प्राधिकारी द्वारा निरंतर जांचा गया है। कीमत के मूल्यांकन की जांच करने के लिए विचार किए गए कारक मामले के तथ्यों के आधार पर एक जांच से दूसरी जांच के लिए अलग अलग हैं। ऐसे मामलों में, जहां कच्ची सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, प्राधिकारी ने विगत वर्षों की आयात कीमत की सामान्य जांच की है। ऐसे मामले में, जहां कच्ची

सामग्री की कीमत में पर्याप्त उतार-चढ़ाव आया है, प्राधिकारी ने आयात कीमत की कच्ची सामग्री की कीमतों के साथ तुलना की है। वर्तमान मामले में सभी पक्षकारों ने यह स्वीकार किया है कि कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी की कीमतों में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी तर्क दिया है कि चूंकि यूपीएल ने हाल ही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, यूपीएल की लागत निर्धारित लागतों के संबंध में अधिक होगी। अतः पहुंच कीमत के साथ प्राइम कास्ट (कच्ची सामग्री लागत+यूटिलिटी लागत+ प्रत्यक्ष व्यय) की तुलना उपयुक्त है, क्योंकि यह निर्धारित लागतों पर विचार नहीं करती।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आवेदकों ने सुनवाई के एक दिन पूर्व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत सूचना परिचालित नहीं की। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकार, जिसमें आवेदक भी शामिल हैं, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रकट किया था, उन्हें जो कुछ मौखिक सुनवाई में प्रस्तुत किया था, उसे लिखित अनुरोधों के रूप में दाखिल करना अपेक्षित था। अन्य पक्षकारों के पास भी लिखित अनुरोधों के रूप में साझा की गई सूचना के लिए अपने प्रत्युत्तर (रिजवाइंडर) दायर करने का अवसर था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार के लिए कोई भी पूर्वधारणा नहीं थी, क्योंकि जो सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई थी, लेकिन प्राधिकारी को लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों के रूप में प्रदान नहीं की गई, उसे वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया गया है।
38. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है कि टिप्पणियां अथवा निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों को दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को पत्र भेजे गए थे, जिसमें विभिन्न अनुरोधों की समय सीमा को स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है, जिसमें पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिनांक का समय और अंतिम पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने तथा प्रकाशित करने पर प्रश्नावली को दायर करने के लिए आगे 15 दिनों का समय शामिल है।
39. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हेबेई चेंगसिन कं. लि. को छोड़कर, जिसने यह अनुरोध किया कि पीसीएन-वार विश्लेषण इस मामले में आवश्यक नहीं है, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में उपरोक्त अवसर का लाभ नहीं उठाया और निर्धारित समय के भीतर पीसीएन पर कोई टिप्पणियां नहीं दी। साइप्लस जीएमबीएच ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से लिक्विड रूप में विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने की मांग की।
40. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के दायरे के संबंध में एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया, जिसमें कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचित किया गया था कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा सोडियम सायनाइड है, चाहे इसका रूप कुछ भी हो। यह भी स्पष्ट किया गया था कि चूंकि पीसीएन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, अतः जांच के लिए कोई भी पीसीएन पद्धति अपनाई नहीं जा रही है और तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
41. वास्तव में, प्राधिकारी ने ऐमिनार फार्मा प्रा. लि. द्वारा किए गए अनुरोधों में असंगतता से संबंधित पद्धति और बदलते तर्कों को पाया है। ऐमिनार ने अपने दिनांक 13 मई, 2023 के ईमेल में, प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि पीसीएन निर्धारण इस मामले में संगत नहीं हो सकता। बाद में, मौखिक सुनवाई के बाद अनुरोध में उसने इसे बदल दिया, जिसमें पीयूसी/पीसीएन पर संप्रेषण के अभाव और एक पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर बल दिया, बावजूद इस तथ्य के कि प्राधिकारी ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 2023 के पत्र के तहत, स्पष्ट रूप से जांच के उत्पाद दायरे और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया। प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों में निरंतरता बना कर रखनी चाहिए।
42. प्राधिकारी उपरोक्त को देखते हुए, हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के साथ सहमत नहीं हैं कि उन्हें पीसीएन का सुझाव देने और प्रश्नावली उत्तर दायर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था।

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार (एडीए) में “देश” शब्द को न्यूनतम के प्रसंग में प्रयोग किया गया है (अनुच्छेद 5.8)। जबकि हितबद्ध पक्षकार “देश” और “परिक्षेत्र” को एडीए के भीतर अलग-अलग होने का सुझाव देते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी अंतर प्रमाणित नहीं है।
44. प्राधिकारी भी यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ और इसके सदस्य राष्ट्र, दोनों ही व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने अधिकारों में डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और शब्द ‘देश’ और ‘परिक्षेत्र’ डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के लिए एक दूसरे के लिए प्रयोग होता है। अतः यूरोपीय संघ चूंकि डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य है, संबद्ध जांच ‘संबद्ध देश’ के रूप में यूरोपीय संघ (ईयू) को आयातों के संबंध में शुरू की गई है न कि यूरोपीय संघ के भीतर अलग अलग देशों के खिलाफ है। यह कोई विवाद नहीं है कि प्राधिकारी यूरोपीय संघ के संबंध में जांच शुरू करने के लिए पात्र हैं। यूरोपीय संघ ने स्वयं ही इसके विपरीत तर्क नहीं दिया है। इस संबद्ध जांच में, चूंकि आयात संबद्ध देश के रूप में यूरोपीय संघ के मूल के हैं और न्यूनतम के स्तरों से अधिक हैं, अतः यूरोपीय संघ के भीतर अलग-अलग सदस्यों के खिलाफ मामला समाप्त होने के तर्क में कोई महत्व नहीं है।
45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच की अवधि का चयन आवेदकों द्वारा क्षति के लिए एक मामला बनाने के लिए छांट कर किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि हाल की होनी चाहिए, उद्योग की स्थिति की एक प्रतिनिधिक तस्वीर दर्शाने के लिए पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए। प्रवृत्तियों का उचित आकलन प्रदान करने के लिए एक 12 माह की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी मानी गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में जांच की अवधि (पीओआई) 12 माह की है, जो कि नियमों के अनुसार है। यह भी देखा गया है कि आवेदकों ने जांच की अवधि में और उससे पूर्व के वर्ष में हानियों का सामना किया है। किसी भी पक्षकार ने यह नहीं स्थापित किया है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई पाटन जांच की अवधि में नहीं हुआ है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह स्वीकार करना कठिन है कि जांच की अवधि का चयन एक मामला बनाने के लिए छंटनी करके किया गया है।
46. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में जांच की अवधि के बाद गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच एक मूल जांच में तब तक आवश्यक नहीं है, जब तक कि इसके लिए तथ्यात्मक परिस्थितियां आवश्यक नहीं हों। यह नोट किया जाता है कि पाटन और क्षति के संबंध में निष्कर्ष जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकते। केवल तभी जब उपरोक्त के संबंध में निर्णायक साक्ष्य जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के संबंध में नहीं हो सकते, तो जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए। तथापि, वर्तमान जांच में जांच की अवधि के तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान क्षति का सामना किया है और इसलिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।
47. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राइम कॉस्ट एक नई संकल्पना है, उनके द्वारा कुछ भी विपरीत प्रदान नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता हो कि ऐसी तुलना उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राइम कॉस्ट की संकल्पना में केवल उत्पादन की परिवर्तनीय लागत, अर्थात् कच्ची सामग्री की लागत, यूटिलिटी लागत, पैकिंग लागत और उपभोज्य को विचार में लिया गया है। प्राइम कॉस्ट एक नई संकल्पना नहीं है, बल्कि उत्पादन की कुल लागत का ही एक भाग है। प्राधिकारी को वर्ष के दौरान आयातों की कीमत प्रवृत्ति की जांच करनी अपेक्षित है। जब उत्पादन की वैश्विक लागत पूरी क्षति अवधि के दौरान स्थिर हो, तो एक साधारण आयात कीमत की जांच पर्याप्त होनी चाहिए। तथापि, यदि उत्पादन की लागत में उतार-चढ़ाव है, तो हाल के आयात की कीमतों से आगे एक विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है। चूंकि सभी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्वीकार किया है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और यह भी तर्क दिया गया है कि यूपीएल एक नया उत्पादक है और इसलिए इसकी अधिक निर्धारित लागत होगी, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राइम लागतों के साथ आयात कीमत की तुलना मामले के तथ्यात्मक मेट्रिक्स में एक उपयुक्त अवधारणा होगी। प्राधिकारी ने मासिक वैश्विक कच्ची सामग्री की कीमतों के साथ क्षति अवधि के दौरान आयात कीमत की भी तुलना की है।

48. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान वार्षिक आयात कीमतों की प्रवृत्ति की जांच की है। इसके अलावा, इसकी तुलना उत्पाद के उत्पादन, अर्थात् प्राइम कॉस्ट (कच्ची सामग्री लागत, यूटिलिटी लागत, पैकिंग लागत और उपभोज्य की लागत) के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी लागतों के साथ की गई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया था कि चूंकि यूपीएल एक नया उत्पादक है, अतः प्राइम कॉस्ट को केवल एचसीसी के लिए विचार में लिया जाना चाहिए ताकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विभिन्न संरचना के कारक विकृति से बचा जा सके। घरेलू उद्योग ने केवल एचसीसी के आंकड़ों के आधार पर प्राइम कॉस्ट की गणना की है, लेकिन प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण समग्र घरेलू उद्योग के लिए किए जाने की जरूरत है न कि घरेलू उद्योग के घटकों के आधार पर चुनिंदा तरीके से। तदनुसार, प्राधिकारी ने एचसीसी और यूपीएल दोनों की उचित तुलना के प्रयोजन के लिए पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की समग्र लागत के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए समेकित आंकड़ों पर विचार किया है।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. चीन जन.गण. के डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के प्रोटोकॉल के पैरा 15(क)(ii) में किए गए प्रावधान के अनुसार, घरेलू कीमतों या चीन के उत्पादकों की लागतों की बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों पर ध्यान न देने की 15 वर्षों की अवधि, पैरा 15(घ) के संदर्भ में दिनांक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है।
- ख. आवेदकों द्वारा वास्तविक सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए उचित साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं।
- ग. आवेदकों द्वारा की गई सामान्य मूल्य की गणना काल्पनिक है। यदि परिकल्पित सामान्य मूल्य इतना अधिक था, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि निर्यातकों ने इस कीमत पर बिक्री की होगी।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमतों के लिए समायोजन का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।
- ड. आवेदकों द्वारा निर्यातकों की घरेलू कीमतों और भारत के लिए निर्यात कीमत में आवेदकों द्वारा की गई तुलना सूचीबद्ध डेटा के आधार पर है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ड्रासलोवका ने भारतीय बाजार में उत्पाद के पाटन में शामिल नहीं किया है।
- च. सामान्य मूल्य का निर्धारण अधिक सक्षम घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। आवेदकों का यह दावा कि एचसीसी को सामान्य मूल्य के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता, भ्रामक है।
- छ. आवेदक उत्पादन का निर्यात उसी कीमत पर करते हैं, जिस पर उत्पाद को भारतीय बाजार में आयात किया गया है, यह दर्शाता है कि कोई पाटन नहीं है और आयात कीमत ही वास्तविक कीमत है।

च.2. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

50. आवेदकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ सदस्यों को चीन जन.गण. में घरेलू कीमतों अन्यथा लागतों पर केवल तभी विचार किए जाने की जरूरत है, यदि जांच अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकें कि बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत उस उत्पाद के निर्माता, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु का उत्पादन कर रहे उद्योग में मौजूद हैं, जिसे चीन के उत्पादकों ने वर्तमान मामले में नहीं दिखाया है।
- ख. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में वास्तविक बिक्री कीमत या लागत के कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

- ग. उत्पाद का संबद्ध देशों में अधिकांशतः उत्पादन किया जा रहा है और इन देशों से अन्य देशों को निर्यात की कीमतें भी पाटित कीमतों पर प्रतीत होती हैं।
- घ. संबद्ध देशों में उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद का पाटन नहीं कर रहे थे, जबकि मांग और आपूर्ति में अन्तर था। उत्पादकों ने यूपीएल द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के तत्काल बाद बाजार में अपने उत्पाद का पाटन करना शुरू कर दिया है।
- ङ. चूंकि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1, पैरा 7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अन्य मापदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में भुगतान की जाने वाली वास्तविक कीमत के आधार पर किया जाना है।
- च. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू कीमत, बिक्री की लागत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था देश में निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।
- छ. एक मात्र भाग लेने वाले चीन के उत्पादक हेबेई चेंगसिन कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दायर नहीं की है।
- ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल एचसीसी के उत्पादन की लागत के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी का संयंत्र पुराना होने के कारण मूल्यहास में है, उत्पादन की लागत में कम मूल्यहास लागत है, कोई ब्याज लागत नहीं है, और कंपनी के लिए प्राकृतिक गैस की खरीद कीमत बाजार कीमतों को नहीं दर्शाती है।
- झ. निप्पो सोडा लिमिटेड और सोजित कारपोरेशन लिमिटेड, जापान ने अपने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को वापस लेने के लिए एक पत्र दाखिल किया था। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि प्रतिकूल तथ्यों को लागू करें।
- ञ. वर्तमान जांच में कोरिया गणराज्य से कोई भी उत्तर नहीं है और कोरिया गणराज्य से पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे अविववादित हैं।
- ट. आवेदकों द्वारा वास्तविक सामान्य मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए आवेदक के अपने अगोपनीय पाठ के भाग के रूप में संबद्ध देशों में कच्ची सामग्री तथा प्राकृतिक गैस की कीमतों के संबंध में सूचना प्रदान की गई है।
- ठ. आवेदकों द्वारा आवेदन में समुद्री मालभाड़ा का साक्ष्य प्रदान किया गया है, जबकि अन्य समायोजनों को प्राधिकारी द्वारा मानक समायोजनों के अनुसार प्रदान किया गया है।
- ड. निर्यातक भारतीय बाजार में उत्पाद का चुनिन्दा पाटन कर रहे हैं। अगोपनीय उत्तर के अनुसार कीमतों की प्रकृति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने घरेलू बाजार और अन्य देशों में कीमतों में वृद्धि की है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं:

- क) हेबेई चेंगसिन कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.
- ख) लुकेबनी जावोदी द्रासलोवका ए.एस. कोलिन, यूरोपीय संघ
- ग) निप्पॉन सोडा कंपनी लिमिटेड एंड सोजिट्ज कारपोरेशन, जापान

च.3.1 संबद्ध देशों से भाग लेने वाले उत्पादकों का कीमत संबंधी पैटर्न

52. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान, भाग लेने वाले उत्पादकों की घरेलू बिक्री कीमतों और निर्यात कीमतों की जांच की है।

53. लुसेबनी जावोडी ड्रासलोवका, कोलिन, यूरोपीय संघ की घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019	2020	2021	जांच की अवधि
क	घरेलू					
1	बिक्री मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
2	बिक्री मूल्य	यूएसडॉ.'000	***	***	***	***
3	कीमत	यूएसडॉ./ मी.टन	***	***	***	***
4	कीमत	प्रवृत्ति	100	100	96	136
ख	निर्यात					
1	बिक्री मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
2	बिक्री मूल्य	यूएसडॉ.'000	***	***	***	***
3	कीमत	यूएसडॉ./ मी.टन	***	***	***	***
4	कीमत	प्रवृत्ति	100	103	87	99

54. उत्पादक द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से यह देखा गया है कि जबकि उसकी घरेलू बिक्री कीमत में उस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और अधिक महत्वपूर्ण जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत को निर्यात कीमत में गिरावट आई है।

55. पिछले कुछ वर्षों में मूल्य प्रवृत्ति की जांच से पता चलता है कि भारतीय बाजार के मामले में तेज कीमत में गिरावट चुनिंदा रूप से हुई है जब यूपीएल ने अपना संयंत्र स्थापित किया था और मांग और आपूर्ति के अंतर को पाट दिया गया था।

च.3.2 संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

56. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
- उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

- (ख) बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.3.3 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

च.3.3.क चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति

57. डब्ल्यू टी ओ में चीन को शामिल करने के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है : "जी ए टी टी -का अनुच्छेद 1994VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार"-के अनुच्छेद (VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

58. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं, लेकिन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के अन्तर्गत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में, बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/डेटा के माध्यम से नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।
59. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

7. "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8.(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा

परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

(4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकते हैं जिसे संगत मानदंडों, जिनमें उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

60. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले एक तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी भी तर्कसंगत आधार पर, वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा समान वस्तु के लिए भारत में भुगतान योग्य कीमत सहित, विधिवत समायोजन करके, यदि आवश्यक हो, एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है।
61. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की घरेलू कीमत, निर्मित मूल्य अथवा निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर एक उपयुक्त देश का चयन करना अपेक्षित है। चूंकि न तो आवेदकों ने और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जा सका। अतः चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा समान वस्तु के लिए भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों के लिए शामिल करने के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करके किया गया है।
62. इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.3.3.ख चीन जन.गण. के निर्यात कीमत

सहयोगी उत्पादक - हेबेई चेंगसिन कं. लि. के लिए निर्यात कीमत

63. उत्पादक ने भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के रूप में ***मी.टन की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि उसने भारत के लिए उत्पाद का प्रत्यक्ष निर्यात किया है और कोई भी अन्य संगत/असंगत पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और स्वदेशी यातायात के संबंध में समायोजन का दावा किया है।
64. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

65. चीन जन.गण. से असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

च.3.4 यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

66. साइप्लस जीएमबीएच और जुसेनी जावोडी द्रासलोवका, कोलिन ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण किया है। तथापि, साइप्लस जीएमबीच ने एक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया था और उसे असहयोगी के रूप में माना गया है।

च.3.4.क यूरोपियन संघ के लिए सामान्य मूल्य

सहयोगी उत्पादक—लुसेबनी जावोडी द्रासलोवका ए.एस. कोलिन के लिए सामान्य मूल्य

67. उत्पादक ने जांच की अवधि में ***मी.टन की घरेलू बिक्रियों की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्रियां असंगत पक्षकारों के लिए हैं। उत्पादक ने स्वदेशी परिवहन और ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दी गई है।

असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

68. यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

च.3.4.ख यूरोपियन संघ के लिए निर्यात कीमत

सहयोगी उत्पादक—लुसेबनी जावोडी द्रासलोवका ए.एस. कोलिन के लिए निर्यात कीमत

69. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के रूप में *** मी.टन की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि उसने भारत को उत्पाद का प्रत्यक्ष निर्यात किया है और कोई भी अन्य संगत/असंगत पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण लागत, कमीशन और स्वदेशी परिवहन के संबंध में समायोजन का दावा किया है।

70. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

71. यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित की गई है।

च.3.5. जापान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

72. निप्पॉन सोडा कं. लिमिटेड ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। तथापि, मौखिक सुनवाई के अनुसरण में प्रतिवादी ने अपने प्रश्नावली उत्तर को वापस लेने के लिए एक पत्र दायर किया। दिनांक 15 दिसंबर, 2023 के पत्र के अंश इस प्रकार हैं:

- i. हम प्राधिकारी को यह अवगत कराने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं कि निप्पॉन सोडा कं. लि. संबद्ध पाटनरोधी जांच से अपनी सहभागिता वापस ले रहे हैं।

- ii. निप्पॉन सोडा कं. लि. के प्रबंधन ने अब यह निर्णय लिया है कि वह इस पाटनरोधी जांच से अपनी सहभागिता को वापस लेंगे, क्योंकि निप्पॉन सोडा कं. लि. के लिए तेजी से बदल रहे कारोबारी वातावरण के चले अप्रैल 2024 से भारत के लिए सोडियम सायनाइड का निर्यात करना संभव नहीं रहेगा।

73. तदनुसार, उत्पादक को असहयोगी माना गया है। अतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए डेटा के आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि जापान से कोई भी प्रतिभागी उत्पादक नहीं है।

च.3.5.क जापान के लिए सामान्य मूल्य

74. जापान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

च.3.5.ख जापान के लिए निर्यात कीमत

75. जापान के लिए निवल निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। निवल निर्यात कीमत की गणना सीमा शुल्क डेटा से की गई है। चूंकि सूचित डेटा सीआईएफ स्तर पर हैं, अतः समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.6 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

76. टीकवांग इंडस्ट्रियल कं. लि., कोरिया गणराज्य ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में दर्ज किया था। तथापि, उत्पादक ने एक प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया। अतः उत्पादक को एक असहयोगी माना गया है। यह नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से कोई भी प्रतिभागी उत्पादक नहीं है।

च.3.6.क कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

77. कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

च.3.6.ख कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

78. कोरिया गणराज्य के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। निवल निर्यात कीमत की गणना सीमा शुल्क डेटा से की गई है। चूंकि सूचित डेटा सीआईएफ स्तर पर हैं, अतः समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.7 पाटन मार्जिन

79. उपरोक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्रतिभागी और गैर-प्रतिभागी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य यूएसडा./मी.टन	निवल निर्यात कीमत यूएसडा./मी.टन	पाटन मार्जिन यूएसडा./मी.टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
1	चीन जन.गण.					
क	हेबेई चेंगसिन कं. लिमिटेड	***	***	***	***	40-50

ख	कोई अन्य	***	***	***	***	70-80
2	यूरोपीय संघ					
क	लुसेबनी जावोदी ड्रासलोवका ए.एस. कोलिन	***	***	***	***	100-110
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	120-130
3	जापान					
क	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
4	कोरिया गणराज्य					
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30

80. प्राधिकारी नोट करता है कि प्रकटीकरण विवरण में निर्माता लुकेबनी ज़ावाँडी ड्रासलोवका ए.एस. की 'डंपिंग मार्जिन रेंज' का उल्लेख करने में अनजाने में टाइपोग्राफिकल त्रुटि हुई। कोलिन के साथ-साथ यूरोपीय संघ से 'कोई अन्य निर्माता' भी। इन अंतिम निष्कर्षों में पाटन मार्जिन रेंज को अब उपरोक्त तालिका में सही कर दिया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

81. घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- ख. “अनावश्यक आयातों” के विश्लेषण में अधिनियम या पाटनरोधी नियमावली में कोई आधार नहीं है। आयातों में वृद्धि की, भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में उद्देश्यपरक जांच होनी चाहिए।
- ग. यूरोपीय संघ से आयात क्षति का कोई कारण नहीं हो सकते। यूरोपीय संघ से आयातों में अन्य देशों की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट आई है।
- घ. यूरोपीय संघ से आयातों का अन्य देशों से आयातों के साथ संचित आकलन न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यूरोपीय संघ की कीमतें चीन की कीमतों से 10% अधिक, औसत कीमत से 6% अधिक और अन्य देशों से आयात कीमतें 13% अधिक हैं। कीमत कटौती यूरोपीय संघ के लिए नकारात्मक है।
- ड. जापान से आयात प्रतिकूल कीमत प्रभाव का एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि चीन से आयात अधिक मात्रा में थे, जबकि जापान से आयात बाजार अंश का केवल 10% थे।
- च. कीमत कटौती में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। वर्ष 2021-22 में हानियां संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकती, जब आयातों की मात्रा में काफी कमी आई।
- छ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 537% तक की वृद्धि हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग ने बिक्रियों की लागत में वृद्धि होने के लिए कारण स्पष्ट नहीं किए हैं। लागत में परिवर्तन होने का कारण कच्ची सामग्री की कीमतों और क्षमता वृद्धि में अस्थायी वृद्धि होना है।
- झ. यूपीएल संबद्ध देशों से आयात की जा रही वस्तुओं की कीमत से कम कीमतों पर दिसंबर, 2021 से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

- ज. चूंकि यूपीएल ने एक नया संयंत्र स्थापित किया है, अतः प्राधिकारी को इसके लिए एक पृथक क्षति विश्लेषण करना और अनुमान के साथ अपनी वास्तविक सूचना की तुलना करनी चाहिए।
- ट. यूपीएल की वास्तविक क्षमता का उपयोग एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यूपीएल एक नया उत्पादक है।
- ठ. जांच की अवधि के दौरान तिमाही उपयोग को कच्ची सामग्री की लागत और एनआईपी के निर्धारण के लिए यूटिलिटी की लागत के लिए अपनाना चाहिए।
- ड. क्षति मापदंडों पर स्टार्ट अपन प्रचालनों और यूपीएल की अक्षमता के कारण प्रभाव पड़ा है।
- ढ. क्षमता में बिना सोचे वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। उत्पादन क्षमता भारत में संबद्ध माल की मांग से काफी अधिक है।
- ण. आवेदकों ने कैप्टिव खपत को भी शामिल करने के बाद क्षति निर्धारण पर विचार करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी को ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए, जो पाटनरोधी नियमावली के तहत अनुमत है और जिसका लगातार अनुसरण किया जा रहा है।
- त. एनआईपी के लिए शामिल पूंजी पर 22% से अधिक प्रतिफल के लिए घरेलू उद्योग का अनुरोध अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि 22% पहले से ही अधिक है और इसे एक मानक के रूप में निर्धारित किया गया था, जब ब्याज दरें काफी अधिक थीं।
- थ. घरेलू उद्योग ने पहले ही मांग का बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आयातों में भारी कमी आई है।
- द. घरेलू उद्योग का अंत स्टॉक जांच की अवधि में उसके तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में 62% तक कम हुआ है।
- ध. स्टॉक में वृद्धि होने का कारण (क) एचसीसी के उत्पादन में नियामक कारणों से रोक, (ख) यूपीएल एक नया संयंत्र स्थापित कर रहा है और (ग) एचसीसी द्वारा भारी मात्रा में आयात होना है।
- न. घरेलू उद्योग ने क्षति की एक तस्वीर तैयार करने के लिए, जहां कुछ भी मौजूद नहीं था, जांच की अवधि को छांट कर चुना है। इस अवधि के दौरान, अमोनिया और कास्टिक सोडा लाई की कीमतों में अस्थायी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण आयात कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई थी।
- प. एचसीसी के संयंत्र का बंद होना और कोविड-19 लॉकडाउन वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान हुए थे, और इससे कारोबार, बिक्रियों और लाभों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- फ. यूपीएल संयंत्र का बंद होना भी पाटित आयातों के कारण से नहीं था, क्योंकि आयातों में गिरावट आई थी, जब यूपीएल ने पहले अपना उत्पादन शुरू किया था।
- ब. क्षति होने का कारण उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत हो सकता है।
- भ. आयातों के लिए मांग कीमतों, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति आदि सहित विभिन्न अन्य कारकों से मार्गदर्शित है।
- म. यूरोपीय संघ से आयात कीमत चीन की कीमतों से 10% अधिक और औसत कीमत से 6% अधिक हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से आयात कीमतें पूरी जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही हैं।
- य. यूरोपीय संघ के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।
- कक. आवेदकों के बाजार अंश में 550% तक की वृद्धि हुई है और आयात अंश में मात्र 9% की गिरावट आई है और अभी आवेदकों ने इन आयातों के कारण क्षति का दावा किया है।

- खख. आवेदकों की क्षमता में केवल एक वर्ष में 637% तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में 496% और 431% तक की वृद्धि हुई है। आवेदकों को एक वर्ष के भीतर क्षमता का पूर्ण उपयोग होने की आशा है। प्राधिकारी ने इस जांच को एक ऐसे व्यर्थ तक/दावे के आधार पर शुरू किया है।
- गग. अस्थायी स्टॉक होना भी एचसीसी द्वारा भारी मात्रा में आयात के कारण हैं। कंपनी का क्षमता उपयोग और बाजार अंश 90% के आस-पास था।
- घघ. यूपीएल के स्टार्ट अप प्रचालनों और आवेदकों की अक्षमता के कारण क्षति मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ड.ड. जैसा कि अनुच्छेद 3.5 के तहत अपेक्षित है, एक पर्याप्त “गैर-आरोपण” विश्लेषण को पूरा करने में, जांच प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अन्य ज्ञात कारकों के कारण क्षति पाटित आयातों का गलत आरोपण नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्हें “पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों को उन अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों से अलग और पहचान” करना चाहिए।
- चच. निर्यात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत की तुलना अनुपयुक्त है, क्योंकि दावा सूचीबद्ध संख्याओं पर आधारित है। भारत को निर्यात कीमत आधार वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री कीमत से अधिक है।
- छछ. कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि असामान्य और अस्थायी प्रकृति की रही है। कच्ची सामग्री की कीमतें जांच की अवधि के बाद सामान्य होनी शुरू हो गई हैं।
- जज. कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण थी। डेल्टा में गिरावट कई कारणों के कारण से है, जो पाटन का कारण नहीं है।
- झझ. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उत्पादन पर गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना करने का दावा और घरेलू वस्तुओं की बिक्री पर नहीं, आधारहीन है, क्योंकि शुल्क का संरक्षण घरेलू बिक्रियों के लिए उपलब्ध है न कि कैप्टिव खपत के लिए। एनआईपी की गणना करते समय, एचसीसी को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू बिक्रियों में इसका अंश यूपीएल की तुलना में महत्वपूर्ण है।
- ञञ. डेल्टा में गिरावट के लिए कारण कच्ची सामग्री की कीमतों का हर समय अधिक रहना था न कि संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा पाटन किया जाना था।
- टट. मांग और आपूर्ति अन्तर के कारण आयात आवश्यक थे। यूपीएल के संयंत्र के बंद होने पर विचार करते हुए, कम से कम 35% की मांग और आपूर्ति अंतर था।
- ठठ. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि डेल्टा में इस तथ्य के कारण गिरावट आई है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में जांच की अवधि में वैश्विक वृद्धि हुई है। कच्ची सामग्री की कीमतों में पुनः जांच की अवधि के बाद गिरावट आई है।
- डड. आवेदकों द्वारा विगत जितने लाभ पर आधारित कीमत कटौती की गणना करने के लिए प्रस्तावित पद्धति गलत है, क्योंकि कीमत संबंधी सूचना पर लेखांकन रिकॉर्ड के आधार पर विचार किए जाने की जरूरत है।
- ढढ. यूपीएल के संयंत्र में अवरोध आया क्योंकि उन्होंने चीन जन.गण. से ग्लास रिएक्टरों के साथ पुराना संयंत्र आयात किया है। इसने कुछ ग्लास लाइन रिएक्टरों का स्थान लिया है, लेकिन अभी भी पुरानी अक्षम मशीनों के साथ संघर्षरत है।

छ.2 आवेदकों की ओर से किए गए अनुरोध

82. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयातों का एक संचित आकलन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(iii) की अपेक्षा पूरी हो गई है।

- ख. संबद्ध देशों से आयातों में 2019-20 में एचसीसी का संयंत्र प्रचालनरत होने और यूपीएल द्वारा 2021-22 में उत्पादन शुरू किए जाने के साथ गिरावट आई है, जिससे मांग आपूर्ति अंतर समाप्त हो गया था।
- ग. यदि आयात मांग और आपूर्ति अंतर समाप्त होने के कारण आवश्यक है तो संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।
- घ. संबद्ध देशों से निर्यातकों ने अपनी निर्यात कीमतों में वृद्धि प्राइम कॉस्ट में वृद्धि के अनुसार नहीं की है, जिसके कारण काफी पाटन हुआ है।
- ङ. जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम है, जिसके कारण सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है, जबकि कंपनी नुकसान पर उत्पाद की बिक्री कर रही है।
- च. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि कीमत कटौती में गिरावट आई है, कीमत कटौती में गिरावट यह दर्शाती है कि घरेलू और आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कीमत कटौती में गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग नुकसान पर बिक्री कर रहा है। यदि घरेलू उद्योग ने लाभों को नहीं छोड़ा होता, तो कीमत कटौती और अधिक होती।
- छ. आयातों पर जांच की अवधि में आवेदकों की कीमतों और जांच की अवधि के दौरान कीमत ह्रास पर एक ह्रासकारी प्रभाव है।
- ज. जबकि भारत में क्षमता वर्ष 2021-22 और जांच की अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उत्पादन में वृद्धि संबद्ध देशों से पाटन के कारण उसी अवधि में मांग आपूर्ति अंतर से काफी कम थी।
- झ. वर्ष 2021-22 और जांच की अवधि में लाभप्रदता में काफी गिरावट आई थी।
- ञ. आवेदक वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे हैं और जांच की प्रस्तावित अवधि में नियोजित पूंजी पर एक नकारात्मक प्रतिफल है।
- ट. आवेदकों के नकदी लाभ में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है।
- ठ. आवेदकों का बाजार अंश, जिस स्तर पर यह पूर्ति कर सकता है, उस स्तर से नीचे है।
- ड. आवेदक के पास वस्तु सूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। वस्तु सूची में कुछ हद तक जांच की अवधि के दौरान गिरावट वस्तु सूचियों को रोकने के लिए उत्पाद को रोकने के परिणामस्वरूप है।
- ढ. यहां तक कि उत्पादन की सामान्य लागत पर भी आवेदकों को हानियां, नकदी हानियां और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल हो रहा है।
- ण. यदि प्राइम कॉस्ट में परिवर्तन पर विचार किया जाता है, तो आयात कीमत, जिस कीमत पर यह होनी चाहिए उस कीमत से कम से कम 20% है।
- त. आवेदकों ने महत्वपूर्ण नकारात्मक और प्रतिकूल विकास को दर्ज किया है।
- थ. जबकि यूपीएल ने हाल ही में उत्पाद में 500 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है, कोई भी उत्पादक वर्तमान निष्पादन पर विचार करते हुए अपने कारोबार में निवेश नहीं करना चाहेगा।
- द. घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण से नहीं है, लेकिन इसकी बजाय संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण है।
- ध. मांग में गिरावट क्षति के कारण नहीं है, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

- न. ऐसी स्थिति में, जहां देश में मांग घरेलू उद्योग की क्षमता की केवल 85% थी, संबद्ध देशों से आयातों में भारतीय मांग में 39% हिस्सा है। आयातों से उत्पादन क्षमताओं का उपयोग रुक रहा था और इसके कारण भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव हो रहा था।
- प. जबकि भारत में आयात कीमत और कच्ची सामग्री की कीमतों के बीच डेल्टा यूपीएल द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व 1600 यूएसडॉलर/मी.टन से अधिक था, उत्पादन शुरू होने के बाद डेल्टा में तीव्र गिरावट आई है। जांच की अवधि के अंत में डेल्टा केवल 300 यूएस डॉलर/मी.टन था।
- फ. जांच की अवधि में 34,000 रु. प्रति मी.टन से अधिक की प्राइम कॉस्ट में तीव्र वृद्धि देखी गई, लेकिन आयात कीमत में वृद्धि केवल 8000 रु. प्रति मी.टन थी।
- ब. यदि घरेलू उद्योग ने प्रति यूनिट वही लाभ रखा होता, जैसा कि आधार वर्ष में अर्जित किया जा रहा था तो कीमत कटौती में जांच की अवधि में 54% के स्तर तक वृद्धि होती।
- भ. जहां तक एमेनार फार्मा प्रा. लि. का विभिन्न अन्य कारकों द्वारा निर्देशित किए जा रहे आयातों के लिए मांग के संबंध में अनुरोध का संबंध है, एमेनार फार्मा प्रा. लि. ने वर्ष 2021-22 और जांच की अवधि में यूपीएल से इसकी आंशिक मांग प्राप्त करना शुरू कर दिया है। अतः इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- म. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता बेहतर है, क्योंकि यूपीएल की प्रौद्योगिकी निर्यातकों से श्रेष्ठ है।
- य. घरेलू उद्योग का अग्रणी समय निर्यातकों से कमतर है।
- कक. बिक्रियों के प्रतिशत के रूप में वस्तुसूची में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। बिक्रियों के % के रूप में वस्तुसूची में केवल जांच की अवधि में गिरावट आई है, क्योंकि यूपीएल ने बढ़ती वस्तुसूचियों में सुविधा के लिए जांच की अवधि में कुछ समय के लिए उत्पादन को रोकने का निर्णय लिया था।
- खख. जहां तक यूपीएल द्वारा जिस कीमत पर उत्पाद का आयात किया गया है, उस कीमतों पर की गई निर्यात बिक्रियों के संबंध में तर्क का संबंध है, यूपीएल पाटित आयातों के चले भारतीय बाजार में उसकी बिक्री में कठिनाई के कारण दिसंबर, 2021 से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए मजबूर हुआ है। यूपीएल निर्यातों में भी इस समस्या का सामना कर रहा है।
- गग. जहां तक क्षति के कारण उच्च वित्त लागतों का संबंध है, उत्पादन की लागत में प्रभारित ब्याज लागत एचसीसी के मामले में शून्य है और यूपीएल के मामले में 0.1% से कम है।
- घघ. जहां तक क्षति के कारण मूल्यहास का संबंध है, उत्पादन की लागत मूल्यहास लागत के रूप में अपर्याप्त है। घरेलू उद्योग उत्पादन की सामान्य लागत पर भी समस्या का सामना कर रहा है।
- ड.ड. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग मौजूद समस्याओं का सामना कर रहा है, घरेलू उद्योग को लाभ हो गया होता, यदि निर्यातकों ने प्राइम कॉस्ट में परिवर्तन के साथ उसके अनुसार अपनी कीमतों का समायोजन किया होता।
- चच. जबकि क्षति विश्लेषण समग्र घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक है, और किसी एक प्रतिभागी उत्पादक के लिए चुनिन्दा नहीं है, अतः घरेलू उद्योग को व्यक्तिगत प्रदर्शन का एक विश्लेषण यह दर्शाएगा कि दोनों ही उत्पादक क्षति का सामना कर रहे हैं।
- छछ. एचसीसी 20 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन कर रहा है और संयंत्र का काफी मूल्यहास हुआ है। 22% का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एनआईपी की गणना के लिए तर्कसंगत नहीं होगा। 22% में एक लाभ शामिल

होगा, जो किसी भी भावी ब्याज लागत, नए निवेश और करों के लिए अपर्याप्त होगा। प्राधिकारी गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में विगत के लाभों पर विचार कर सकते हैं।

जज. यदि एचसीसी ने बाजार कीमतों पर प्राकृतिक गैस की खरीद की होती, तो उसे नुकसान हो गया होता।

झझ. यूपीएल लिमिटेड ने क्षति अवधि में 90% का एक क्षमता उपयोग हासिल किया है और प्राधिकारी इसकी गैर क्षतिकारी कीमत की गणना के लिए इस पर विचार कर सकते हैं। यूपीएल के लिए, नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिफल एनआईपी की गणना के लिए विचार में लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक नया संयंत्र है और इसमें पाटन से पूर्ण सुरक्षा अपेक्षित होती है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

83. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि एक क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत देते हैं, “..... पाटित आयातों, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसे आयातों के ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....” कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों द्वारा एक पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा एक पर्याप्त मात्रा में कीमतों को गिरने अथवा कीमत में वृद्धिको रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती।

84. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान क्षति और कारणात्मक संबंध और प्राधिकारी द्वारा संगत पाई गई क्षति के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और संगत मापदंडों के तहत इस प्रकार समाधान किया गया है।

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड गिरावट को दर्शाएं। कुछ मापदंड गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य मापदंड नहीं दिखा सकते। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है अथवा पाटन के कारण क्षति का सामना करने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।

आयातों का संचित आकलन

86. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के तहत यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के कारण एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे, यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है, और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है, अन्यथा जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो आयात साझा रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक होगा; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचित आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन आयात पाटित कीमतों पर हैं।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

ग. इन देशों से आयातों की मात्रा पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

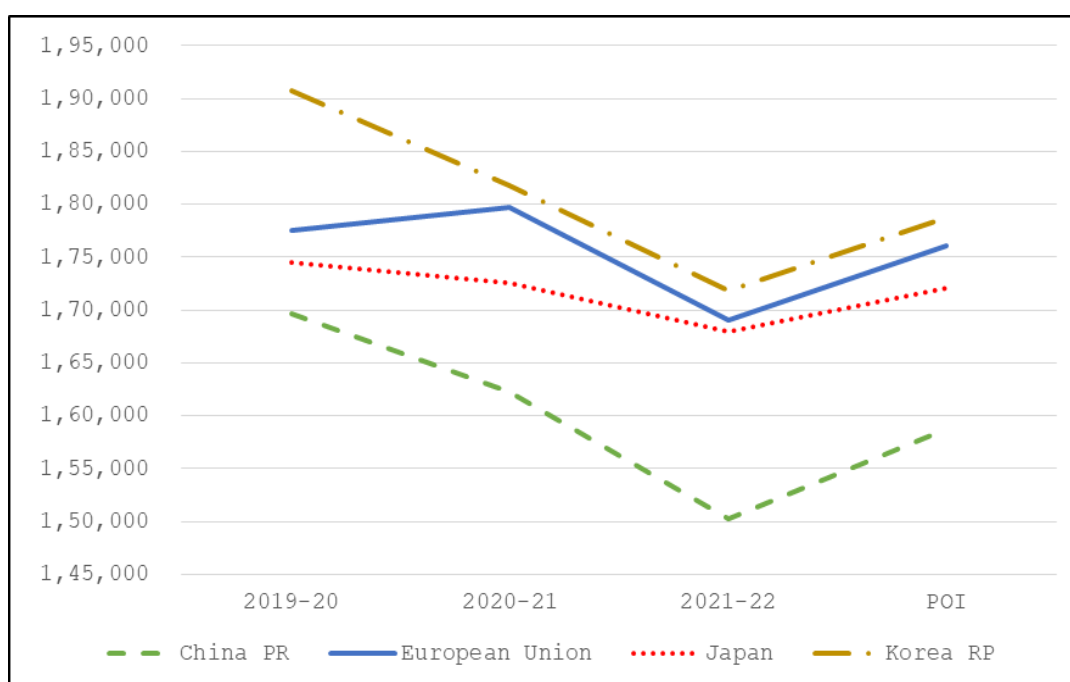
88. यह पता लगाने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव का संचित आकलन आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त है, निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है:-

- क. विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद समान वस्तुएं हैं और गुणों में तुलनीय हैं।
- ख. घरेलू तौर पर उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद परस्पर बदले जा सकते हैं। घरेलू सामग्री तथा आयातित सामग्री को उपभोक्ता एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तथा निर्यातक और घरेलू उद्योग ने उस उत्पाद को उन्हीं ग्राहकों को बेचा है।
- ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है।
- घ. संबद्ध देशों से आयात कीमत एक दूसरे के साथ मिलकर परिवर्तित हुई है।

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रदान किया है कि घरेलू उत्पादक और संबद्ध देशों से निर्यातक समान उत्पाद को समान ग्राहकों को बेचते हैं और दोनों ही समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों उत्पादों को ग्राहकों द्वारा बदल बदल पर प्रयोग में लाया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम डेटा से भी इसका पता लगाया गया है।

90. नीचे दी गई तालिका और ग्राफ में संबद्ध देशों से आयात कीमत दर्शाई गई है।

क्र.सं.	देश का नाम	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
1	चीन जन.गण.	रु./मी.टन	1,69,695	1,62,204	1,50,208	1,58,735
2	यूरोपियन संघ	रु./मी.टन	1,77,584	1,79,751	1,69,072	1,76,036
3	जापान	रु./मी.टन	1,74,554	1,72,545	1,67,900	1,72,113
4	कोरिया गणराज्य	रु./मी.टन	1,90,699	1,81,723	1,71,896	1,78,771



91. आधार वर्ष में कीमतों के साथ जांच की अवधि में आयात की कीमतों की तुलना से यह पता चलता है कि सभी संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है। इसी प्रकार, जब जांच की अवधि में कीमतों की तुलना तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की कीमतों के साथ की जाती है, तो सभी संबद्ध देशों से आयात मूल्यों में वृद्धि देखने में आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमतों में मासिक परिवर्तनों के कारण औसतन वार्षिक आयात मूल्य अनिवार्य रूप से समान स्तर पर नहीं हो सकते, यद्यपि आयात की कीमतों की समग्र प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि वे मिलकर परिवर्तित हुए हैं।
92. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन करना उचित समझते हैं।

यूरोपीय संघ और जापान से आयातों का पृथक आकलन

93. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि यूरोपीय संघ और जापान से आयात में गिरावट आई है और वे क्षति का कारण नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II के पैरा (iii) में प्रदान की गई संचय की सभी शर्तें वर्तमान मामले में पूरी हैं। यह भी देखने में आया है कि प्रत्येक संबंधित देश से आयात मूल्यों में गिरावट देखने में आई है। यह भी देखा गया है कि यूरोपीय संघ और जापान से औसतन आयात मूल्य कोरिया से कम था। प्राधिकारी ने सौदा-वार आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि आयातक इन स्रोतों से बदल बदल कर आयात कर रहे हैं। अतः इस तर्क में कोई महत्व नहीं है कि यूरोपीय संघ और जापान से आयातों को अलग किया जाना चाहिए और उनका अलग अलग आकलन किया जाना चाहिए।

गैर क्षतिकारी कीमत की गणना

94. घरेलू उद्योग ने एचसीसी के लिए गैर क्षतिकारी मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए लाभ पर विचार करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संयंत्र की तिमाही उपयोग के आधार पर यूपीएल के गैर-क्षतिकारी मूल्य के निर्धारण का अनुरोध किया है। तथापि, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III और प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही सतत पद्धति के आधार पर गैर-क्षतिकारी मूल्य निर्धारित किया है। प्राधिकारी ने अपने एनआईपी के निर्धारण के लिए एचसीसी द्वारा अर्जित किए गए निवेश पर विगत के प्रतिफल पर विचार करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

यूपीएल और एचसीसी के लिए पृथक क्षति विश्लेषण

95. हितबद्ध पक्षकारों ने यूपीएल और एचसीसी के लिए एक पृथक क्षति विश्लेषण करने का अनुरोध किया था, यह देखते हुए कि यूपीएल ने एक नई यूनिट स्थापित की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों संस्थाओं के लिए अलग अलग क्षति का विश्लेषण करने का अनुरोध कानून और नियमों के विपरीत होगा, क्योंकि आवश्यक समग्र घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक के चुनिंदा रूप हैं। उपरोक्त के बावजूद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों कंपनियों को संचयी और अलग अलग रूप से प्रदर्शन में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

मानक आधार पर यूपीएल का प्रदर्शन

96. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि यूपीएल एक नया उत्पादक है, अतः क्षति की जांच मापदंड के आधार पर भी की जानी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। मापदंडों के साथ तुलना उन मामलों के लिए आवश्यक है, जहां पर घरेलू उद्योग में पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन नहीं होता है। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या पाटित किए गए आयात घरेलू उद्योग को कोई महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा रहे हैं। अतः अनुमानों के साथ तुलना उचित नहीं होगी।
97. तथापि, किए गए अनुरोधों को देखते हुए प्राधिकारी ने उत्पादन की मानक लागत# पर घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया है (क्षति की अवधि में यूपीएल के उच्चतम क्षमता उपयोग पर विचार करके), ताकि यह देखा जा सके कि क्या क्षति को स्टार्ट अप के प्रचालन या कम क्षमता उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। नीचे दी गई तालिका में ईष्टम स्तर पर क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को दर्शाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
1	बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	88	76	81
2	उत्पादन की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	76	106	131
3	प्रति यूनिट लाभ	रु./मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	110	21	-12
4	लाभ लाख रु. में	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	237	84	-53
5	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	237	84	-52
6	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	216	103	-9
7	आरओसी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	84	7	-7

जैसा कि आवेदकों द्वारा प्रदान किया गया है

98. उत्पादन की मानक लागत पर घरेलू उद्योग के प्रदर्शन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग जब तक कि मानक लागतों पर भी नुकसान का सामना करेगा।

आयात कीमतों के अनुसार यूपीएल की निर्यात कीमत

99. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि यूपीएल उसी कीमतों पर निर्यात कर रहा है, जिन कीमतों पर आयात किया जा रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि निर्यात पूरी तरह से अनावश्यक हैं और वस्तु सूची का विशुद्ध निपटान करने के लिए है जैसे यूपीएल घरेलू बाजार में लाभकारी कीमतों पर बिक्री करने में असमर्थ था। यह देखा गया है कि निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में बेची गई कीमत से काफी कम कीमत पर है। यह अपने आप ही घरेलू उद्योग के दावे को प्रमाणित करता है कि बिक्रियां वस्तु सूची को निपटाने के लिए की गई थी। यह तथ्य कि उत्पादक काफी कम और अलाभकारी कीमतों पर निर्यात करने के लिए मजबूर था, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाता है।

यूपीएल संयंत्र के साथ समस्याएं

100. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि यूपीएल ने एक पुराना संयंत्र खरीदा और संयंत्र की समस्याओं के कारण नियमित बंदी रही। यूपीएल के परिसर में भौतिक सत्यापन के दौरान इस समस्या की जांच की गई थी। यूपीएल द्वारा स्थल सत्यापन के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि कंपनी द्वारा एक नया संयंत्र स्थापित किया गया था। यूपीएल द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संयंत्र को बंद करने का कारण केवल निष्क्रिय वस्तु-सूची थी न कि संयंत्र में किसी अन्य समस्या के कारण।

छ.3.1 मांग का आकलन

101. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया है। इसके अलावा, मांग को दो बार निर्धारित किया गया है – एक बार घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत को निकाल कर और उसके बाद शामिल करके।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	216	396	431
2	संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	14,189	12,544	8,586	6,272
3	अन्य देशों से आयात	मी.टन	1,776	421	180	180
4	मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	98	97	89
5	कैप्टिव खपत*	मी.टन	***	***	***	***
6	मांग (कैप्टिव सहित)	मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	98	117	111

102. कोविड फैलने के कारण वर्ष 2020-21 में भारत में कुल मांग/ खपत में गिरावट आई किन्तु उसके बाद वर्ष 2021-22 में इसमें वृद्धि हुई। जांच की अवधि में मांग में दुबारा मामूली गिरावट आई।

छ. 3.2. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

103. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की यह निश्चय करने के लिए जांच की गई है कि क्या भारत में या तो कुल रूप में या उत्पादन अथवा खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।

104. कुल रूप में और उत्पादन तथा खपत के संबंध में विभिन्न देशों से आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:

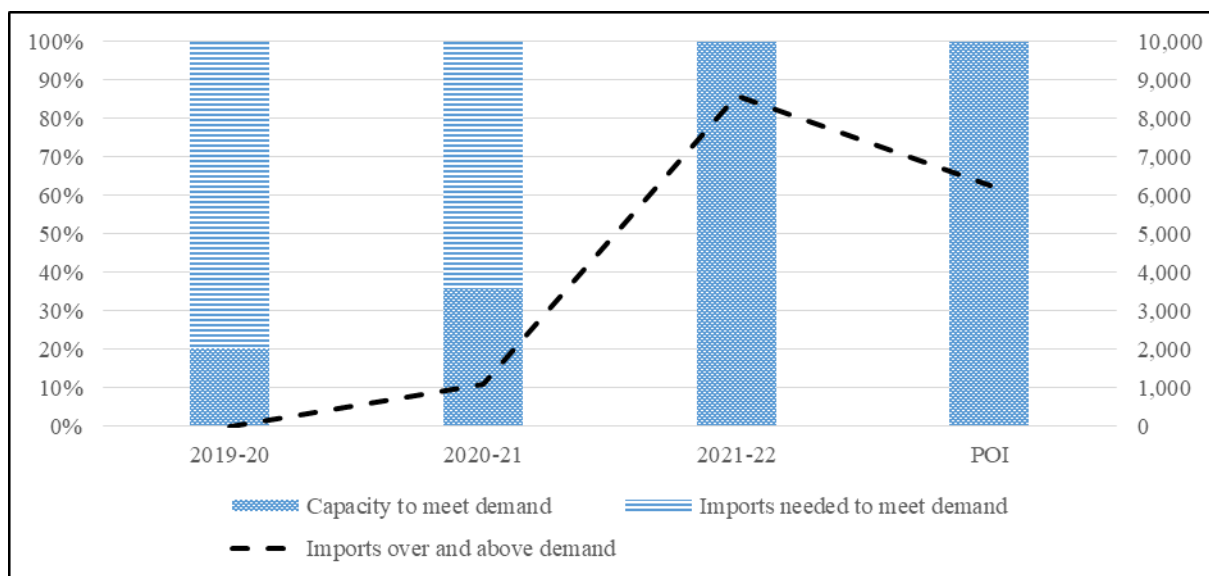
क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	मी टन	14,189	12,544	8,586	6,272
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात: -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	36	11	9
ख	मांग (कैप्टिव सहित)	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	90	52	40
ग	कुल आयात	%	89%	97%	98%	97%

105. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान कुल रूप में और उत्पादन व खपत के संबंध में गिरावट आई है।

106. प्राधिकारी ने भारतीय उद्योग द्वारा उत्पाद और आपूर्ति के लिए मांग के संबंध में आयात में गिरावट की स्थिति की जांच की है। नीचे दी गई सारणी क्षति अवधि में आयातों, और भारतीय उद्योग की क्षमता और देश में मांग को दर्शाती है-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	भारत में मांग	मी. टन	***	***	***	***
2	घरेलू उद्योग की क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
3	मांग और आपूर्ति में अंतर	मी. टन	***	***	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं
4	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	14,189	12,544	8,586	6,272

5	मांग- आपूर्ति अंतर से अधिक आयात	मी. टन	***	***	8,586	6,272
---	---------------------------------	--------	-----	-----	-------	-------



107. यह देखा गया है कि देश में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में एक बड़ा मांग और आपूर्ति अंतर था और इसलिए उपभोक्ताओं के पास आयात के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। तथापि, वर्ष 2021-22 में यूपीएल द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ ही, बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर पूरा हो गया था। वास्तव में, भारतीय उद्योग की स्थापित क्षमता अब देश में उत्पाद की मांग की तुलना में अधिक है। इसलिए, जहां विगत में देश में उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए आयात जरूरी थे, वहीं अब संबद्ध देशों से आयात भारत में क्षमताओं की प्रतिस्पर्धा में है। यह भी देखा गया है कि यूपीएल ने अपने बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए हानि पर बिक्री की है।

छ. 3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

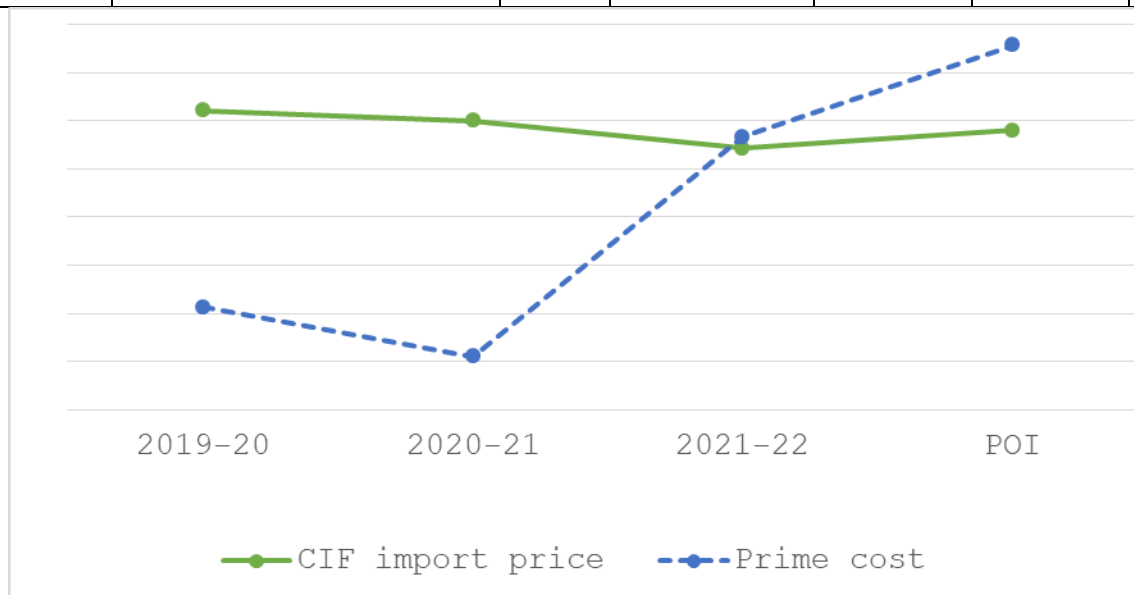
108. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से उत्पाद की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच, व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटा कर तुलना की गई है।

क. कीमतों का विकास

109. प्राधिकारी ने आयात कीमतों की प्रवृत्ति की पीयूसी के उत्पादन से सीधे रूप से संबद्ध लागतों के साथ आयात कीमतों की प्रवृत्ति की तुलना की है अर्थात् प्रधान लागत (कच्चे माल की लागत, यूटिलिटी लागत, पैकिंग लागत और उपभोज्य की लागत)। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया था कि चूंकि यूपीएल एक नया उत्पादक है, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के विभिन्न संरचनाओं के कारण विरूपण से बचने के लिए, अकेले एचसीसी के लिए प्रधान लागत पर विचार किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति विश्लेषण को समग्र रूप से किरूप से अपनाए जाने की जरूरत है न कि केवल चुनिंदा घरेलू उद्योगों के संघटकों के आधार पर। प्राधिकारी ने, तदनुसार एचसीसी और यूपीएल, दोनों के लिए भी कुल आंकड़ों पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	सीआईएफ आयात कीमत		1,74,216	1,69,958	1,58,414	1,66,001
	प्रवृत्ति		100	98	91	95

2	प्रधान लागत		***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	78	177	218



110. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 में, आयात कीमत और आवेदकों की प्रधान लागत के बीच उल्लेखनीय अंतर था, जो वर्ष 2020-21 में और अधिक बढ़ गया था। तथापि, 2021-22 में प्रधान लागत में वृद्धि हुई है जबकि आयात कीमत में गिरावट आई है, जहां जांच की अवधि में प्रधान लागत में और अधिक वृद्धि हुई है, आयात कीमत लगभग समान स्तर पर बनी रही हैं, जो प्रधान लागत से कम है।

111. घरेलू उद्योग ने भारत में कच्चे माल और आयात कीमत की मासिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए भी आईएफ आयात कीमत तथा अमोनिया और कास्टिक सोडा संबंधी कीमतों के बीच अंतर का परिमाणीकरण किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

क्र. सं.	माह	अमोनिया अमरीकी डालर/मी. टन	कास्टिक सोडा अमरीकी डालर/मी. टन	प्राकृतिक गैस अमरीकी डालर/मी. टन	आयात कीमत अमरीकी डालर/मी. टन	अंतर अमरीकी डालर/मी. टन
1	2019-एम्04	361	212	417	2,461	1,717
2	2019-एम्05	337	227	414	2,556	1,816
3	2019-एम्06	315	206	394	2,515	1,824
4	2019- एम् 07	301	194	405	2,513	1,831
5	2019- एम् 08	293	202	397	2,499	1,822
6	2019- एम् 09	307	189	417	2,458	1,766
7	2019- एम् 10	326	187	366	2,483	1,824
8	2019- एम् 11	340	199	414	2,493	1,776
9	2019- एम् 12	329	186	405	2,466	1,774

10	2020- एम 01	325	176	391	2,414	1,744
11	2020- एम 02	333	152	400	2,470	1,808
12	2020- एम 03	327	155	409	2,460	1,792
13	2020- एम 04	333	155	379	2,363	1,716
14	2020- एम 05	300	173	350	1,588	969
15	2020- एम 06	297	191	312	2,364	1,764
16	2020- एम 07	268	179	271	2,309	1,772
17	2020- एम 08	281	171	210	2,317	1,829
18	2020- एम 09	282	162	217	2,266	1,780
19	2020- एम 10	318	146	241	2,214	1,699
20	2020- एम 11	321	145	261	2,248	1,714
21	2020- एम 12	331	150	316	2,102	1,513
22	2021- एम 01	333	137	336	2,210	1,615
23	2021- एम 02	371	131	342	2,242	1,623
24	2021- एम 03	439	143	325	2,219	1,564
25	2021- एम 04	580	151	306	2,125	1,393
26	2021- एम 05	629	157	378	2,089	1,263
27	2021- एम 06	632	176	332	2,078	1,271
28	2021- एम 07	664	186	418	1,952	1,046
29	2021- एम 08	716	193	486	2,087	1,088
30	2021- एम 09	725	213	407	2,017	1,061
31	2021- एम 10	768	228	467	1,963	918
32	2021- एम 11	858	276	651	1,956	664
33	2021- एम 12	999	320	668	2,262	833
34	2022- एम 01	1,256	303	677	2,204	627
35	2022- एम 02	1,288	309	548	2,352	858
36	2022- एम 03	1,274	356	725	2,300	628
37	2022- एम 04	1,588	365	765	2,155	251

38	2022- एम 05	1,707	383	656	2,158	259
39	2022- एम 06	1,338	414	703	2,345	604
40	2022- एम 07	1,294	404	828	2,244	433
41	2022- एम 08	1,300	409	951	2,094	174
42	2022- एम 09	1,321	406	1,017	2,354	367

112. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत और कच्चे माल के कारण लागतों के बीच अंतर में तेजी से गिरावट आई है। जहां वर्ष 2019-20 में अंतर औसतन 1800 अमरीकी डालर/ मी. टन था, वहीं जांच की अवधि के अंत तक यह गिरकर लगभग 400 अमरीकी डालर/ मी. टन हो गया।

ख. कीमत कटौती

113. नीचे दी गई तालिका जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत और आयातों की बिक्री कीमत के बीच तुलना को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	निवल बिक्री कीमत	पहुंच कीमत	कीमत कटौती	
		रु./ मी. टन		रु./मी. टन	%
1	चीन	***	1,71,831	***	0-10%
2	जापान	***	1,72,113	***	0-10%
3	कोरिया	***	1,78,771	***	0-10%
4	यूरोपीय संघ	***	1,90,559	***	(0-10)%
5	सभी संबद्ध देश	***	1,73,637	***	0-10%

114. यह देखा गया है कि ई.यू को छोड़कर सभी संबद्ध देशों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक हैं।

115. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि क्षति अवधि में कीमत कटौती में गिरावट आई है। एडी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है। तथापि, आवेदकों ने स्वीकार किया है कि विगत में उच्च कीमत कटौती और वर्तमान अवधि में निम्न कीमत कटौती घरेलू उद्योग और आयातों के बीच विगत में सापेक्ष रूप से काफी कम प्रतियोगिता और वर्तमान अवधि में प्रतिस्पर्धा की उच्च मात्रा को दर्शाती है। संबद्ध देशों में उत्पादकों ने अपनी कीमतों को प्रधान लागतों में बदलाव के अनुरूप नहीं रखा जिसने घरेलू उद्योग पर सामग्री को बेचने और बाजार में बने रहने के लिए घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच के अंतर को पाटने पर दबाव बनाया।

116. घरेलू उद्योग ने आगे इस बात पर और जोर डाला कि यदि उसने आधार वर्ष में समान लाभप्रद कीमतों पर बिक्री की हो हो, कीमत कटौती उच्च होती। इसे नीचे तालिका में चित्रित किया गया है।

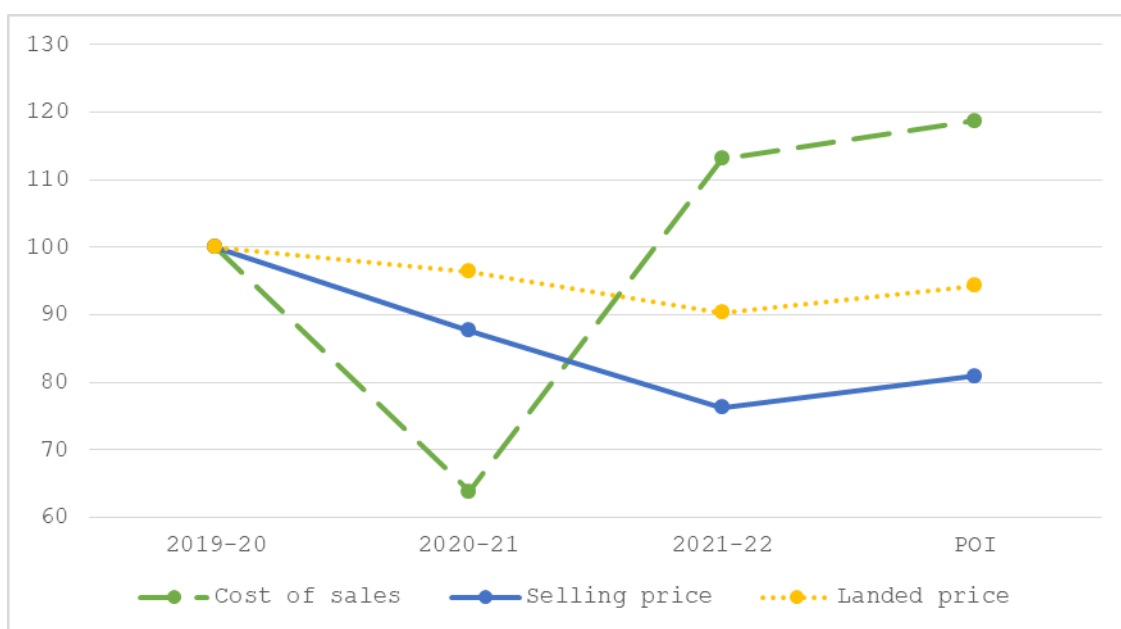
क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	जांच की अवधि	
				वास्तविक	क्या लाभ बनाए रखा गया था
1	बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***

2	पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***
3	कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	20-30%	0-10%	40-50%

ग. कीमत हास/ न्यूनीकरण

117. कीमत तालिका बिक्रियों, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत की लागत में परिवर्तन को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	युनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
3	पहुंच कीमत	रु./मी. टन	1,84,077	1,77,443	1,66,368	1,73,637
	परिवर्तन					
1	बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन		***	***	***
2	बिक्री कीमत	रु./मी. टन		***	***	***
3	पहुंच कीमत	रु./मी. टन		-6,634	-11,075	7,269
	प्रवृत्ति					
1	बिक्रियों की कीमत		100	64	113	119
2	बिक्री कीमत		100	88	76	81
3	पहुंच कीमत		100	96	90	94



118. यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में, बिक्रियों की लागत में लगभग *** रुपए (36 सूचकांक बिन्दु द्वारा) प्रति मी. टन की गिरावट आई जबकि बिक्री कीमत में *** रुपए (12 सूचकांक बिन्दु) प्रति मी. टन की गिरावट आई। घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 तक लाभप्रद था और इसलिए, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी/दमनकारी प्रभाव नहीं पड़ा था। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में लागतें उच्च थी क्योंकि उत्पादकों में से एक संयंत्र (एचसीसी) बंद था।

119. वर्ष 2021-22 में, बिक्रियों की लागत में *** रुपए प्रति मी. टन (49 सूचकांक बिन्दु) की वृद्धि हुई किन्तु बिक्री कीमत में *** रुपए प्रति मी. टन (12 सूचकांक बिन्दु) की गिरावट हुई। बिक्रियों की लागत में वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण थी। इस अवधि ने आयातों की पहुंच कीमत में 9,674 रुपए प्रति मी. टन (6 सूचकांक बिन्दु) की गिरावट भी देखी। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी। घरेलू उद्योग ने इस अवधि में हानियों का सामना किया। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया कि यह वह अवधि थी जब यूपीएल ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था और निर्यातकों ने भारतीय बाजार में पाटन आरंभ किया था।

120. बिक्रियों की लागत में *** रु. प्रति मी. टन (7 सूचकांक बिन्दु) की वृद्धि हुई और बिक्री कीमत में *** रुपए/ प्रति मी. टन (5 सूचकांक बिन्दु) की वृद्धि हुई। तथापि, आयात कीमतों में समान समानुपात में वृद्धि नहीं हुई। इसमें केवल 7269 प्रति मी. टन (4 सूचकांक बिन्दु) की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, बिक्रियों की लागत और आयातों की पहुंच कीमत के बीच का अंतर अधिक बढ़ गया और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को समान अनुपात में बढ़ाने से रोका गया। इसलिए, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का ह्रासकारी प्रभाव पड़ा।

छ. 3.4. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

क. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियां और क्षमता उपयोग

121. नीचे दी गई सारणी क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, निर्यात बिक्रियों और कैप्टिव खपत को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	171	637	637
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	247	544	496
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	144	85	78
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	216	396	431
5	निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		-	-	100	633
6	कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		-	-	100	114

122 यह अवलोकन किया गया है कि-

- क. एचसीसी का संयंत्र 2019-20 में 5 महीनों के लिए बंद था। एचसीसी की क्षमता को उस सीमा तक माना गया है।
- ख. यूपीएल ने वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था।
- ग. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है और देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। देश में मांग क्षमता का लगभग 85% है।
- घ. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के साथ ही, वर्ष 2020-21 में और उसके बाद 2021-22 में उत्पादन में भी वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में उत्पादन में गिरावट आई। जांच की अवधि में उत्पादन में यह गिरावट घरेलू बिक्रियों, निर्यात बिक्रियों और कैप्टिव खपत के बावजूद है।
- ड. क्षमता उपयोग में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है किन्तु 2021-22 में इसमें गिरावट आई, जांच की अवधि में और अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उन पर जांच की अवधि में उत्पादन में कमी करने के लिए दबाव था।
- च. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 से बिक्री मात्रा में वृद्धि घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी, जो पूर्ण भारतीय मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग उत्पादन में वृद्धि की सीमा तक उत्पाद की बिक्री करने के योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, स्टॉक के उत्पादन का उल्लेखनीय रूप से ढेर लग गया।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा 2019-20 और 2020-21 की अवधि में कोई निर्यात नहीं किया गया। निर्यात 2021-22 में आरंभ हुआ और जांच की अवधि में इसमें तेजी से वृद्धि हुई।
- ज. घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में भी जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

ख. मालसूची

123. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के अथशेष, अंतशेष और औसत मालसूची को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	अथशेष माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतशेष माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत माल सूची	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	647	1,548	1,260

124. यह देखा गया है कि मार्च, 2021 और उसके पश्चात मार्च, 2022 तक घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि, पीओआई के अंत तक मालसूची में गिरावट आई है। औसत मालसूची में 2020-21 में और वर्ष 2021-22 में और अधिक वृद्धि हुई किन्तु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

ग. बाजार हिस्सा

125. बाजार हिस्से से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	221	478	553
2	संबद्ध देश	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति		100	90	52	40
3	असंबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	24	9	9

126. यह देखा गया है कि जांच अवधि में क्षमता में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के, बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की क्षमता देश में संपूर्ण मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए, देश में मांग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का हिस्सा उस स्तर से नीचे है, जिसे यह वहन कर सकता है।

घ. लाभ/ हानि, नकद लाभ और पूंजी निवेश पर आय

127. लाभप्रदता से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	लाभ/ हानि	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	168	-47	-46
2	लाभ/ हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	361	-187	-196
3	नकद लाभ	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	141	-20	-17
4	नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	304	-81	-74
5	पीबीआईटी	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	168	-47	-45
6	पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	361	-187	-195
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	128	-16	-30

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 2019-20 में लाभ में था। एचसीसी द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ। तथापि, 2021-22 में, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उस वर्ष महत्वपूर्ण गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने 2021-22 में वित्तीय हानियों का सामना किया, जो जांच की अवधि में बढ़ गयीं।

129. वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग नकद लाभ, सकारात्मक पीबीआईटी और निवेश पर आय अर्जित कर रहा था। घरेलू उद्योग के निष्पादन में इस संबंध में 2020-21 में सुधार हुआ किन्तु 2021-22 में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन और खराब हो गया। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग ब्याज पूर्व हानि और निवेश पर ऋणात्मक आय दर्ज की।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**130.** प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	103	424	516
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	132	454	531
3	दैनिक उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	247	544	496
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	238	128	96

131. यह देखा गया है कि रोजगार एवं मजदूरी ने क्षति अवधि और जांच की अवधि में एक वृद्धि कारक प्रवृत्ति दर्शायी है। यूपीएल द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ ही रोजगार में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में उत्पादकता ने एक वृद्धिकारी प्रवृत्ति दर्शायी है क्योंकि यूपीएल ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया था।

च. वृद्धि**132.** प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाईयां	2020-21	2021-22	पीओआई
1	क्षमता	वाई/वाई	71%	272%	0%
2	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	31%	-41%	-5%
3	उत्पादन	वाई/वाई	147%	120%	-9%
4	विक्रियां	वाई/वाई	116%	84%	9%
5	मालसूची	वाई/वाई	547%	139%	-19%
6	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	15%	32%	9%
7	लाभ/ हानि	वाई/वाई	68%	-128%	3%
8	नकद लाभ	वाई/वाई	41%	-114%	-16%
9	पीबीआईटी	वाई/वाई	261%	-152%	-5%
10	आरओआई	वाई/वाई	28%	-113%	-85%

133. यह देखा गया है कि जहां कुछ मात्रा संबंधी मापदंडों ने क्षति अवधि के दौरान एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है वहीं लाभ/ हानि, पीवीआईटी, आरओआई, उत्पादन और क्षमता उपयोग ने जांच की अवधि में एक ऋणात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है।

छ. पूंजी जुटाने की क्षमता

134. यूपीएल ने विचाराधीन उत्पाद में 500 करोड़ रुपए से अधिक नया निवेश किया है। तथापि, घरेलू उद्योग देश में उल्लेखनीय क्षमताओं के बावजूद, विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन और क्षमता उपयोग का इष्टतम स्तर प्राप्त करने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग वित्तीय हानियां, ब्याज और कर पूर्व हानि तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय उपगत कर रहा है।

ज. पाटन मार्जिन

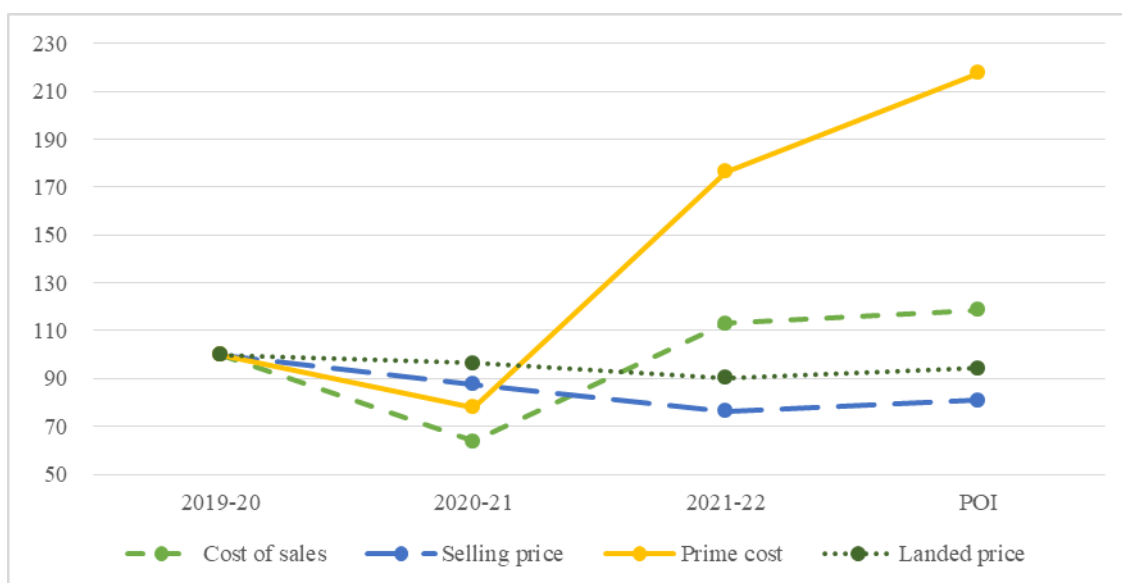
135. पाटन मार्जिन उस सीमा का एक संकेतक है जिस तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण हैं।

झ. घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

136. नीचे दी गई सारणी आयात की कीमतों और प्रधान लागतों को उतार-चढ़ाव, उत्पादन की लागत (मानक स्तर पर) और क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रु./ मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	64	113	119
2	बिक्री कीमत	रु./ मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	88	76	81
3	प्रधान लागत	रु./ मी.टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	78	177	218
4	पहुंच कीमत	रु./ मी.टन	1,84,077	1,77,443	1,66,368	1,73,637
	प्रवृत्ति		100	96	90	94

137. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की तुलना में अधिक थी। उत्पादन की लागत में 2020-21 में गिरावट आई थी किन्तु वर्ष 2021-22 में और जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यह जांच करने के लिए कि क्या उत्पादन की लागत में वृद्धि नई संयंत्र स्थापना यूपीएल के कारण थी, प्राधिकारी ने जांच अवधि में मानक स्तर (निर्धारित लागतें उच्चतम क्षमता उपयोग पर मानकीकृत की गई हैं) और प्रधान लागत (केवल परिवर्तनीय लागतों) के स्तर पर उत्पादन की लागत की तुलना की है। यह देखा गया है कि क्षति अवधि में लागतों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि यूपीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के कारण नहीं थी।



138. जहां लागतों में वृद्धि हुई है, वहीं आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। आयातों की पहुंच कीमतों में उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात केवल घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक है।

ब. क्षति पर निष्कर्ष

139. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

- क. कुल एवं सापेक्ष रूप में आयातों ने यूपीएल द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ क्षति अवधि में गिरावट दर्शायी है।
- ख. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अब घरेलू उद्योग की क्षमता मांग को वहन करने के लिए पर्याप्त है जांच की अवधि में कुल और सापेक्ष दोनों रूप में पाटित आयातों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- ग. जांच की अवधि में आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से निम्न है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।
- घ. आयात कीमत कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी हैं। जहां कच्चे माल की लागतों में वृद्धि हुई है वहीं आयात कीमतों में गिरावट आई है।
- ङ. आयात कीमत में बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसने घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने से रोका है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का दमन कर रहे थे।
- च. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है। तथापि, जांच की अवधि में गिरावट आई क्योंकि घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन स्थगित करने के लिए विवश होना पड़ा था।
- छ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, हिस्से में यह वृद्धि हानि पर बिक्री द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई है।
- ज. आवेदक की बिक्री मात्रा में वर्ष 2020-21 में एचसीसी द्वारा उत्पादन को आरंभ करने तथा वर्ष 2021-22 में यूपीएल द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के साथ वृद्धि हुई। हालांकि, जांच की अवधि में उत्पादन में दुबारा गिरावट आई है।
- झ. घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर वित्तीय हानियों और ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन की मानक लागत पर भी वित्तीय हानियों का सामना किया है।
- ञ. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और महत्वपूर्ण है।
- ट. मात्रा और कीमत, दोनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक है।

गैर-आरोप्य विश्लेषण

140. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच किया जाना जरूरी है जो समान समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न क्षति पाटित आयातों पर आरोपित न की जाए। कारक जो इस संबंध में प्रासंगिक है, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और स्वदेशी उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतियोगिता, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। इसकी नीचे जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों को भी क्षति पर आरोपित किया जा सकता है।

क. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

141. नीचे दी गई सारणी जांच की अवधि में आयातों की मात्रा और कीमत को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	आयात मात्रा मीट्रिक टन में	आयात कीमत सीआईएफ रुपए/ मी. टन	कुल आयातों में हिस्सा
1	चीन	3,400	1,58,735	52.40%
2	जापान	1,704	1,72,113	26.26%
3	कोरिया गणराज्य	936	1,78,771	14.43%
4	यूरोपीय संघ	232	1,76,036	3.58%
5	संबद्ध देश	6,272	1,66,001	97.21%
6	ताईवान	180	1,52,497	2.79%
7	जोड़	6,452	1,65,603	100%

142. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त, ताईवान से भी विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया है। हालांकि ताईवान से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है और यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकता।

ख. मांग में संकुचन

143. क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण नहीं हो सकती है।

ग. खपत का पैटर्न

144. प्राधिकारी की जानकारी में खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है। इसलिए, यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता था।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां

145. यह जांच यह नहीं दर्शाती कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकती थीं।

ड. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

146. जांच से यह नहीं पता चला है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था जो घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण नहीं हो सकता था।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

147. वर्तमान क्षति मूल्यांकन के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को पृथक-पृथक रखा गया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन के संभावित समावेशन के कारण क्षति पर विश्लेषण गलत प्रस्तुतीकरण नहीं है।

148. यह देखा गया है कि ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हों। इसलिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है जैसाकि नीचे स्थापित किया गया है।

क. आयातों की पहुंच कीमत में बिक्री की कीमत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। जहां बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं आयातों की कीमत में गिरावट आई है।

ख. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्रियों की कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम हैं। आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती कर रहे हैं जिसने लागत में उतार-चढ़ाव के अनुरूप इसकी बिक्री कीमतों के समान रखने से रोका है। आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

ग. पाटित आयातों से कीमत दबाव ने घरेलू उद्योग पर वित्तीय हानि पर बिक्री करने के लिए विवश किया है। घरेलू उद्योग भी नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है।

घ. आयातों की लगातार निम्न कीमतों ने आवेदकों को इष्टतम स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

च. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उस स्तर से नीचे है जिस पर पूरा कर सकता है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

149. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर आवेदकों के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित की है। गैर-क्षतिकारक कीमत को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित जानकारी/ आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन को परिकलित करने के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादन की पहुंच कीमत के साथ गैर-क्षतिकारक कीमत की तुलना की गई है। गैर-क्षतिकारक कीमत को निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल और युटिलिटीज के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत और/ या एनआईपी में असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों और/ या परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। नियमावली के अनुबंध- III में यथा निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत पर पहुंचने के लिए ब्याज, निगमित कर की वसूली तथा लाभ के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @22%) को अनुमति दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी अमरीकी डालर/ मी. टन	पहुंच कीमत अमरीकी डालर/ मी. टन	क्षति मार्जिन अमरीकी डालर/ मी. टन	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
1	चीन जन. गण.					
क	हेबेई चेंगशिन कंपनी लिमि.	***	***	***	***	10-20
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
2	यूरोपियन संघ					
क	ल्युसेबनी जवोडी द्रासलोव्का ए. एस.	***	***	***	***	0-10

	कोलिन					
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	0-10
3	जापान					
क	कोई भी	***	***	***	***	20-30
4	कोरिया गण. जन.					
ख	कोई भी	***	***	***	***	20-30

भारतीय उद्योग मुद्दे

अ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के मुद्दों के संबंध में निम्नानुसार निवेदन किया है:

- क. शुल्कों को लागू किए जाने से प्रयोक्ता उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, मुख्य रूप से आम जनता पर क्योंकि भारत में समान वस्तु का 60% उत्पादन कृषि और फार्मा सेक्टर के लिए जाता है।
- ख. उत्पाद की कीमत में वृद्धि जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों पर प्रभाव डालेंगी जैसे एम्पीसिलीन, सिफेलेक्सिन, क्लोपीडोग्रेल और फंगीसाइड्स (कवकनाशी) प्रागरेंसिस (फिनेथिल अल्कोहल) एंटी बायोटिक्स और अन्य फर्मास्युटिकल्स।
- ग. डीसीएम श्री राम लिमिटेड महत्वपूर्ण मध्यवर्ती औषधियों में एक- डी (-) अल्फा फिनाइल गलाइसिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड (पीजीसीएस) के लिए एकमात्र ग्लोबल वैश्विक है जो सिफेलेक्सिन के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है।
- घ. उपायों को लागू किए जाने से घरेलू उत्पादकों को कार्टेल बनाने की अनुमति मिल जाएगी जिसके परिणामस्वरूप बाजार में प्रवेश करने के लिए बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी।
- ड. पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप प्रयोक्ता उद्योग को हानि होगी क्योंकि विचाराधीन उत्पाद को प्रयोग करके उत्पादित किए गए माल पर बहुत कम मार्जिन मिलता है।
- च. एससीसी के विरुद्ध इसके विनिर्माण करने वाले संयंत्रों से असुरक्षित अपशिष्ट निपटान के कारण हर जगह विरोध आयोजित किए जा रहे हैं जिसके कारण स्थानीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमि और जल प्रदूषण हो रहा है।
- छ. आवेदकों से आपूर्ति अनियमित है।
- ज. उपभोक्ता उद्योग पर आयात करने का दबाव है क्योंकि आवेदक शुद्धता संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
- झ. यूपीएल द्वारा सप्लाई किया गया उत्पाद फार्मा क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है जो भारतीय मांग के 25-30% के लिए उत्तरदायी है।

अ.2. आवेदकों की ओर से किए गए निवेदन

151. आवेदकों ने भारतीय उद्योग के मुद्दों के संबंध में निम्नानुसार निवेदन किए हैं:

- क. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र और उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव महत्वहीन है।
- ख. पाटन रोधी शुल्क को लागू किया जाना अपस्ट्रीम उद्योग को विकास करने में लाभ पहुंचाएगा। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल अमोनिया, कास्टिक सोडा, सल्फरिक एसिड और प्राकृतिक गैस हैं जो भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं और जिसे घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार से अपनी जरूरतों के अनुसार पूरा कर लिया है।

- ग. पाटन रोधी शुल्क को लागू किया जाना घरेलू विनिर्माताओं के हित में होगा क्योंकि यह घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतियोगिता करने और उनके वित्तीय स्थिति में सुधार करने की अनुमति देगा।
- घ. पाटन रोधी शुल्क को लागू किया जाना उचित कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा में उत्पाद की आपूर्ति करने में समर्थ प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू उद्योग की प्राप्ति करने में उपभोक्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को चीनी उत्पादकों के विपरीत, जिन्हें बाजार बदलने का विकल्प प्राप्त है यदि वे अपनी शर्तों पर खरीदार प्राप्त नहीं कर पाते, उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखना होता है। इसलिए, उपभोक्ता मालसूची की निम्न मात्रा को बनाए रख सकते हैं और निर्यातकों की तुलना के घरेलू उद्योग से खरीद करते समय नियोजित पूंजी में बड़ी मात्रा में रुकावट नहीं होगी।
- ड. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना उत्पाद का एक सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता के हित में होगा।
- च. उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित और पाटित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच पर निर्भर नहीं कर सकती।
- छ. पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना और/ या घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखना नहीं बल्कि संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा किसी भी व्यापार विकृति को दूर करके एक समान अवसर स्थापित करना और उचित प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय उद्योग को एक अवसर की स्वीकृति प्रदान करना है।
- ज. पाटन रोधी शुल्कों के उद्देश्यों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी [2006 (202) ई.एल.टी.23 (एस.सी.)] के मामले में मान्यता प्रदान की गई है जिसमें एक आधुनिक, अत्यधिक औद्योगिक, शक्तिशाली राज्य का सृजन करने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में पाटनरोधी कानून द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।
- झ. हिन्दुस्तान केमिकल कंपनी के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन के दावे के संबंध में, मामले की माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जांच की गई है और कंपनी ने प्रचालन के लिए पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त की है।
- ञ. आवेदकों ने ऐसी शुद्धता की आपूर्ति भी की है, जैसीकि उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित की गई थी।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

152. प्राधिकारी ने इस बात पर जोर दिया है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति को सुधारना है। पाटनरोधी उपायों की सिफारिश, यदि कोई हो, मनमाने ढंग से संबद्ध देशों से आयातों की कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। इसके बजाय यह पाटन, क्षति के विस्तृत विश्लेषण और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध पर आधारित है तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार ऐसे उपायों की उपस्थिति से बना रहेगा। घटती प्रतिस्पर्धा से परे, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों के जरिए अनुचित लाभों को प्राप्त करने से रोकता है। प्रतिस्पर्धा कम होने के बजाय, पाटनरोधी उपाय पाटन पद्धतियों के माध्यम से अनुचित लाभ के संचय को रोकने का काम करते हैं। यह संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करते हैं। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क उचित व्यापार पद्धतियों के लिए एक बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाले हैं।
153. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्यो सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके विचारों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रकार के संभव प्रभावों सहित वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचारों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर एक पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए भी एक प्रश्नावली निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सप्लाई किए गए उत्पादों के स्रोतों को बदलने की घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के

प्रभाव, कारक जो पाटन रोधी शुल्क को लागू करने के द्वारा उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन को त्वरित या विलंब कर सकते हैं, के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ, जानकारी की मांग की।

154. वर्तमान जांच में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया:

क्र. सं.	आयातक/ प्रयोक्ता
1	एशियन कैमटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	भारत रसायन लिमिटेड
3	कैमटेक इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
5	यूरोफाइन केमिकल्स लिमिटेड
6	एम्मेनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
7	हिमानी इंडस्ट्रीज लिमि.
8	एमबी सेल्स कारपोरेशन
9	मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड
10	प्रीमियर इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

155. प्रयोक्ताओं की उपरोक्त सूची से, केवल भारत रसायन लिमिटेड और डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं।

156. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी जारी की। आवेदकों और डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस प्रश्नावली के लिए एक विस्तृत उत्तर दायर किया है।

157. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उन्मूलन किया जाना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने का प्रयोजन किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना और उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित करना नहीं है।

158. प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर की जांच की है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित उत्पादों में प्रयोग किया जाता है:

डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	
क्र. सं.	उत्पाद
1	डीएल -2- (2- क्लोरोफिनाइल) ग्लाइसिन
2	डीएल अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन
3	अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन
4	अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड
5	अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन डेन साल्ट
6	एसआईपीए-2 अंडर कान्ट्रेक्ट मैनुफैक्चरिंग
7	वेलाइन
8	बेनजिल साइनाइड

भारत रसायन लिमिटेड	
9	4 एसिटिल 2-मिथाइल बेंजामाइड (अम्बड) 98%
10	फेन्वालेट टेक्नीकल
11	पारा- क्लोरो- ए- आईएसओ (पीसीए पाउडर)
12	पैरा क्लोरो बेंजल साइनाइड
13	पैरा क्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड (पीसीपीए पाउडर)
14	लाम्बडा साइहालोथरिन टेक्नीकल (पीडब्ल्यू)
15	लाम्बडा साइहालोथरिन टेक्नीकल (एलक्यू)
16	साइपरमेथरिन टेक्नीकल
17	अल्फा साइपरमेथरिन टेक्नीकल
18	फ्लक्सामेटामाइड

159. नीचे दी गई सारणी डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद के हिस्से और इस पर उसके प्रभाव को दर्शाती है:

क्र. सं.	उत्पाद	खपत संबंधी मानदंड	प्रभाव %	प्रभाव रेंज
1	डीएल -2- (2- क्लोरोफिनाइल) ग्लाइसिन	***	***	1-2%
2	डीएल अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन	***	***	1-2%
3	डी (-) अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन	***	***	1% से कम
4	डी (-) अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	***	***	1% से कम
5	डी (-) अल्फा फिनाइल ग्लाइसिन डेन साल्ट	***	***	1% से कम
6	वेलाइन	***	***	1-2%
7	बेनजिल साइनाइड	***	***	3-4%
8	4-एसिटिल 2-मिथाइल बेंजामाइड (अम्बड) 98%	***	***	1% से कम
9	फेन्वालेट टेक्नीकल	***	***	1-2%
10	पैरा- क्लोरो- ए- आईएसओ (पीसीए पाउडर)	***	***	1-2%
11	पैरा क्लोरो बेंजल साइनाइड	***	***	2-3%
12	पैरा क्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड (पीसीपीए पाउडर)	***	***	2-3%
13	लाम्बडा साइहालोथरिन टेक्नीकल (पीडब्ल्यू)	***	***	1% से कम
14	लाम्बडा साइहालोथरिन टेक्नीकल (एलक्यू)	***	***	1% से कम

15	साइपरमिथरिन टेक्नीकल	***	***	1% से कम
16	अल्फा साइपरमिथरिन टेक्नीकल	***	***	1% से कम
17	फ्लक्सामेटामाइड	***	***	1% से कम

- 160.** अतः जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निवेदनों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रभाव 50 प्रतिशत से अधिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों में 1% से कम है जबकि कई अन्यो के लिए यह 1%-2% के बीच है।
- 161.** प्रयोक्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग पर आयात करने का दबाव था क्योंकि यह बांछित शुद्धता वाले उत्पाद की सप्लाई नहीं कर सकता था। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विश्लेषण प्रमाणपत्र की जांच की और पाया कि आवेदकों द्वारा सप्लाई किए गए उत्पाद में वही शुद्धता सामग्री है जैसी कि निर्यातकों के उत्पाद में। इसलिए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- 162.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि हाल ही में एक घरेलू उद्योग द्वारा किया गया महत्वपूर्ण निवेश (500 करोड़ रुपए) मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, पाटन की वर्तमान स्थिति ने आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण उत्पादन को स्थगित करने के लिए घरेलू उत्पादकों पर दबाव डाला। यह भी देखा गया है कि जांच की अवधि की तुलना में, आयातों की पहुंच कीमत विगत में उच्च थी। प्रयोक्ताओं ने निष्पक्ष बाजार स्थितियों को ध्यान में रखकर अपने संयंत्र स्थापित किए हैं। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि प्रयोक्ताओं के प्रचालन सिर्फ इसलिए अलाभकारी हो जाएंगे क्योंकि शुल्क को लागू करने के द्वारा पाटन को रोका गया है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पुनः स्थापित की गई है। पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे कर समान अवसरों का सृजन कर सकते हैं और बाजार में आपूर्ति को जारी रख सकते हैं।
- 163.** यह भी देखा गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और पाटन रोधीशुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की अनुपलब्धता नहीं होगी। वास्तव में, यदि सामग्री घरेलू बाजार से खरीदी जाती है तो आपूर्ति के लिए लीड टाइम कम हो सकता है और उपयोगकर्ता निम्न स्तर की इन्वेंट्री बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा, पाटन रोधीशुल्क संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि आयात उचित कीमतों पर जारी रह सकता है।
- 164.** प्राधिकरण मानता है कि पाटन रोधीशुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर असर पड़ सकता है। हालांकि, पाटन रोधी उपाय लागू करने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। यह भी देखा गया है कि अतीत में कीमतें वर्तमान कीमतों से अधिक थीं। पाटन रोधीशुल्क लगाने से केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात कीमतें उचित कीमतों पर बहाल हो जाएंगी।
- 165.** यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू बाजार से की है। इसलिए, शुल्क लगाने से अपस्ट्रीम उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी और अपस्ट्रीम उद्योग को फलने-फूलने में भी मदद मिलेगी।

ट. प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ

ट.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

- 166.** अन्य इच्छुक पार्टियों ने प्रकटीकरण विवरण के लिए निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

- क. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता की कोई जांच नहीं की जाती है।
- ख. आयात की मात्रा के संबंध में भी कोई विश्लेषण नहीं किया गया है यदि वे निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- ग. हेबेई चेंगक्सिन कंपनी लिमिटेड ने ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम डीए 2011 के मामले में माननीय सीस्टेट के निर्णय का हवाला दिया है। माननीय सीस्टेट ने घरेलू बिक्री में वृद्धि, उत्पादन और क्षमता उपयोग, बढ़े हुए मुनाफे जैसे कारकों की जांच की थी। नियोजित पूंजी पर रिटर्न और इन्वेंट्री क्षति नहीं

दिखाती है। प्रतिवादी ने ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग के उपरोक्त मामले में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के साथ विषय जांच में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना की है और दावा किया है कि जांच को उसी तर्ज पर समाप्त किया जाना चाहिए।

- घ. क्षति की अवधि में क्षमता में 537% की वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षति जांच अवधि में मूल्यहास लागत, ब्याज लागत, मजदूरी और ओवरहेड्स में वृद्धि का कोई विश्लेषण नहीं है।
- ङ. उत्पादन की लागत को रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल/उपयोगिताओं की लागत में अनुचित, असामान्य और अस्थायी वृद्धि के लिए समायोजित किया जाना चाहिए ताकि विषय वस्तुओं के उत्पादन की उचित लागत को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- च. चेक गणराज्य से आयात की कम मात्रा और नकारात्मक मूल्य कम होने को ध्यान में रखते हुए, चेक गणराज्य से आयात क्षति का कारण नहीं हो सकता है। जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- छ. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने गैर-विषय देशों से आयात किया है। तथापि, एचसीसी ने कोरिया आरपी से आयात किया है और सूचना छुपा ली गई है।
- ज. प्राधिकरण ने नोट किया है कि विगत में आयात डंप न किए गए मूल्यों पर किया गया था। अतीत में कीमतें समान स्तर पर थीं और यदि मौजूदा कीमतें डंप की गई कीमतों पर हैं, तो यह दर्शाता है कि अतीत में आयात डंप की गई कीमतों पर भी थे।
- झ. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह 90% अथवा मासिक उच्चतम क्षमता उपयोग और दोनों उत्पादकों के बीच सर्वोत्तम उपभोग मानकों पर विचार करते हुए उत्पादन की मानकीकृत लागत की गणना करे क्योंकि नए संयंत्र में उच्च खपत मानदंड होंगे।
- ञ. प्राधिकरण द्वारा की गई गणना के अनुसार पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नीचे बताया गया है।
- ट. प्राधिकरण ने नोट किया है कि एमनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू उद्योग से खरीद की है। खरीदारी सख्त जरूरत में की गई थी जब उपयोगकर्ताओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।
- ठ. यह ज्ञात नहीं है कि प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा किए गए आयात के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को सत्यापित करने के लिए उसके रिकॉर्ड की जांच की है या केवल प्रकटीकरण में दर्ज किए गए लेनदेन वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।
- ड. प्राधिकरण यह सत्यापित करने में विफल रहा है कि प्राकृतिक गैस की अनिश्चित और अनियमित आपूर्ति और तकनीकी बाधाओं के बावजूद घरेलू उद्योग 98% शुद्धता स्तर की पुष्टि करने में सक्षम है।
- ढ. पीसीएन की उपयुक्त पद्धति का निर्धारण प्राधिकरण की बाध्यकारी जिम्मेदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इच्छुक पक्ष क्या कहते हैं और क्या टिप्पणी करते हैं।
- ण. कई देशों से निर्यातकों की अचानक वापसी से प्राधिकरण द्वारा गहरी जांच शुरू हो जानी चाहिए थी। यह बाजार में एक अंतर्निहित बदलाव को इंगित करता है जो उत्पाद की आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करता है और पूरी तरह से जांच की आवश्यकता होती है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ।

167. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण के लिए निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।

- क. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह उन सभी कोडों को निर्दिष्ट करे जिनमें उत्पाद आयात किया जाता है, शुल्क तालिका में या 4 अंकों के स्तर पर शुल्क की सिफारिश करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अजंता प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के हाल के फैसले के कारण। भारत संघ।

- ख. चीन जनगण और गैर-प्रतिभागी देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रतिभागी उत्पादकों के लिए उच्चतर सामान्य मूल्य निर्यातकों की भागीदारी को हतोत्साहित करेगा।
- ग. प्राधिकरण ने हेबेई चेंगशिन कं, चीन और निप्पॉन सोडा, जापान के मूल्य रूझान पर क्षति की अवधि में विचार नहीं किया है जो भारतीय बाजार में चयनात्मक आक्रामक मूल्य निर्धारण दर्शाता है।
- घ. जबकि आवेदक ने कुछ व्यय आवंटित करने के लिए उत्पादन मात्रा अनुपात का दावा किया था, प्राधिकरण ने उन्हें उत्पादन मूल्य अनुपात के आधार पर आवंटित किया है। ये व्यय प्रति इकाई आधार पर किए जाते हैं और उत्पादन मूल्य पर आबंटन उपयुक्त नहीं होगा।
- ङ. यूपीएल की गैर-हानिकारक कीमत की गणना में अनुमत शुद्ध अचल संपत्ति और कार्यशील पूंजी यूपीएल द्वारा किए गए दावे की तुलना में काफी कम है और कोई कारण नहीं बताया गया है।
- च. प्राधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि घरेलू बाजार में पाटन के कारण स्टॉक जमा होने के कारण उत्पादन में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप अंततः जांच अवधि में मालसूची में गिरावट आई।
- छ. प्राधिकरण ने अंशदान की गणना पर विचार नहीं किया है। घरेलू उद्योग नकारात्मक योगदान के साथ कार्य कर रहा है। जबकि एक उत्पादक अपनी निश्चित लागत पर नुकसान उठा सकता है, यदि बिक्री मूल्य उत्पादन करने के लिए सीमांत लागत से भी कम है, तो उत्पादन करने में कोई व्यावसायिक औचित्य नहीं है।
- ज. भले ही अन्य दलों ने कहा है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन वे आधार वर्ष की तुलना में अधिक बने हुए हैं।
- झ. जांच अवधि के बाद की प्रवृत्तियों की जांच करने का अर्थ होगा कि घरेलू उद्योग (क्षति की जांच करने के लिए) और भाग लेने वाले उत्पादकों (डंपिंग की जांच करने के लिए) के नए आंकड़ों का संग्रह अपेक्षित होगा। जब तक प्राधिकरण पूरी प्रक्रिया पूरी करता है, तब तक जांच की बाद की अवधि भी पुरानी हो जाएगी, और प्रदान किए गए आंकड़े फिर से बाजार के उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे।
- ञ. घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में इन्वेंट्री होल्डिंग को काफी निचले स्तर पर रखा जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का लीड टाइम आयात की तुलना में काफी कम है।

ट.3. प्राधिकरण द्वारा परीक्षा

168. प्राधिकरण ने इच्छुक पाठयों द्वारा किए गए प्रकटनोत्तर प्रस्तुतीकरण की जांच की है और नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से उनका समाधान किया गया है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में इसे दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
169. प्राधिकरण नोट करता है कि हेबेई चेंगक्सिन कंपनी लिमिटेड ने सीईएसटीएटी में ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम डीए 2011 के साथ वर्तमान मामले के तथ्यों की तुलना की है। प्राधिकरण नोट करता है कि दोनों मामलों के तथ्य अलग-अलग हैं। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को नुकसान, नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न और उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट का सामना करना पड़ा है, जो ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग बनाम डीए 2011 के मामले में नोट किए गए समान नहीं है। एकमात्र समानता यह है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री दोनों मामलों में बढ़ी है। हालांकि, वर्तमान मामले में वृद्धि लागत पर आई है क्योंकि घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी कीमतें कम कर दीं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए, प्राधिकरण नोट करता है कि दोनों मामलों के बीच कोई समानांतर नहीं निकाला जा सकता है और इसलिए तत्काल मामले को समाप्त करने का अनुरोध आधार नहीं रखता है।

170. जहां तक अनुचित अनुपातों के आबंटन और गैर-हानिकारक मूल्य के अपर्याप्त प्रकटीकरण पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि गैर-हानिकारक मूल्य नियमों के अनुबंध-III और प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही सतत पद्धति के आधार पर निर्धारित और प्रकट किया गया है।
171. जबकि प्राधिकरण एक उपयुक्त पीसीएन पद्धति स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, यह इस बात पर जोर देता है कि इच्छुक पार्टियों की टिप्पणियां अत्यधिक सामग्री हो सकती हैं। उद्योग विशेषज्ञता एक सटीक पद्धति के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है जो खोजी प्रक्रिया के भीतर पारदर्शिता के महत्व को प्रदर्शित करती है। प्राधिकरण नोट करता है कि रचनात्मक इनपुट एक जांच की मजबूती को काफी बढ़ाते हैं। Emmennar की इस भूमिका को यह कहकर खारिज करना कि यह महत्वहीन है कि इच्छुक पक्ष क्या कहते हैं और टिप्पणी करते हैं, जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता और कठोरता को कमजोर करता है। पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण ने विषय जांच में पीसीएन की कोई पद्धति नहीं अपनाने का निर्णय लिया।
172. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर टिप्पणियों का संबंध है, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स डाटा और घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए रिकार्डों से इसकी जांच की है। जांच की अवधि में कोई आयात नहीं किया जाता है।
173. जहां तक नए संयंत्र के कारण उच्च मूल्यास लागत, मजदूरी और व्याज लागत पर टिप्पणियों का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने उत्पादन की मानकीय लागत पर भी निष्पादन की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को तब भी नुकसान उठाना पड़ा है जब घरेलू उद्योग के संयंत्र को इष्टतम क्षमता उपयोग पर परिचालन करने पर विचार किया जाता है।
174. जहां तक टिप्पणियों का संबंध है कि विगत में मूल्य समान स्तर पर थे और यदि वर्तमान मूल्य पाटित मूल्यों पर हैं तो इससे यह पता चलता है कि विगत में आयात पाटित मूल्यों पर भी थे। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों की टिप्पणी कच्चे माल की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखने में विफल रहती है। क्षति की अवधि में कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है लेकिन आयात मूल्य में गिरावट आई है।
175. विरोधी इच्छुक पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों पर कि उत्पादन की लागत को समायोजित करने की आवश्यकता है, प्राधिकरण नोट करता है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि आवेदक के साथ-साथ निर्यातकों के लिए सामान्य कारक हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रश्न का निर्णय आदर्श परिस्थितियों को मानकर नहीं किया जा सकता बल्कि इसका निर्णय प्रचलित स्थिति के आधार पर किया जाना है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह घरेलू उद्योग पर विचार करे जैसा कि यह विद्यमान है और यह जांच करेगा कि क्या घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षति की अवधि में खराब हुआ है।
176. इमेन्नार ने कहा है कि कई भागीदार निर्यातक यह कहते हुए वर्तमान जांच कार्यवाही से पीछे हट गए हैं कि "व्यापार परिदृश्य में तेजी से बदलाव के कारण निर्यातक संबंधित वस्तुओं के अपने व्यवसाय को जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं"। एमेन्नार का कहना है कि निर्यातकों के इस तरह के बयानों और उनके परिणामस्वरूप वापसी के लिए प्राधिकरण से महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाता है कि इमेन्नार ने निर्यातकों को वापस लेने से किए गए सामान्य बयान पर अनुचित जोर दिया है। किसी भी व्यापार उपचारात्मक जांच में भाग लेने का निर्णय एक स्वैच्छिक निर्णय है और वाणिज्यिक हित द्वारा निर्देशित है। भाग लेने वाले निर्यातक जिन्होंने बाद में जांच से वापस ले लिया है, उन्होंने केवल इस सामान्य बयान को बताया और "तेजी से बदलाव" को इंगित नहीं किया, जिसने उन्हें विषय वस्तुओं के अपने व्यवसाय को बंद करने के लिए मजबूर किया। जब तक कोई इच्छुक पक्ष विशेष रूप से किसी मुद्दे को इंगित नहीं करता है, तब तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण इसकी प्रकृति का विश्लेषण कैसे कर सकता है। यहां तक कि

इमेन्नार, जिन्होंने इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए कहा है, इस संबंध में किसी भी कारक को इंगित करने में विफल रहे हैं। प्राधिकरण को किसी इच्छुक पक्ष द्वारा हर निराधार दावे या केवल कथन का परीक्षण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष और सिफारिश

177. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:

- क. पाटन रोधी शुल्क का अनुरोध करने वाला आवेदन हिंदुस्तान केमिकल कंपनी और यूपीएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- ख. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम साइनाइड है, इसके रूप की परवाह किए बिना।
- ग. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के लिए एक समान वस्तु है।
- घ. आवेदकों ने यूपीएल लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले विगत में आयात किया था। आवेदकों ने 2020-21 में या जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- ङ. आवेदकपाटन रोधीनियमों के नियम 2 (बी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं और आवेदनपाटन रोधीनियमों के नियम 5 (3) की आवश्यकता को पूरा करता है।
- च. विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन माजन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन सकारात्मक हैं।
- छ. घरेलू उद्योग को क्षति लगी है जैसा कि निम्नलिखित द्वारा स्थापित किया गया है: -
 - i. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग के पास क्षमता अब मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जांच की अवधि में पूर्ण और सापेक्ष दोनों शर्तों में पाटित आयात की मात्रा काफी अधिक है।
 - ii. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहा था।
 - iii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन को निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया था।
 - iv. घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नुकसान पर बेचना पड़ा। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी उस स्तर से काफी नीचे है जिसे वह पूरा कर सकता है।
 - v. घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान हो रहा है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न मिल रहा है।
- ज. अन्य इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया था कि क्षति क्षमता विस्तार के कारण है। तथापि, घरेलू उद्योग को उत्पादन की मानकीय लागत पर भी वित्तीय हानि हुई है।
- झ. ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो सकती हो। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण केवल भारतीय बाजार में उत्पाद की पाटन है।

- ज. घरेलू उद्योग ने मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण निवेश (500 करोड़ रुपये) किया है। पाटन की मौजूदा स्थिति ने घरेलू खिलाड़ियों को आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण उत्पादन निलंबित करने के लिए मजबूर किया है।
- ट. देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमता देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ठ. प्राधिकरण मानता है कि पाटन रोधीशुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटन रोधीशुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

178. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को पाटन, क्षति, कारण लिंक और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित उपबंधों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के बाद, प्राधिकरण का ध्यान है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने और क्षति की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

179. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने पाटन के माजन और क्षति के माजन के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण ने चीन जन गण में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर ऐसे संशोधित निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है, जैसा कि नीचे शुल्क सारणी के कॉलम 7 में दर्शाया गया है, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ आइटम	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क \$/MT
1	2	3	4	5	6	7
1	2837	सोडियम साइनाइड, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो	चीन	चीन सहित कोई भी देश	हेबै चेंगक्सिन कं, लिमिटेड	286
2	-वही-	-वही-	चीन	चीन सहित कोई भी देश	ऊपर क्र.सं. (1) में उल्लिखित के अलावा कोई भी निर्माता	554
3	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय	चीन	ऊपर क्र.सं. (1) में उल्लिखित	554

			संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश		के अलावा कोई भी उत्पादक	
4	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	लुसेबनी ज़ावोडी ट्रैस्लोव्का ए.एस. कोलिन	13
5	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	ऊपर क्र.सं. (4) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक।	230
6	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश	यूरोपीय संघ	ऊपर क्र.सं. (4) में उल्लिखित के अलावा कोई भी उत्पादक	230
7	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	447
8	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी निर्माता	447
9	-वही-	-वही-	कोरिया गण. जन.	कोरिया गण. जन. सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	413
10	-वही-	-वही-	चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया के अलावा कोई भी देश	कोरिया गण. जन.	कोई भी निर्माता	413

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

आगे की प्रक्रिया

180. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अनन्त स्वरूप, नामित प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th March 2024

Case No. AD (OI)-03/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Sodium Cyanide (NaCN)' originating in or exported from China PR, European Union, Japan and Korea RP.

F. No. 6/03/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as “AD Rules”);

BACKGROUND OF THE CASE

1. Hindusthan Chemical Company (HCC) and UPL Limited (UPL) (“hereinafter referred to as the ‘applicants’ or the ‘domestic industry’”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Anti-Dumping Rules, 1995 (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Sodium Cyanide (NaCN)**” (hereinafter also referred to as the ‘product under consideration’ or the ‘PUC’, or the ‘subject goods’) from China PR, European Union, Japan and Korea RP (hereinafter also referred to as the ‘subject countries’).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima-facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/03/2023-DGTR dated 31st March, 2023, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of Rules.
 - ii. The Authority issued a public notice dated 31st March 2023 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 31st March 2023 to the embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users in India, and the other interested parties, as per the details made available by the applicants. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - v. The embassies of the subject countries were sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters with the request to advise the exporters/producers from their respective subject countries to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.
 - vi. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application.
 - vii. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as ‘EIQ’) to the interested parties including the Department of Chemicals & Petrochemicals seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.

- viii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters from the subject countries, whose contact details were provided by the domestic industry in the application, in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

S. No.	Country	Producer/Exporter
1	China PR	i. Hebei Chengxin Co. Ltd. ii. Zhejiang Chemicals Import and Export. iii. JSM (Shenzhen) Enterprise Company Limited. iv. Asambly Chemicals Company Limited. v. Anhui Anqing Shunchuang Chemical.
2	European Union	i. Cyplus Gmbh (Evonik Subsidiary) ii. Evonik Industries Ag iii. Draslovka Holding B.V. iv. Union Group Chemical Company S. L.
3	Japan	i. Sojitz Corporation
4	Korea RP	i. Hanwha Corporation ii. Unid Global Corporation iii. Dk Metal World Ltd.

- ix. In response to the above notification, the following producers/exporters of the product under consideration from the subject countries have registered as an interested party.

S. No.	Country	Producer/Exporter
1	China PR	i. Hebei Chengxin Co. Ltd
2	European Union	i. CyPlus GmbH ii. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
3	Japan	ii. Nippon Soda Co. Ltd. iii. Sojitz Corporation
4	Korea RP	i. Taekwang Industrial Co. Ltd

- x. The producers/exporters from the subject countries who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.

- xi. The Authority also sent questionnaires to the following known importers/users of the product under consideration in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

S. No.	Importers/Users
1.	Arshiya Logistics Service Limited
2.	Ascent Finchem Private Limited
3.	Ashoka Meta Chem Industries
4.	Asian Chemtech Private Limited
5.	Benzo Chem Industries Private Limited
6.	Bharat Rasayan Limited
7.	Chemplast Sanmar Limited
8.	Chemtech Intermediates Private Limited
9.	DCM Shriram Industries Limited
10.	Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited

11.	Divis Laboratories Limited
12.	Emmennar Pharma Private Limited
13.	Eurofine Chemicals
14.	Gharda Chemicals Limited
15.	Grauer & Weil (I) Limited
16.	Hemani Industries Limited
17.	Heranba Industries Limited
18.	Hikal Limited
19.	Hindustan Zinc Limited
20.	Honour Lab Limited
21.	Inventys Research Company Limited
22.	Jaggo Overseas
23.	M.B. Sales Corporation
24.	Mahavir Expochem Limited
25.	Meghmani Organics Limited
26.	Premier Intermediates Private Limited
27.	Rathoure Trading Company
28.	Sabari Chemicals Private Limited
29.	Sanjay Chemicals (I) Private Limited
30.	Shree Ganesh Chemicals
31.	Shyamal Chemical Industries
32.	Tagros Chemicals India Private Limited
33.	Techno Commercial traders
34.	Teva Api India Private Limited
35.	Yamuna Meta Chem

- xii. The following importers/users of the product under consideration in India have registered as an interested party in the present investigation.

S. No.	Importer/User
1	Asian Chemtech Private Limited
2	Bharat Rasayan Limited
3	Chemtech Intermediates Private Limited
4	DCM Shriram Industries Limited
5	Eurofine Chemicals Limited
6	Emmenar Pharma Private Limited
7	Hemani Industries Limited
8	M B Sales Corporation
9	Meghmani Organics Limited
10	Premier Intermediates Private Limited

- xiii. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The Authority has relied upon the same for the subject investigation.
- xiv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2021 to 30th September 2022 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2019 to 31st March 2020, 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022 and the period of investigation (POI).
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held on 7th December 2023. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- xvi. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvii. The information submitted by the applicants has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final finding.
- xviii. The information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries was also examined through desk verification to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present disclosure statement.
- xix. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the manner prescribed through Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims.
- xx. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxi. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 19th March, 2024 and the interested parties were allowed time up to 24th March 2024 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding notification.
- xxii. '***' in this document represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of Rules.
- xxiii. The exchange rate for the POI (October 2022 – September 2023) adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$=Rs 77.48.P

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation is as follows:

"3. The product under consideration for the present investigation is 'Sodium Cyanide' which is a moderately strong base. It is a poisonous compound with the formula NaCN. It is white in colour and is a water-soluble solid. Cyanide cation has a high affinity for metals, thus, attributing high toxicity to this base.

4. Uses: Sodium Cyanide is used for extraction of gold and silver from their respective ores, in electroplating, heat treatment of metals (case hardening), manufacturing insecticides, dyes, pigments, bulk drugs and in many organic syntheses, agrochemicals, nylon intermediates, gelating compounds, ore flotation and pharmaceutical intermediates.

5. Tariff classification: The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 283711 of the Customs Tariff Classification. However, in the past, the PUC has also been imported under other sub-headings as well, such as 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 and 28371910.

C.1 Submissions made by the other interested parties.

5. The other interested parties have submitted as follows with regard to the product under consideration and like article:
- The product under consideration, sodium cyanide (NaCN) exists in powder or cylindrical tablet forms whereas UPL only produces liquid sodium cyanide as a by-product. The petition and initiation notification failed to address the different forms of sodium cyanide that are produced, sold, and imported and it seems the Authority has overlooked this important detail.
 - The product is sold in the market in powder, tablets and liquid form and the concentration varies. Prices of the product vary depending upon the form in which it is sold.
 - Authority did not seek comments from the interested parties on the need for PCN methodology.
 - UPL has faced problems on maintaining quality of the product as purity level of product has not been at 98% level.

C.2 Submissions made on behalf of the applicants.

6. The applicants have submitted as follows with regards to the product under consideration and like article:
- The product under consideration is sodium cyanide which is a moderately strong base. It is a poisonous compound with the formula NaCN. It is white and is a water-soluble solid.
 - The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 283711 of the Tariff Classification. However, in past, the product has also been imported under other sub-headings as well, such as 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 and 28371910.
 - All producers of the product produce first in liquid form. However, it is preferred to be transported in solid form considering the nature of the product, economics and difficulty in selling the product in liquid form.
 - The product is eventually consumed in liquid form after being dissolved in water to make a 30% solution. It is entirely irrelevant if the product is transacted in solid or liquid form.
 - The mere fact that sodium cyanide is also transported and used in liquid form does not make sodium cyanide in solid and liquid form different products.
 - The product manufactured by the applicants is 'like article' to the product being imported from the subject countries.
 - Emmennar Pharma Pvt. Ltd.'s claim that the applicants cannot provide the desired purity lacks merit. In fact, the purity content provided by the domestic industry exceeds 98%, matching the quality of imports. While the user previously did not source any material domestically, they have recently begun to partially shift their requirements to the domestic industry.

C.3 Examination by the Authority

7. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder.
8. As regards the submission that the applicants are unable to provide the product with 98% purity level as required by the user industry, the Authority notes that the applicants have provided sales invoices and certificate of analysis showing sales of the product with 98% purity. The applicants have additionally highlighted that Emmennar Pharma Private Limited has shifted its requirement from imports to domestic industry and while the respondent was earlier sourcing its entire requirement from imports but has now shifted some portion of its requirements to the domestic industry. In view of the above, the contention of the interested party that the applicants do not provide the product with the desired standard cannot be accepted.
9. With respect to the form of product being sold in the domestic market, it is seen that sodium cyanide is initially produced and ultimately consumed in liquid form. However, considering the nature of the product, ease of transportation and the economics involved, it is preferred to be converted into solid form i.e., in the form of tablets/briquettes for transportation purpose. The Authority through its clarification letter for the PUC & PCNs issued on 6th August 2023 clarified that the product under consideration is sodium cyanide, regardless of its form. Liquid form of sodium cyanide is nothing but just the product mixed with water. Liquid form can be converted into solid, and the solid form can be re-converted into liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form and liquid form produced by all producers are comparable in terms of all essential characteristics of the product.

10. As regards the contention that the Authority did not seek comments on the need for PCNs, it is noted that post initiation of the investigation letters were sent to all the interested parties, which clearly established the timelines of various submissions, including 15 days' time to file comments on PUC/PCNs. However, barring one interested party, Hebei Chengxin Co. Ltd., which submitted that PCN-wise analysis is not required in this case, none of the interested parties in the investigation availed the above opportunity and made any comments on the PCNs within the stipulated time. Hence, the Authority finds this contention to be totally baseless.
11. The product under consideration in the present investigation is sodium cyanide which is a moderately strong base. It is a poisonous compound with the formula NaCN. It is white in colour and is a water-soluble solid. Cyanide cation has a high affinity for metals, thus, attributing high toxicity to this base.
12. The product under consideration is used for extraction of gold and silver from their respective ores, in electroplating, heat treatment of metals (case hardening), manufacturing insecticides, dyes, pigments, bulk drugs and in many organic syntheses, agrochemicals, nylon intermediates, gelating compounds, ore flotation and pharmaceutical intermediates.
13. In view of the above, the Authority concludes that the scope of the product under consideration is sodium cyanide, regardless of its form. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 283711 of the Customs Tariff Classification. The product has also been imported under other sub-headings as well, such as 28371990, 28372090, 28372040, 28391100 and 28371910. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration or the levy of anti-dumping duty.
14. As per the information available on record, the Authority notes that the product produced by the domestic industry is like article to product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject countries in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Thus, the Authority concludes that the product manufactured by the domestic industry constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries in the terms of Rule 2(d).

SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

15. The other interested parties have submitted as follows with regards to the scope of domestic industry and standing:
 - a. HCC, UPL and Hindusthan Engineering & Industries Limited, the parent company of HCC, are habitual/regular importers and traders of the subject goods in substantial volumes, before, during and after the period of investigation.
 - b. The applicants have imported the PUC from the subject countries and traded it because of their inability to produce and supply due to regular stoppage of production on account of environmental issues, technical issues and regulatory ban on them from time to time.

D.2 Submissions made by the applicants.

16. The applicants have submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. The applicants are the only producers of the product under consideration in India.
 - b. HCC (formerly known as Cyanides & Chemicals Company) is a unit of Hindusthan Engineering & Industries Limited and has been engaged in the production of the product under consideration for more than 35 years.
 - c. UPL Limited had recently set up a new plant in India with an investment of Rs 500 cr. and has commenced its production of the product under consideration from April 2021.
 - d. Both the producers had imported the product under consideration in the past. While UPL imported for captive consumption before start of commercial production, Hindusthan Chemical Company imported in 2019-20 and 2020-21 for trading purpose to meet the customers requirements.
 - e. Imports by HCC were made in 2019-20 when its plant was shut down. These imports were from non-subject countries.
 - f. The applicants have not imported the product under consideration in the period of investigation.

- g. The applicants are not related to any of the producer/exporters in the subject countries or any importers of the subject goods in India.

D.3 Examination by the Authority.

17. The application has been filed by Hindusthan Chemical Company and UPL Limited.

18. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers".

19. As regards the submission of applicants being regular importers and traders, the Authority has examined transaction wise import data for the injury period and has found that the entire imports by HCC are in the period 2019-20 and 2020-21. There are no imports made by HCC in the period of investigation. Further, the parent company of HCC has also not imported any product in the period of investigation.

20. The table below shows the imports made by HCC over the years.

S. No.	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Imports from subject countries	MT	***	***	No imports	
2	Imports from non-subject countries	MT	***	***		
3	Imports in relation to subject countries imports	%	***	***		
4	Imports in relation to production	%	***	***		

21. Further, it has been submitted by the other interested parties that the parent company of HCC has imported the product in the period of investigation. The Authority notes that the transaction wise import data does not show any imports made by Hindusthan Engineering & Industries Limited in the POI.

22. It has been submitted that UPL imported in 2019-20 and 2020-21. The imports were made prior to commencement of commercial production by UPL. The Authority notes that there are no imports by UPL in the period of investigation.

23. The table below shows the imports made by UPL over the years.

S.No.	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Imports from subject countries	MT	***	***	No imports	
2	Imports from non-subject countries	MT	***	***		
3	Imports in relation to subject countries imports	%	***	***		
4	Imports in relation to production	%	No production			

24. The Authority notes that the interested parties' portrayal that the imports were being made by the applicants only due to shut downs cannot be accepted since the applicants have imported the subject goods in the past to primarily cater to the demand supply gap and to retain its customers. The Applicants have contended that there was no dumping in the years 2019-20 and 2020-21 and the imports by the applicants were at un-dumped prices.

25. The Authority is required to examine if an applicant has imported in such large volumes that its nature has turned to be of an importer or a trader. The Authority notes that both the applicants had imported in past to primarily cater to the Indian demand. However, one of the applicants has even undertaken substantial investment of Rs 500 cr. to set up a new plant for production of the PUC. The Authority is also required to examine if an applicant has imported the product under consideration in the period of investigation. The Authority notes that the applicants have not imported in the period of investigation.

The applicants have also certified that they are not related to any importer in India or exporter of the product under consideration in the subject countries. The Authority, therefore, concludes that the applicants satisfy the requirements of Rule 2(b) of the Rules.

26. The Authority further notes that HCC and UPL are the only producers in India and together constitute 100% of the total Indian production and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by other interested parties.

27. The other interested parties have submitted as follows with regards to confidentiality:
- The applicants suffer from excess confidentiality as relevant information has been kept confidential. Relevant information has not been given even in the indexed form.
 - Costing formats, price undercutting, price underselling, profitability in percentage and dumping margin have been claimed completely confidential.
 - The applicants have blackened the information on self-imports in the period of investigation.
 - Details of production being suspended have been claimed confidential.

E.2 Submissions made by the applicants.

28. The applicants have submitted as follows with regards to confidentiality:
- The applicants have not claimed any excessive confidentiality. Entire information has been disclosed as per Trade notice 10/2018 dated 7th September 2018.
 - The information given in the costing formats, price undercutting, price underselling and profitability is business sensitive information and is not amenable to summarization.
 - As regards the argument that the applicants have blackened the information on self-imports in the period of investigation, it is clarified that there are no imports in the period of investigation.

E.3 Examination by the Authority.

29. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).
30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of AD Rules, 1995 provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

31. The Hon'ble Supreme Court in Reliance Industries relied on its decision in Sterlite Industries (India) Ltd. V. Designated Authority. Sterlite Industries had emphasized upon the importance of confidentiality. In para 3 of said decision it was reaffirmed that:
- 3 confidentiality under Rule 7 is not something which must be automatically assumed. Of course, in such cases there is need for confidentiality as otherwise trade competitors would obtain confidential information which they cannot otherwise get. But whether information supplied is required to be kept confidential has to be considered on a case-to-case basis. It is for the Designated Authority to decide whether a particular material is required to be kept confidential.*
32. The Authority reviewed the confidential information submitted by the interested parties, evaluating the adequacy of the confidentiality claims. Upon finding the claims substantiated, the Authority has granted approval for the confidentiality requests where deemed necessary, thereby ensuring that such sensitive information remains undisclosed to other interested parties. In situations where it was feasible, entities that furnished confidential information were advised to provide ample non-confidential renditions of the confidentially submitted information. The Authority facilitated the distribution of the non-confidential versions of the evidence presented by various interested parties, instructing them to share these non-confidential versions of their submissions via electronic communication.
33. As regards the submission on HCC's production being suspended being claimed confidential, the Authority notes that the same was disclosed in the application and the written submissions filed by the applicants. Therefore, the contention is incorrect.
34. As regards information given in costing formats, on price undercutting, price underselling and profitability being claimed confidential, the Authority notes that the information relating to these parameters are business sensitive information which cannot be disclosed. The applicants were required to disclose the confidential information as per the Trade notice 08/2018 dated 7th September 2018 and the applicants have complied with the requirements.

MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Submissions made by the other interested parties

35. The other interested parties have submitted as follows with regards to miscellaneous issues:
- a. As per Trade Notice No. 04/2012 dated 23rd May 2012, applicants were required to circulate the information presented in the public hearing to the other interested parties one day prior. The applicants did not circulate the information.
 - b. The Authority had not given sufficient time for filing of comments or the exporter questionnaire response.
 - c. Authority has not given any opportunity to interested parties to suggest PCN methodology.
 - d. Since the product is sold in both solid and liquid form, they should form a basis of PCN, and the dumping margin and injury margin should be determined based on PCN methodology.
 - e. Information regarding the shutdown of plant of HCC by Gujarat Pollution Control Board has been deliberately suppressed by the applicants.
 - f. Interestingly, while there is no actual decline in prices, a new concept called 'prime cost' has been introduced by the applicants to confuse the Authority. As noted above, the applicant HCC has been earning supernormal profits both pre and post POI with huge contribution/profitability from the PUC. This contribution/profitability declined marginally in the POI because of temporary increase in the prices of the basic raw materials as stated above which is being camouflaged as impact of dumped imports by deliberately selecting a truncated period.
 - g. Domestic industry has selectively chosen this period as the period of investigation to paint a picture of injury where none existed. During this period, there was a temporary upsurge in prices of ammonia and caustic soda lye which has also caused a significant increase in import prices as well.

- h. Czech Republic accounts for less than three per cent of the total imports of the subject goods in India. The *de minimis* test as per Article 5.8 / Rule 14(d) is to be applied to a particular 'country' and not to a 'territory'. Therefore, of the only two producers in EU, (respondent from Czech Republic whose imports alone are not above de-minimis limit and 'CyPlus GmbH' from Germany whose imports alone are above the de-minimis limit) the imports from Czech Republic alone are to be considered.
- i. The Czech Republic's share in India's total imports of subject goods accounts for less than 3% of the total imports. The investigation should be terminated immediately if the share of imports from a country is less than 3% of the total imports into India.
- j. The application was originally filed against China PR, Japan, and Korea RP as evidenced from para no. 8 of the initiation notification and not against Czech Republic.

F.2 Submission made on behalf of the applicants.

36. The applicants have submitted as follows with regards to miscellaneous issues:

- a. Entirety of information provided by the applicants in the public hearing is part of the written submissions filed with the Authority and circulated with the other interested parties. The other interested parties had opportunity to comment on the same.
- b. Barring the year 2019-20 when HCC's plant was shut down due to government restrictions, there have been no other regulatory ban on the applicants.
- c. Information regarding plant shutdown by HCC is part of the application. The information has not been suppressed.
- d. Being unstable in nature due to its hazardous nature, the product cannot be exported in liquid form as it is and there are no imports of the product in liquid form. Therefore, there is no need for PCN methodology.
- e. As regards the contention that the period of investigation has been chosen selectively, a 12-month period is considered appropriate by global investigating authorities for examining dumping and injury. The applicants have suffered material injury in the period of investigation as well as the financial year immediately preceding it and it cannot be considered that it was a temporary phenomenon.
- f. The words used in Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 are 'country or territory'. The Rules cannot override the Act or restrict the ambit of the Act. The rules have to be consistent with the Act. The anti-dumping rules are framed under the Customs Tariff Act, 1975. The rules and law should be read as a whole and one provision should be construed with reference to other provisions so as to make a consistent enactment of the whole statute. When the term used in the Customs Tariff Act is country or territory, it cannot be interpreted that because the Rules use the word 'country', they restrict the scope of the law.
- g. The opposing interested parties have submitted that the domestic industry has introduced a new concept of "prime cost". It is seen that the prime cost has been calculated to evaluate the price trends over the years. It has been claimed that the import price has not moved in line with the changes in the cost of production. An examination of the evolution of the price has been consistently examined by the Authority. The factors considered to examine the evolution of price have varied from investigation to investigation based on the facts of the case. In cases where there has been no change in the raw material prices, the Authority has simply examined the import price over the years. In cases where the raw material price has fluctuated significantly, the Authority has compared the import price with the raw material prices. In the present case, all the parties have accepted that the prices of the raw materials and utilities have increased over the years. The interested parties have also argued that since UPL has recently begun commercial production, the cost of UPL will be higher on account of fixed costs. Therefore, a comparison of prime cost (Raw material Cost + Utility Cost + Direct Expense) with the landed price is appropriate since it does not take into consideration the fixed costs.

F.3 Examination by Authority

37. It has been submitted by the interested parties that the applicants did not circulate the information presented in the public hearing to the other interested parties one day prior to the hearing. The Authority notes that all the interested parties, including the applicants who presented their views in the oral hearing, were required to file whatever was orally presented in the form of written submissions. The other parties too had the opportunity to file their rejoinders to the information shared in the written submission. The Authority notes that no prejudice has been caused to any interested party since information which was presented orally but not provided to the Authority in written submissions/rejoinders has not been considered for the purpose of the present final finding.
38. As regards the submission of the interested parties that sufficient time was not provided to file comments or exporter questionnaire responses, the Authority notes that post initiation of the investigation letters were sent to all the interested parties, which clearly established the timelines of various submissions, including 15 days time to file comments on PUC/PCNs and further 15 days time to file the questionnaire responses upon finalization and publishing of the final PCN methodology.
39. The Authority further notes that barring Hebei Chengxin Co. Ltd., which submitted that PCN-wise analysis is not required in this case, none of the interested parties in the investigation availed the above opportunity and made any comments on the PCNs within the stipulated time. CyPlus GmbH sought exclusion of the PUC in the liquid form from the scope of the product under consideration.
40. The Authority issued a clarificatory letter regarding the scope of the product under consideration and the PCNs wherein it was informed to all the interested parties that the scope of the product under consideration is sodium cyanide, regardless of its form. It was further clarified that since no proposals were received for construction of PCNs hence, no PCN methodology is being adopted for the investigation and accordingly the interested parties were asked to submit questionnaire responses.
41. Interestingly, the Authority finds a concerning pattern of inconsistency and shifting arguments in the submissions made by Emmennar Pharma Pvt. Ltd. In its email dated 13th May 2023, Emmennar, while seeking extension of time to file questionnaire response, suggested that PCN determination might not be relevant in this case. Later in the submissions post the oral hearing it reversed its course, claiming a lack of communication on PUC/PCNs and asserting the necessity of a PCN methodology despite the fact that the Authority vide its letter of 6th August 2023, unambiguously clarified the product scope of the investigation and PCN methodology. The Authority recommends that interested parties should maintain consistency in their submissions.
42. The Authority, in view of the above, does not agree with the contentions of interested parties that sufficient time was not provided to them to suggest PCNs and file questionnaire responses.
43. The Authority notes that the Anti-Dumping Agreement (ADA) uses the term "country" within the *de minimis* context (Article 5.8). While the interested party suggests "country" and "territory" are distinct within the ADA, there's no clear legal distinction established.
44. The Authority also recognizes that both the EU and its member states individually are the members of WTO in their own rights and the words 'country' and 'territory' are used interchangeably for members of WTO. Hence, the EU being a member of WTO, the subject investigation has been initiated in respect of imports from European Union (EU) as 'the subject country' and not against individual countries within the EU. It is not in dispute that the Authority is entitled to initiate investigations in respect of EU. The EU itself has not contended in contrary. In this subject investigation, since imports originate from the EU as the subject country and are above *de-minimis* levels, therefore the contention of termination of case against an individual member within the EU does not hold merit.
45. It has been submitted by the other interested parties that the period of investigation has been selectively chosen by the applicants to build up a case for injury. The Authority notes that the period of investigation must be recent and should be long enough to reflect a representative picture of the industry's condition. A period of 12 months is considered sufficiently long enough to allow for proper assessment of trends. The Authority notes that the POI in the present case is a 12 month period which is in accordance with the Rules. It is also seen that the applicants suffered losses in the

POI as well as the year prior to that. None of the parties have established that there is no dumping of the product under consideration in the period of investigation. Hence the Authority finds it difficult to accept that the period of investigation has been selectively chosen to build up a case.

46. The opposing interested parties have claimed that the raw material prices have declined in the post period of investigation. It is noted that examination of post-POI data is not warranted in an original investigation unless factual circumstances warrant the same. It is noted that conclusions regarding dumping and injury is to be reached based on the POI data. It is only when conclusive evidence regarding the above cannot be based on the POI data, the post-POI data may be examined. However, the facts of the POI in the present investigation establish that the applicant has suffered injury during the POI and therefore, the question of examination of post-POI data does not arise.
47. The Authority notes that while it has been contended by the opposing interested parties that prime cost is a new concept, nothing in contrary has been provided by them to show that such comparison is not appropriate. The Authority notes that the concept of prime cost takes into consideration only the variable cost of production, i.e. raw material cost, utility cost, packing cost and consumables. Prime cost is not a new concept but is only a part of the total cost of production. The Authority is required to examine the price trend of imports over the year. When the global cost of production remains stable throughout the injury period, a simple import price examination should be sufficient. However, if costs of production have fluctuated, a broader analysis beyond just import prices can be undertaken. Since all the opposing interested parties have accepted that the raw material prices have increased in the injury period and have also contended that UPL is a new producer and will therefore have high fixed costs, the Authority, therefore, notes that comparing the import price with the prime cost will be an appropriate approach in the factual matrix of the case. The Authority has also compared the import price over the injury period with the monthly global raw material prices.
48. The Authority has examined the trend of yearly import prices over the injury period. Further, the same were compared with the costs directly associated with production of the product, i.e. prime cost (raw material cost, utility cost, packing cost and cost of consumable). The domestic industry had contended that since UPL is a new producer, prime cost may be considered for HCC alone, in order to avoid distortion due to different composition of the domestic industry over the injury period. The domestic industry calculated prime cost based on the data of HCC alone, but The Authority notes that injury analysis is required to be undertaken for the domestic industry as a whole and not just selectively based on constituents of domestic industry. The Authority has accordingly considered aggregate data for both HCC and UPL fair comparison purpose to analyse the impact of landed value vis-à-vis cost of the domestic industry as a whole.

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made by other interested parties.

49. The other interested parties have submitted as follows with regards to market economy treatment, normal value, and export price:
 - a. 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15(d).
 - b. Proper evidence has not been provided by the applicants for the calculation of the actual normal value.
 - c. The normal value calculation as done by the applicants is imaginary. If the normal value calculated was so high, there is no reason why the exporters would have sold at this price.
 - d. No evidence of adjustment to export prices has been provided by the domestic industry.
 - e. The comparison made by the applicants in the domestic prices of the exporters and the export price to India is based on the indexed data and cannot be relied upon. Draslovka has not engaged in the dumping of the product in the Indian market.
 - f. Normal value should be determined based on the cost of the most efficient domestic producer. The claim of the applicants that HCC cannot be considered for normal value is misleading.

- g. The applicants export the product at the same price in which the product is imported in the Indian market. This shows that there is no dumping, and the import price is the actual price.

F.2 Submissions made by the applicants.

- 50. The applicants have submitted as follows with regards to market economy treatment, normal value, and export price:
 - a. Even though the provisions of Article 15(a)(ii) have expired, WTO members are required to consider domestic prices or costs in China PR only if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product as per Article 15(a)(i), which the Chinese producers in the present case have not shown.
 - b. No verifiable evidence of the actual selling price or cost in a market economy third country is available for determining normal value for China PR.
 - c. The product is being produced majorly in the subject countries and the export prices from these countries to other countries also appear to be at dumped prices.
 - d. The producers in the subject countries were not dumping the product in the Indian market when there was a demand supply gap. The producers have started dumping their product in the market as soon as UPL started production.
 - e. As normal value for China PR cannot be determined on the basis of other parameters laid down under Annexure-I, Paragraph 7 of the AD Rules, the normal value is to be determined based on price actually payable in India.
 - f. No interested party has provided any information with respect to domestic price, cost of sales or export price in market economy country.
 - g. The only participating Chinese producer Hebei Chengxin Co. Ltd has not filed market economy treatment questionnaire.
 - h. Normal value cannot be determined based on cost of production of HCC alone as the company's plant being old has a depreciated, depreciation cost is low in cost of production, have no interest cost and the purchase price of natural gas for the company is in not reflective of the market prices.
 - i. Nippon Soda Limited and Sojitz Corporation Limited, Japan had filed a letter withdrawing its exporter questionnaire response. Therefore, Authority is requested to apply adverse facts.
 - j. There is no response from Korea RP in the present investigation and the claims of the domestic industry with respect to dumping from Korea RP are undisputed.
 - k. Information regarding raw material and natural gas prices in the subject countries have been provided by the applicants as part of its non-confidential version of the application for the purpose of calculating actual normal value.
 - l. Evidence of ocean freight has been provided by the applicants within the application while other adjustments have been provided as per the standard adjustments allowed by the Authority.
 - m. Exporters are selectively dumping the product in the Indian market. Analysis of trend of the prices as per the non-confidential response shows that they have increased the prices in their domestic market and other countries.

F.3 Examination by the Authority

- 51. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses: -
 - a) Hebei Chengxin Co. Ltd., China PR.
 - b) Lučební závody Draslovka a.s. Kolín., European Union.
 - c) Nippon Soda Co. Ltd. and Sojitz Corporation, Japan.

F.3.1 Pricing pattern of the participating producers from the subject countries.

52. The Authority has examined the domestic selling prices and the export prices of the participating producer over the injury period.
53. The information regarding the domestic selling price and the export price of the Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, European Union is given in the table below.

S.No.	Particular	UOM	2019	2020	2021	POI
A	Domestic					
1	Sales volume	MT	***	***	***	***
2	Sales value	USD'000	***	***	***	***
3	Price	USD/MT	***	***	***	***
4	Price	Trend	100	100	96	136
B	Export					
1	Sales volume	MT	***	***	***	***
2	Sales value	USD'000	***	***	***	***
3	Price	USD/MT	***	***	***	***
4	Price	Trend	100	103	87	99

54. It is seen from the questionnaire response filed by the producer that while its domestic sales price has increased over the period and more importantly in the period of investigation, the export price to India has declined.
55. Examination of the price trend over the years shows that the sharp price decline has been selectively in case of the Indian market when UPL set up its plant and the demand supply gap was bridged.

F.3.2 Normal value and export price for the subject countries.

56. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.3.3 Normal value and export price for China PR.**F.3.3.a Normal value for China PR****Market Economy Status for Chinese Producers**

57. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

58. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per the provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

59. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/ information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines ds not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WO member country during the three year period preceding the

investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment in compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

60. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
61. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country. The Authority notes that it is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. Since neither the applicants nor the interested parties have provided any verifiable information, the normal value could not be determined on this basis. Therefore, the normal value for China PR has been determined based on price actually paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the cost of production in India after addition for the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits.
62. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

F.3.3.b Export price for China PR

Export price for co-operative producer – Hebei Chengxin Co. Ltd.

63. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, credit cost and inland transportation.
64. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. The export price so determined is given below in the dumping margin table.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

65. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4 Normal value and export price for European Union.

66. CyPlus GmbH and Lučební závody Draslovka a.s. Kolín have registered as interested parties. However, CyPlus GmbH did not file a questionnaire response and has been treated as non-cooperative.

F.3.4.a Normal value for European Union**Normal value for co-operating producer - Lučební závody Draslovka a.s. Kolín**

67. The producer has reported domestic sales of *** MT in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The claims made have been accepted. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value for non-cooperating producers.

68. The normal value for non-cooperative producers/exporters from the European Union has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.4.b Export price for European Union**Export price for co-operating producer - Lučební závody Draslovka a.s. Kolín**

69. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, credit cost, commission and inland transportation.
70. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

Export price for non-co-operative exporters/producers.

71. The export price for non-cooperative producers/exporters from the European Union has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5 Normal value and export price for Japan.

72. Nippon Soda Co. Ltd. has filed a questionnaire response. However, pursuant to the oral hearing, the respondent filed a letter withdrawing its questionnaire response. The letter dated 15th December 2023 reads as below: -
- i. We are writing this letter to inform the Authority that Nippon Soda Co. Ltd., is withdrawing its participation from the subject anti-dumping investigation.
 - ii. Management of Nippon Soda Co. Ltd. has now taken a decision that it will withdraw participation from this anti-dumping investigation as it will not be possible for Nippon Soda Co. Ltd., to export sodium cyanide to India from April 2024 due to rapidly changing business environment.
73. The producer has accordingly been treated non-cooperative. Therefore, the normal value and export price has not been determined based on the data provided by the respondent. Hence, it is noted that there is no participating producer from Japan.

F.3.5.a Normal value for Japan

74. The normal value for Japan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.5.b Export price for Japan.

75. The net export price for Japan has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price has been calculated from the customs data. Since the data reported is at CIF level, adjustments have been made for ocean freight, marine insurance commission, inland freight, port expenses and bank charges. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6 Normal value and export price for Korea RP.

76. Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea RP had registered as an interested party. However, the producer did not file a questionnaire response. Therefore, the producer has been treated as non-cooperative. It is noted that there is no participating producer from Korea RP.

F.3.6.a Normal value for Korea RP.

77. The normal value for Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.6.b Export price for Korea RP.

78. The net export price for Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price has been calculated from the customs data. Since the data reported is at CIF level, adjustments have been made for ocean freight, marine insurance commission, inland freight, port expenses and bank charges. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.7 Dumping margin.

79. Based on the normal value and export price determined above, the dumping margin for the participating and non-participating producers has been determined and is shown below.

SN	Particular	Normal value USD/MT	Net export price USD/MT	Dumping margin USD/MT	Dumping margin %	Dumping margin Range
1	China PR					
a	Hebei Chengxin Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
b	Any other	***	***	***	***	70-80
2	European Union					
a	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín	***	***	***	***	100-110
b	Any other	***	***	***	***	120-130
3	Japan					
a	Any other	***	***	***	***	30-40
4	Korea RP					
b	Any other	***	***	***	***	20-30

80. The Authority notes that an inadvertent typographical error occurred in the disclosure statement in mentioning the ‘dumping margin range’ of the producer Lučební závody Draslovka a.s. Kolín as well as ‘any other producer’ from the European Union. The dumping margin range has now been corrected in the above table in these final findings.

EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**G.1 Submissions made by other interested parties.**

81. The other interested parties have submitted as follows with regards to injury to the domestic industry:
- There is no increase in imports from the subject countries in absolute terms or relative to production or consumption in India.
 - Analysis of “unnecessary imports” does not have any basis either in the Act or AD Rules. The increase in imports should be examined objectively in absolute terms or in relation to production or consumption in India.
 - Imports from the European Union cannot be a cause of injury. Imports from the European Union have declined at a much higher rate as compared to other countries.
 - Cumulative assessment of imports from EU with imports from other countries is not justified as EU prices are 10% higher than Chinese prices, 6% higher than the average price and 13% higher than the import prices from other countries. Price undercutting is negative for the European Union.
 - Imports from Japan cannot be a cause of adverse price impact as the imports from China were in major proportion whereas the imports from Japan were only 10% of the market share.
 - The price undercutting has declined over the injury period. Losses in 2021-22 cannot be due to imports from the subject countries when the volume of imports came down significantly.
 - Production of the domestic industry has increased throughout the injury period. It has increased by 537% in the period of investigation as compared to the base year.
 - The domestic industry has not explained the reason for the increase in cost of sales. The change in cost is because of a temporary rise in raw material prices and capacity addition.

- i. UPL has been exporting products under consideration from December 2021 at prices much below the price at which goods are imported from the subject countries.
- j. As UPL has set up a new unit, the Authority should undertake a separate injury analysis for it and compare its actual information with the projection.
- k. Actual capacity utilization of UPL cannot be considered for determining NIP since UPL is a new producer.
- l. Quarterly utilization over the period of investigation should be adopted for raw material cost and cost of utilities for determination of NIP.
- m. Injury parameters are impacted due to startup operations and inefficiency of UPL.
- n. The mindless enhancement in capacity is causing injury to the domestic industry. The production capacity is much higher than the demand of the subject merchandise in India.
- o. The applicants have requested injury determination to be considered after including captive consumption as well. The Authority should adopt that methodology which is permissible under the AD Rules, and which is consistently being followed.
- p. The domestic industry's request for more than 22% return on capital employed for NIP should be rejected because 22% is already high and was fixed as a standard when the interest rates were very high.
- q. The domestic industry has already captured a major share of demand as the imports have drastically decreased.
- r. The closing stock of the domestic industry has declined by 62% in the period of investigation as compared to the immediately preceding year.
- s. The increase in stock is due to (a) HCC's production suspension for regulatory reasons, (b) UPL setting up a new plant and (c) imports of massive quantity by HCL.
- t. The domestic industry has selectively chosen the period of investigation to paint a picture of injury where none existed. During this period, there was a temporary upsurge in prices of ammonia and caustic soda lye which had also caused a significant increase in import prices as well.
- u. Shutdown of HCC's plant and COVID-19 lockdown took place during the first quarter of 2021-22 and have negatively affected the business, sales, and profits.
- v. Shutdown of the UPL plant was also not because of the dumped imports since the imports had declined when UPL had first started its production.
- w. Injury might be due to high depreciation and interest cost.
- x. Demand for imports is guided by various other factors including prices, technology, quality, timely supply, etc.
- y. Import price from European Union are 10% higher than Chinese prices and 6% higher than the average price. Further, the import prices from European Union remained stable throughout the period of investigation.
- z. Price undercutting is negative for European Union.
- aa. The market share of the applicants has increased by 550% and the import share has declined to a mere 9% and yet the applicants have claimed injury on account of these imports.
- bb. The capacity of the applicants has increased by 637% in just one year. Similarly, production and domestic sales have increased by 496% and 431%. The applicants expect the capacity to be fully utilised within one year. The Authority has initiated this investigation based on such an absurd argument/claim.
- cc. Temporary stock piling is also due to import of massive quantity by HCC. The company's capacity utilization and market share were close to 90%.
- dd. The injury parameters are adversely impacted due to startup operations of UPL and inefficiency of the applicants.
- ee. As required under Article 3.5, in completing an adequate "non-attribution" analysis, the investigating authority must ensure that injury caused by any other known factors is not wrongly attributed to the dumped imports. As a result, they must "separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors".

- ff. The comparison of the export price and domestic selling price is inappropriate since the claim is based on indexed numbers. The export price to India is higher than the domestic selling price during the base year.
- gg. The increase in price of raw material has been abnormal and temporary in nature. The raw material prices have started normalizing in the post period of investigation.
- hh. The rise in raw material prices was due to Russia-Ukraine war. The decline in delta is due to several factors which do not account for dumping.
- ii. The claim by the domestic industry to calculate non injurious price on domestic production and not on domestic merchant sales is baseless since the duty protection is available for domestic sales and not captive consumption. While calculating the NIP, more weightages should be given to HCC since its share in the domestic sales is significant as compared to UPL.
- jj. The reason for decline in delta was because the raw material prices were at an all-time high and not because of dumping by the producers in the subject countries.
- kk. The imports were needed due to demand and supply gap. Considering the shutdown of the plant of UPL, there was a demand and supply gap of at least 35%.
- ll. The argument of the domestic industry that the delta has declined was due to the fact that the raw material prices increased globally in the period of investigation. The raw material prices have declined again in the post period of investigation.
- mm. The methodology proposed by the applicants to calculate price undercutting based on same profit as in the past is incorrect as price information is required to be considered based on the accounting records.
- nn. UPL plant faced disruptions as they imported secondhand plant from China PR with glass reactors. It has replaced some glass line reactors but is still struggling with the second-hand inefficient machines.

G.2 Submissions made on behalf of the applicants.

82. The applicants have submitted as follows with regards to injury to the domestic industry:
- a. A cumulative assessment of imports from the subject countries is required as requirements of Annexure II (iii) of the AD Rules have been satisfied.
 - b. Imports from subject countries declined with HCC's plant becoming operational in 2019-20 and commencement of production by UPL in 2021-22 thereby closing the demand-supply gap.
 - c. If the imports necessary due to the demand-supply gap are removed, the imports from the subject countries have increased very significantly in the period of investigation.
 - d. The exporters from the subject countries have not increased their export prices in line with the increase in the prime cost resulting in significant dumping.
 - e. The landed price of imports in the period of investigation is below the selling price of applicants resulting in positive price undercutting despite company selling the product at losses.
 - f. As regards the submission that the price undercutting has declined, a decline in price undercutting shows increasing competition between the domestic and imported products. The price undercutting has declined because the domestic industry is selling at losses. Had the domestic industry not sacrificed profits, the price undercutting would have been higher.
 - g. The imports have had a suppressing impact on the prices of the applicants in the period of investigation and price depression over the injury period.
 - h. While capacity in India was sufficient in 2021-22 and the period of investigation to meet the demand, the increase in production was much less than the demand-supply gap in the same period due to dumping from the subject countries.
 - i. Profitability has declined significantly in 2021-22 and the period of investigation.
 - j. The applicants are bleeding financial losses and a negative return on capital employed in the proposed period of investigation.
 - k. Cash profits of the applicants have significantly declined over the injury period.
 - l. The market share of the applicants is below the level to which it can cater.
 - m. The inventory with the applicants has increased over the injury period. The decline in inventories to some extent in the period of investigation is a result of suspension of production to contain inventories.

- n. Even at the normated cost of production, the applicants are suffering losses, cash losses and negative return on capital employed.
- o. If changes in prime cost are taken into consideration, the import price is at least 20% below the price it should have been.
- p. The applicants have recorded significantly negative and adverse growth.
- q. While UPL has recently invested more than 500 Cr. in the product, no producer would want to invest in their business considering the current performance.
- r. Injury to the domestic industry is not because of any other factors but rather due to dumped imports from the subject countries.
- s. The decline in demand is not a cause for injury as demand for the subject goods has increased over the injury period.
- t. Imports from the subject countries hold 39% share in the Indian demand in a situation where the demand in the country was only 85% of the capacity of the domestic industry. The imports were preventing utilisation of production capacities and caused adverse volume effects on the Indian industry.
- u. While delta between import price into India and raw material prices was more than 1600 USD/MT before UPL commenced production, the delta steeply declined post the commencement of production. Delta towards end of the period of investigation was only 300 USD/MT.
- v. The period of investigation saw a steep increase in the prime cost of more than Rs 34,000 per MT but the increase in import price was only Rs 8000 per MT.
- w. Had the domestic industry kept the same profit per unit as was being earned in the base year, the price undercutting would have increased in the period of investigation to a staggering level of 54%.
- x. As regards the submission of Emmennar Pharma Pvt. Ltd. on demand for imports being guided by various other factors, Emmennar Pharma Pvt. Ltd. has partly started sourcing its requirements from UPL in 2021-22 and the period of investigation. Therefore, the contention cannot be accepted.
- y. The quality of material supplied by the domestic industry is better as UPL's technology is superior to exporters.
- z. The lead time of the domestic industry is lower than that of the exporters.
- aa. The inventory as % of sales have increased over the injury period. The inventory as % of sales have declined in the period of investigation only because UPL decided to suspend production for some time in the period of investigation to ease off rising inventories.
- bb. As regards the argument on export sales made by UPL at same prices in which the product is imported, UPL has been forced to export the product under consideration from December 2021 because of difficulty in selling the same in the Indian market because of dumped imports. UPL is suffering in exports as well.
- cc. As regards high finance costs being a cause of injury, the interest cost charged in the cost of production is nil in the case of HCC and less than 0.1% in the case of UPL.
- dd. As regards depreciation being a cause of injury, the cost of production as depreciation cost is insignificant. The domestic industry is suffering at the normal cost of production as well.
- ee. As regards the argument that the domestic industry is suffering due to inherent issues, the domestic industry would have been profitable had the exporters adjusted their prices in line with the change in the prime cost.
- ff. While the injury analysis is required for the domestic industry as a whole and not selectively for only one of the participating producers, an analysis of the individual performance of the domestic industry will show that both the producers are suffering injury.
- gg. HCC has been producing for more than 20 years and the plant is highly depreciated. A return on capital employed of 22% will not be reasonable for NIP calculation. 22% would imply a profit which will be insufficient to cover any future interest cost, fresh investments, and taxes. The Authority may consider past profits as a basis to determine the non-injurious price.
- hh. Had HCC procured natural gas at market prices, it would have suffered losses.

- ii. UPL Limited has achieved a capacity utilization of 90% in the injury period and the Authority may consider it for calculation of its non-injurious price. For UPL, 22% return on capital employed can be considered for NIP calculation as it is a new plant and requires complete protection from dumping.

G.3 Examination by the Authority

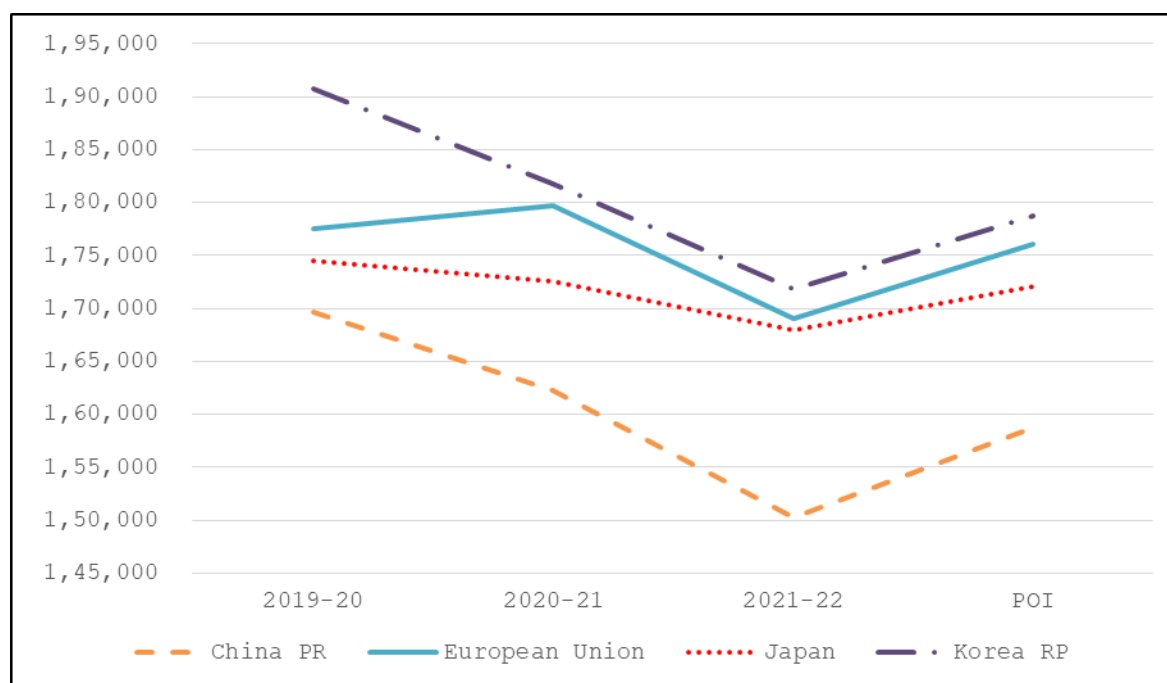
- 83. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 84. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters.
- 85. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.

Cumulative assessment of imports.

- 86. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 87. The Authority notes that:
 - a. Imports of the product under consideration from China PR, European Union, Japan and Korea RP are at dumped prices.
 - b. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules.
 - c. The volume imports from these countries are above the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules.
- 88. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined: -
 - a. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.
 - b. Domestically produced products and the imported products are interchangeable. Consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
 - c. There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products.
 - d. Import price from the subject countries have moved in tandem with each other.
- 89. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that the domestic producers and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both products are being used by the consumers interchangeably. The same has also been ascertained by the Authority through DG Systems data.

90. The table and graph below show the import price from the subject countries.

SN	Country Name	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	China PR	Rs/MT	1,69,695	1,62,204	1,50,208	1,58,735
2	European Union	Rs/MT	1,77,584	1,79,751	1,69,072	1,76,036
3	Japan	Rs/MT	1,74,554	1,72,545	1,67,900	1,72,113
4	Korea RP	Rs/MT	1,90,699	1,81,723	1,71,896	1,78,771



91. A comparison of the import prices in the period of investigation with the prices in the base year show that the import prices from all the subject countries have declined. Similarly, when the prices in the period of investigation are compared with the prices in the immediately preceding year, the import price from all the subject countries have shown a marginal increase. The Authority also notes that the average yearly import prices may not necessarily be at exact similar level due to monthly changes in the prices, however, the overall trend of the import prices shows that they have moved in tandem.
92. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

Separate assessment of imports from European Union and Japan.

93. It has been submitted by the opposing interested parties that imports from European Union and Japan have declined and they are not a cause of injury. The Authority notes that all the conditions of cumulation as provided in Para (iii) of Annexure II of the AD Rules are satisfied in the present case. A mere decline in import volume from one source does not justify de-cumulation of imports and the segregated analysis of injury from different sources. It is also seen that the import prices have shown decline from each of the subject countries. It is also seen that the average import price from EU and Japan were lower than that from Korea. The Authority has examined the transaction wise data and found that the importers are interchangeably importing from these sources. Therefore, there is no merit in the contention that imports from European Union and Japan should be de-cumulated and assessed separately.

Calculation of non-injurious price.

94. The domestic industry has requested for consideration of profits for the year 2020-21 as a basis for determination of non-injurious price for HCC. Further, the other interested parties have requested for determination of non-injurious price of UPL based on quarterly utilization of the plant. The Authority has, however, determined the non-injurious price based on the Annexure-III of the Rules and the consistent practice followed by the Authority. The Authority has not accepted the request of the domestic industry for considering the past return on investment earned by HCC for fixation of its NIP.

Separate injury analysis for UPL and HCC.

95. The interested parties had requested for a separate injury analysis for UPL and HCC considering that UPL has set up a new unit. The Authority also notes that a request of analysis of injury separately for the two entities shall be contrary to law and rules as the requirement is for injury examination for domestic industry as a whole and not selectively for each constituent of the domestic industry. Notwithstanding the above, the Authority notes that both the companies have faced deterioration in performance both cumulatively and individually.

Performance of UPL based on normations.

96. It has been submitted by the interested parties that the since UPL is a new producer, the injury examination should be undertaken based on normation as well. The Authority notes that there is no legal basis for this. Comparison with normations is required for cases where the domestic industry does not have production over the entirety of injury period. In the present case, the Authority has examined if the dumped imports are causing any material injury to the domestic industry. Therefore, the comparison with projections will not be appropriate.
97. However, in light of the submissions made, the Authority has also analysed the performance of the domestic industry at normated cost of production[#] (by considering highest capacity utilisation of UPL over the injury period) to see if the injury can be attributed to start up operations or low capacity utilisation. The table below shows the performance of the domestic industry over the injury period at optimum level.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	88	76	81
2	Cost of production	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	76	106	131
3	Profit per unit	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	110	21	-12
4	Profit in Rs Lakhs	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend		100	237	84	-53
5	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend		100	237	84	-52
6	Cash profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend		100	216	103	-9
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend		100	84	7	-7

As provided by the applicants

98. The analysis of performance of the domestic industry at normated cost of production indicates that the domestic industry would suffer losses even at normated costs.

Export prices of UPL in line with import prices.

99. It has been submitted by the opposing interested parties that UPL is exporting at the same prices at which it is being imported. The domestic industry, however, has submitted that the exports are completely unwarranted and purely to dispose of the inventory which UPL was unable to sell in the domestic market at remunerative prices. It is seen that the export price is much below the price at which the domestic industry has sold in the domestic market. This itself substantiates the claim of the domestic industry that the sales were made to dispose of the inventory. The fact that the producer was forced to export at significantly low and unremunerative prices is a reflection of the injury caused to the domestic industry due to the dumped imports.

Issues with UPL plant.

100. It has been submitted by other interested parties that UPL purchased a second hand plant and the plant issues lead to regular shutdowns. The issue was examined during the physical verification of at the premises of UPL. It was clarified by UPL during the on-site verification that the plant was a newly installed plant by the

company. It has also been submitted by UPL that the shutdowns undertaken were only because of the idle inventory lying and not due to any issues in the plant.

G.3.1. Assessment of demand.

101. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. Further, demand has been determined twice – once excluding and then including captive consumption of the domestic industry.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Domestic sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend		100	216	396	431
2	Import from subject countries	MT	14,189	12,544	8,586	6,272
3	Import from other countries	MT	1,776	421	180	180
4	Demand (excluding captive)	MT	***	***	***	***
	Trend		100	98	97	89
5	Captive consumption*	MT	***	***	***	***
6	Demand (including captive)	MT	***	***	***	***
	Trend		100	98	117	111

102. The total demand/consumption in India declined in 2020-21 due to outbreak of COVID but increased thereafter in 2021-22. The demand has declined again marginally in the period of investigation.

G.3.2. Volume effect of dumped imports

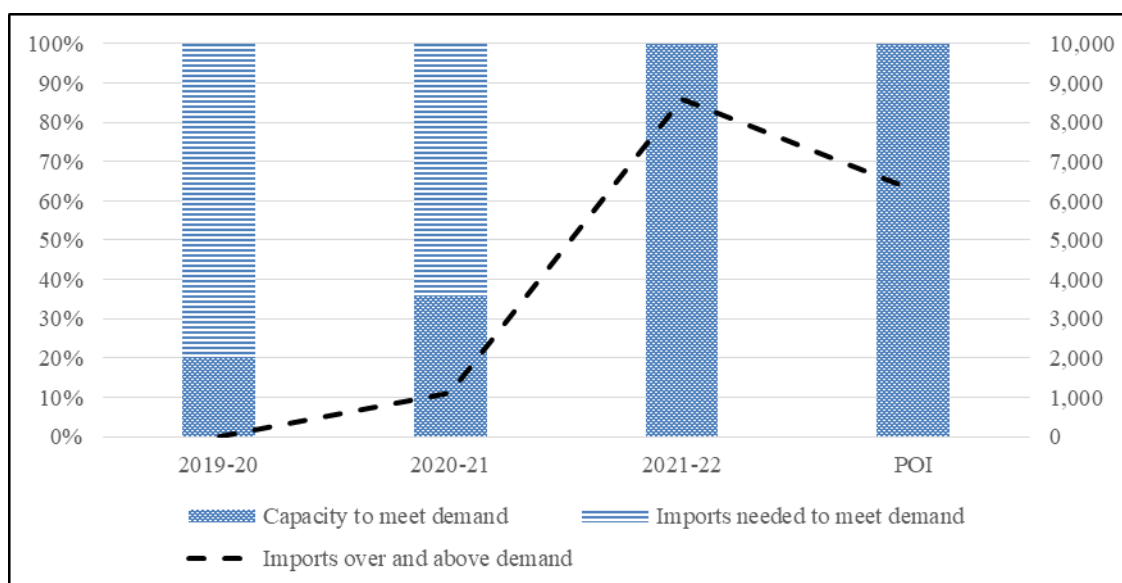
103. The effect of the volume of dumped imports from the subject countries has been examined in order to ascertain whether imports have increased either in absolute terms or in relation to production or consumption in India.
104. The volume of imports from various countries in absolute terms and in relation to production and consumption is as under:

S.No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Imports from subject countries	MT	14,189	12,544	8,586	6,272
2	Subject countries import in relation to: -					
A	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend		100	36	11	9
B	Demand (including captive)	%	***	***	***	***
	Trend		100	90	52	40
C	Total Imports	%	89%	97%	98%	97%

105. It is seen that the imports from the subject countries have declined in absolute terms and relative to production and consumption over the injury period.
106. The Authority has examined the situation of decline in import with regard to demand for the product and supply by the Indian industry. The table below shows the imports over the injury period, the capacity with the Indian industry and the demand in the country.

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Demand in India	MT	***	***	***	***
2	Capacity of domestic industry	MT	***	***	***	***
3	Gap in demand and supply	MT	***	***	No gap	No gap
4	Imports from subject countries	MT	14,189	12,544	8,586	6,272

5	Import above demand-supply gap	MT	***	***	8,586	6,272
---	--------------------------------	----	-----	-----	-------	-------



107. It is seen that, there was a large demand and supply gap in the country in the year 2019-20 and 2020-21 and therefore, the users had no option but to meet their requirements through import. However, with the commencement of production by UPL in 2021-22, the demand supply gap in the market was bridged. In fact, the installed capacities with the Indian industry are now higher than the demand for the product in the country. Therefore, while the imports in the past were necessary to cater the demand for the product in the country, the imports from the subject countries are now in competition with the capacities in India. It is also seen that UPL has sold at losses to increase its market share.

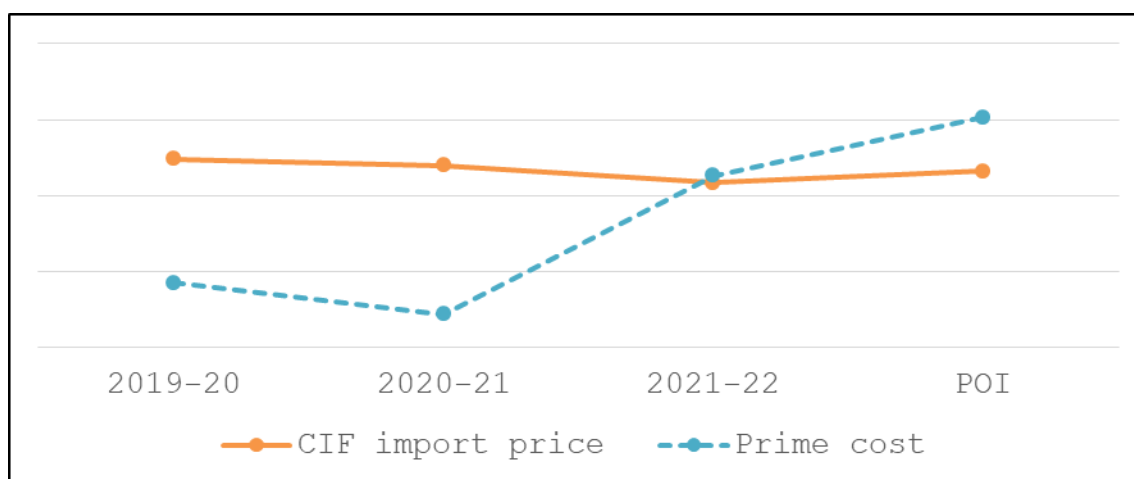
G.3.3. Price effect of dumped imports

108. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

a. Evolution of prices.

109. The Authority has compared the trend of import prices with the costs directly associated with production of the PUC, i.e. prime cost (raw material cost, utility cost, packing cost and cost of consumable). The domestic industry had contended that since UPL is a new producer, prime cost may be considered for HCC alone, in order to avoid distortion due to different composition of the domestic industry over the injury period. The Authority notes that injury analysis is required to be undertaken for the domestic industry as a whole and not just selectively based on constituents of domestic industry. The Authority has accordingly considered aggregate data for both HCC and UPL also.

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	CIF import price	₹/MT	1,74,216	1,69,958	1,58,414	1,66,001
	Trend		100	98	91	95
2	Prime cost	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	78	177	218



110. It is seen that in the year 2019-20, there was a significant gap between the import price and the prime cost of the applicants which further increased in the year 2020-21. However, in 2021-22 the prime cost has increased whereas the import price has declined. While the prime cost has further increased in the period of investigation, the import price has remained at almost the same level which is below the prime cost.

111. The domestic industry has provided information regarding monthly international price of the raw materials and the import price into India. Further, the domestic industry quantified the difference between CIF import price for the subject goods and costs on account of ammonia and caustic soda. The table below shows the factual position.

S. No.	Month	Ammonia USD/MT	Caustic soda USD/MT	Natural gas USD/MT	Import price. USD/MT	Difference USD/MT
1	2019-M04	361	212	417	2,461	1,717
2	2019-M05	337	227	414	2,556	1,816
3	2019-M06	315	206	394	2,515	1,824
4	2019-M07	301	194	405	2,513	1,831
5	2019-M08	293	202	397	2,499	1,822
6	2019-M09	307	189	417	2,458	1,766
7	2019-M10	326	187	366	2,483	1,824
8	2019-M11	340	199	414	2,493	1,776
9	2019-M12	329	186	405	2,466	1,774
10	2020-M01	325	176	391	2,414	1,744
11	2020-M02	333	152	400	2,470	1,808
12	2020-M03	327	155	409	2,460	1,792
13	2020-M04	333	155	379	2,363	1,716
14	2020-M05	300	173	350	1,588	969
15	2020-M06	297	191	312	2,364	1,764
16	2020-M07	268	179	271	2,309	1,772
17	2020-M08	281	171	210	2,317	1,829
18	2020-M09	282	162	217	2,266	1,780
19	2020-M10	318	146	241	2,214	1,699
20	2020-M11	321	145	261	2,248	1,714
21	2020-M12	331	150	316	2,102	1,513
22	2021-M01	333	137	336	2,210	1,615

23	2021-M02	371	131	342	2,242	1,623
24	2021-M03	439	143	325	2,219	1,564
25	2021-M04	580	151	306	2,125	1,393
26	2021-M05	629	157	378	2,089	1,263
27	2021-M06	632	176	332	2,078	1,271
28	2021-M07	664	186	418	1,952	1,046
29	2021-M08	716	193	486	2,087	1,088
30	2021-M09	725	213	407	2,017	1,061
31	2021-M10	768	228	467	1,963	918
32	2021-M11	858	276	651	1,956	664
33	2021-M12	999	320	668	2,262	833
34	2022-M01	1,256	303	677	2,204	627
35	2022-M02	1,288	309	548	2,352	858
36	2022-M03	1,274	356	725	2,300	628
37	2022-M04	1,588	365	765	2,155	251
38	2022-M05	1,707	383	656	2,158	259
39	2022-M06	1,338	414	703	2,345	604
40	2022-M07	1,294	404	828	2,244	433
41	2022-M08	1,300	409	951	2,094	174
42	2022-M09	1,321	406	1,017	2,354	367

112. It is seen that the difference between the import price of the product under consideration and the costs on account of raw material have declined sharply. While the difference averaged to 1800 USD/MT in 2019-20, the same has declined to around 400 USD/MT towards the end of the period of investigation.

b. Price undercutting

113. The table below shows the comparison between the landed price of imports and the selling price of the imports in the period of investigation.

S. No.	Particulars	Net selling price Rs/MT	Landed price Rs/MT	Price undercutting	
				Rs/MT	%
1	China	***	1,71,831	***	0-10%
2	Japan	***	1,72,113	***	0-10%
3	Korea	***	1,78,771	***	0-10%
4	EU	***	1,90,559	***	(0-10)%
5	Subject countries as a whole	***	1,73,637	***	0-10%

114. It is seen that the price undercutting is positive in respect of all the subject countries, barring EU. Further, the weighted average price undercutting is positive.

115. It has been contended by the other interested parties that the price undercutting has declined over the injury period. It is noted as per Annexure-II of AD Rules, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India. However, the applicants have submitted that high price undercutting in the past and low price undercutting in the present period shows relatively much lower competition between the domestic industry and imports in the

past and high degree of competition in the present period. The producers in subject countries did not align their prices to the changes in the prime costs which forced the domestic industry to bridge the gap between the prices of the domestic and imported product in order to sell the material and sustain in the market.

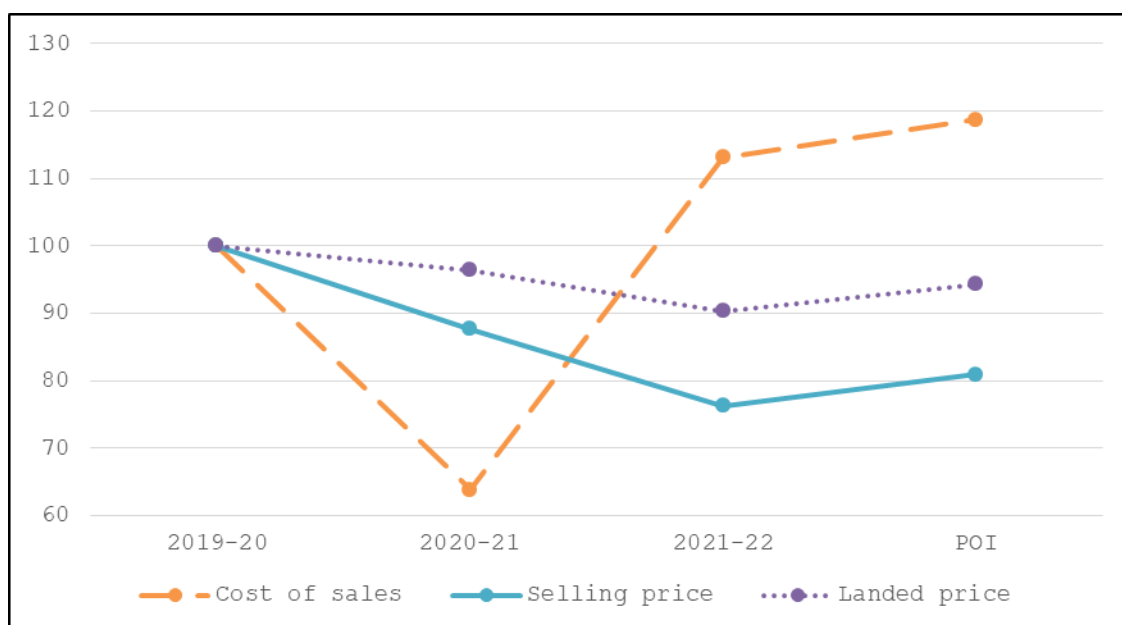
116. The domestic industry has further highlighted that had it sold at same profitable prices as in the base year, the price undercutting would have been higher. The same has been depicted in the table below.

SN	Particulars	UOM	2019-20	Period of investigation	
				Actual	If profit was retained
1	Selling price	Rs/MT	***	***	***
2	Landed price	Rs/MT	***	***	***
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
4	Price undercutting	%	20-30%	0-10%	40-50%

c. Price suppression/depression

117. The table below shows the change in the cost of sales, selling price and landed price of imports.

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
3	Landed price	₹/MT	1,84,077	1,77,443	1,66,368	1,73,637
	Change					
1	Cost of sales	₹/MT		***	***	***
2	Selling price	₹/MT		***	***	***
3	Landed price	₹/MT		-6,634	-11,075	7,269
	Trend					
1	Cost of sales		100	64	113	119
2	Selling price		100	88	76	81
3	Landed price		100	96	90	



118. It is seen that in the year 2020-21, the cost of sales declined by around Rs *** (by 36 index points) per MT whereas the selling price declined by Rs *** (12 index points) per MT. The domestic industry was profitable till 2020-21 and therefore, the imports were not having any suppressing/ depressing impact on the prices of the domestic industry. It has also been submitted that the cost in 2019-20 were higher because the plant of one of the producers (HCC) was shutdown.
119. In the year 2021-22, the cost of sales increased by Rs *** per MT (49 index points) but the selling price declined by Rs *** per MT (12 index points). The increase in the cost of sales was due to raw material cost. This period also saw a decline in the landed price of imports by Rs 9,674 per MT (6 index points). The landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry. The domestic industry suffered losses in this period. It has been stated by the domestic industry that this was the period when UPL started commercial production and the exporters started dumping in the Indian market.
120. The cost of sales has further increased by Rs ***per MT (7 index points) and the selling price increased by Rs ***per MT (5 index points). However, the import price did not increase in the same proportion. It only increased by 7,269 per MT (4 index points). Resultantly, the gap between the cost of sales and the landed price of imports widened and the domestic industry was prevented from increasing its prices in the same proportion. Therefore, the imports had a suppressing impact on the prices of the domestic industry in the period of investigation.

G.3.4. Economic parameters relating to the domestic industry.

a. Capacity, production, domestic sales and capacity utilization

121. The table below shows capacity, production, capacity utilisation, domestic sales, export sales and captive consumption.

S. No.	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend		100	171	637	637
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend		100	247	544	496
3	Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Trend		100	144	85	78
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	216	396	431
5	Export sales	MT	***	***	***	***

	Trend		-	-	100	633
6	Captive consumption	MT	***	***	***	***
	Trend		-	-	100	114

122. It is observed that: -

- a. The plant of HCC was shut down for 5 months in 2019-20. The capacity of HCC has been considered to that extent.
- b. UPL started commercial production in 2021-22 with an investment of Rs 500 cr.
- c. The capacity of the domestic industry has increased over the injury period and is sufficient to cater the entire demand in the country. The demand in the country is around 85% of the capacity.
- d. With the increase in the capacity of the domestic industry, the production also increased in 2020-21 and thereafter in 2021-22. The production has, however, declined in the period of investigation. The decline in production in the period of investigation is despite increase in domestic sales, export sales and captive consumption.
- e. The capacity utilisation has increased in 2020-21 but declined in 2021-22. With the decline in production in the period of investigation, the capacity utilisation has further declined in the period of investigation. The domestic industry has contended that they were forced to reduce production in the period of investigation.
- f. The domestic sales of the domestic industry have also increased over the injury period. The increase in sales volume from 2021-22 is not commensurate with the increase in capacity and production of the domestic industry which is sufficient to cater the entire Indian demand. Further, the domestic industry was not able to sell the product to the extent of increase in production. This resulted in significant piling up of the production in stocks.
- g. There were no exports by the domestic industry in the period 2019-20 and 2020-21. Export started in 2021-22 and increased sharply in the period of investigation.
- h. The captive consumption of the domestic industry has also increased over the injury period.

b. Inventories

123. The table below shows the opening, closing and average inventory of the domestic industry.

S. No.	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend		100	647	1,548	1,260

124. It is seen that the average inventory with the domestic industry increased sharply by March 2021 and thereafter March 2022. However, the inventories declined by the end of the POI. The average inventory increased in 2020-21, further increased in the year 2021-22 but has declined in the period of investigation.

c. Market share

125. The information regarding market share is given below: -

S. No.	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend		100	221	478	553
2	Subject countries	%	***	***	***	***

	Trend		100	90	52	40
3	Non-subject countries	%	***	***	***	***
	Trend		100	24	9	9

126. It is seen that with the increase in the capacity, the market share of the domestic industry has increased over the injury period. The market share of the subject countries has declined over the injury period. The capacity of the domestic industry is sufficient to cater the entire demand in the country, therefore, considering the demand in the country, the domestic industry's share is below the level it can cater.

d.Profit / loss, cash profits and return on capital investment.

127. The information regarding profitability is given below: -

SN	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Profit/loss	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend		100	168	-47	-46
2	Profit/loss	Rs Lakhs	***	***	***	***
	Trend		100	361	-187	-196
3	Cash profit	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend		100	141	-20	-17
4	Cash profit	Rs Lakhs	***	***	***	***
	Trend		100	304	-81	-74
5	PBIT	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend		100	168	-47	-45
6	PBIT	Rs Lakhs	***	***	***	***
	Trend		100	361	-187	-195
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend		100	128	-16	-30

128. The Authority notes that the domestic industry was in profits in 2019-20. The profitability of the domestic industry improved in the year 2020-21 with restoration of production of HCC. However, in 2021-22, the profitability of the domestic industry declined significantly in that year. The domestic industry started suffering financial losses in 2021-22, which increased in the period of investigation.

129. The domestic industry was earning cash profits, positive PBIT and return on investment in 2019-20. The performance of the domestic industry on these accounts improved in 2020-21, but declined in 2021-22 significantly. The performance of the domestic industry deteriorated further in the period of investigation. The domestic industry recorded loss before interest and negative return on investment in the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity.

130. The relevant information is given below: -

SN	Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	No of employees	Nos.	***	***	***	***
	Trend		100	103	424	516
2	Salaries & wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend		100	132	454	531

3	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend		100	247	544	496
4	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend		100	238	128	96

131. It is seen that the employment and wages show an increasing trend over the injury period and the period of investigation. The employment has increased with the commencement of production by UPL. Productivity shows an increasing trend over the injury period as UPL started commercial production.

f. Growth.

132. The relevant information is given below: -

S. No.	Particulars	Units	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	Y/Y	71%	272%	0%
2	Capacity utilization	Y/Y	31%	-41%	-5%
3	Production	Y/Y	147%	120%	-9%
4	Sales	Y/Y	116%	84%	9%
5	Inventory	Y/Y	547%	139%	-19%
6	Market Share	Y/Y	15%	32%	9%
7	Profit/loss	Y/Y	68%	-128%	3%
8	Cash profit	Y/Y	41%	-114%	-16%
9	PBIT	Y/Y	261%	-152%	-5%
10	ROI	Y/Y	28%	-113%	-85%

133. It is seen that that while few volume parameters showed a positive trend over the injury period, the profit/loss, PBIT, ROI, production and capacity utilization show a negative trend in the period of investigation.

g. Ability to raise capital investment.

134. UPL made fresh investment of more than 500 Cr in the product under consideration. However, the domestic industry has been unable to achieve optimum level of production and capacity utilisation for the product under consideration, despite significant capacities in the country. The domestic industry is incurring financial losses, loss before interest and tax and negative return on capital employed.

h. Margin of dumping.

135. The margin of dumping may be an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The dumping margin determined for each of the subject country, is above *de-minimis* and significant.

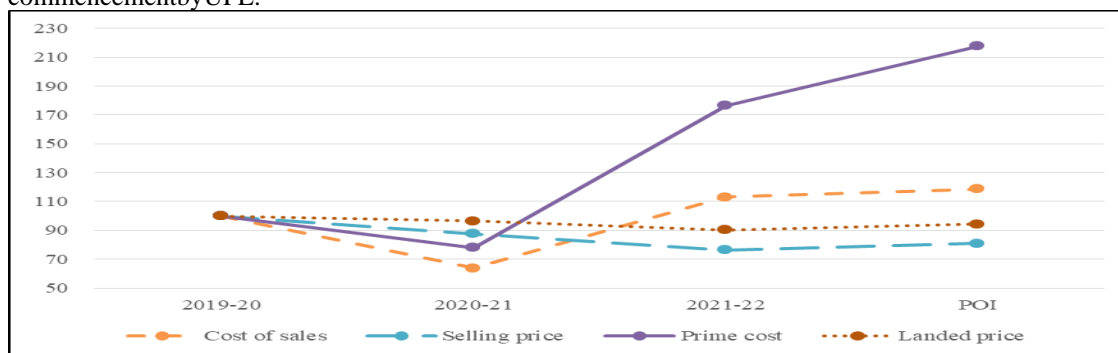
i. Factors affecting prices of the domestic industry.

136. The table below shows the movement of prices of imports and prime cost, cost of production (at normated level) and the selling price of the domestic industry over the injury period.

S. No.	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	64	113	119
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend		100	88	76	81
3	Prime cost	₹/MT	***	***	***	***

	Trend		100	78	177	218
4	Landed price	₹/MT	1,84,077	1,77,443	1,66,368	1,73,637
	Trend		100	96	90	94

137. It is seen that in the year 2019-20 and 2020-21, the landed price of imports was materially higher than the cost of production of the domestic industry. The cost of production declined in 2020-21 but increased in the year 2021-22 and the period of investigation. In order to examine if the increase in the cost of production was due to new plant set up UPL, the Authority has compared the cost of production at normated level (fixed costs normated at highest capacity utilisation) and prime cost (only variable costs) over the injury period. It is seen that the costs have increased over the injury period and the increase was not due to commercial production commencement by UPL.



138. While the costs have increased, the landed price of imports has declined. The landed price of imports have not moved in line with the increase in the cost of production. As a result, the domestic industry have not been able to increase their prices in line with the cost of production. Therefore, the imports from the subject countries are the only factor affecting the prices of the domestic industry.

j. Conclusion on injury

139. On the basis of the above analysis, the following can be concluded: -

- The imports in absolute and relative terms have shown a decline over the injury period with the commencement of production by UPL.
- Considering the fact that the capacity with the domestic industry is now sufficient to meet the demand, the volume of dumped imports in both absolute and relative terms in the period of investigation is considerably high.
- The landed price of import is below the selling price of the domestic industry in the period of investigation resulting in positive price undercutting.
- The import price has not moved in line with the movement of raw material costs. While the raw material costs have increased, the import price has declined.
- The import price has not increased in line with the increase in the cost of sales. This has prevented the domestic industry from increasing prices. The imports were suppressing the prices of the domestic industry.
- The production of the domestic industry has increased over the injury period. However, the production declined in the period of investigation as the domestic industry were forced to suspend commercial production.
- The market share of the domestic industry has increased over the injury period. However, this increase in share has been achieved by the domestic industry by selling at losses.
- Sales volume of the applicant increased in 2020-21 with the commencement of production by HCC and in 2021-22 with commencement of commercial production by UPL. However, production declined again in the period of investigation.
- The domestic industry is suffering financial losses and a negative return on capital employed. Domestic industry has suffered financial losses even at normated cost of production.
- The dumping margin determined for each of the subject country is above de-minimis and significant.

- k. The growth of the domestic industry has been negative both in terms of volume and price.

NON-ATTRIBUTION ANALYSIS.

140. As per the Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury.

a. Volume and price of imports from third countries.

141. The table below shows the volume and price of imports in the period of investigation.

S. No.	Particulars	Import volume in MT	Import price CIF ₹/MT	Share in total imports
1	China	3,400	1,58,735	52.40%
2	Japan	1,704	1,72,113	26.26%
3	Republic of Korea	936	1,78,771	14.43%
4	European Union	232	1,76,036	3.58%
5	Subject countries	6,272	1,66,001	97.21%
6	Taiwan	180	1,52,497	2.79%
7	Total	6,452	1,65,603	100%

142. It is seen that in addition to the subject countries, there are imports of the product under consideration from Taiwan. The volume of imports from Taiwan are, however, below *de-minimis* level and they could not have been a cause of injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

143. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, a decline in demand could not have been a cause of injury to the domestic industry.

c. Pattern of consumption

144. No significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in this regard. Therefore, it could not have been a cause of injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition

145. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry. Therefore, conditions of competition could not have been a cause of injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

146. The investigation has not shown that there was any significant change in technology which could not have been a cause of injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry

147. The price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, the analysis on injury is not misrepresentative due to possible inclusion of export performance.

148. It is seen that there are no other factors which could have caused material injury to the domestic industry. Therefore, the Authority notes that the material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports as is established below.

- a. The landed price of imports has not increased in line with the increase in the cost of sales. While the cost of sales has increased, the price of the imports has declined.
- b. The landed price of imports is significantly below the cost of sales and the selling price of the domestic industry. The imports are undercutting the selling price and cost of the sales of the domestic industry which has prevented the domestic industry from not aligning its selling prices in line with the movement in cost. The landed price of imports has been suppressed the prices of the domestic industry.
- c. The price pressure from the dumped imports has forced the domestic industry to sell at financial losses. The domestic industry has also suffered a negative return on capital employed.
- d. The continuous low priced of imports has not allowed the applicants to utilize its capacity to optimum level.
- e. The production of the domestic industry has declined in the period of investigation.
- f. The market share of the domestic industry is below the level which it could have catered.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

149. The Authority has determined the non-injurious price for the applicants on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the applicants. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

S. No.	Particular	NIP USD/MT	Landed price USD/MT	Injury margin USD/MT	Injury margin %	Injury margin Range
1	China PR					
a	Hebei Chengxin Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30
2	European Union					
a	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín	***	***	***	***	0-10
b	Any other	***	***	***	***	0-10
3	Japan					
a	Any	***	***	***	***	20-30
4	Korea RP					
b	Any	***	***	***	***	20-30

INDIAN INDUSTRY ISSUE

J.1 Submissions made by the other interested parties

150. The other interested parties have submitted as follows with regards to Indian Industry issues:

- a. Imposition of duties will adversely impact the user industry, mainly the common masses as 60% of the consumption of like article in India goes for agriculture and pharma sector.
- b. Increase in price of the product will impact the price of the lifesaving drugs such as Ampicillin, Cephalexin, Clopidogrel and fungicides, fragrances (phenethyl alcohol), antibiotics, and other pharmaceuticals.
- c. DCM Shriram Limited is the sole global producer for one of the critical intermediate drugs – D (-) Alpha Phenyl Glycine Chloride Hydrochloride (PGCH) used for production of Cephalexin.

- d. Imposition of the measures would allow domestic producers to form cartels resulting in creating barriers to enter the market.
- e. Anti-dumping duties will result in losses to the user industry as there is very little margin on the goods produced using the product under consideration.
- f. Widespread protests have been held against HCC for unsafe waste disposal from its manufacturing plants, leading to significant land and water pollution in local areas.
- g. The supply from the applicants is erratic.
- h. The user industry is forced to import as the applicants are not able to meet the purity requirements.
- i. Product supplied by UPL faces quality issues in the pharma sector which accounts for 25-30% of the Indian demand.

J.2 Submissions made on behalf of the applicants.

151. The applicants have submitted as follows with regards to Indian Industry issues:

- a. The impact of the anti-dumping duty on downstream sectors and products is insignificant.
- b. The imposition of anti-dumping duty will benefit the upstream industry to flourish. The raw material required for the production of the product under consideration are ammonia, caustic soda, sulphuric acid and natural gas which are available in the Indian market and which the domestic industry has completed sourced for its requirements from the Indian market.
- c. Imposition of anti-dumping duty would be in the interest of domestic manufacturers as it would allow the domestic industry to compete with the dumped imports and improve their financial health.
- d. Imposition of anti-dumping duty would be in the interest of consumers to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition with fair priced imports. Furthermore, the domestic industry unlike the Chinese producers who have the option to switch markets if they don't find buyers to their terms, will keep the consumers interest in mind. Consumers therefore can maintain a lower degree of inventory and will not have a significant amount of blockage of capital employed when procuring from the domestic industry in comparison to exporters.
- e. Imposition of anti-dumping duty would be in the interest of public at large to have a strong and competitive domestic production of the product.
- f. The viability of the consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices.
- g. The objective of anti-dumping duties is not to restrict imports and/or protect the domestic industry but rather to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject countries and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
- h. The purpose of anti-dumping duties is also recognized by the Hon'ble Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority* [2006 (202) E.L.T. 23 (S.C.)] wherein it was highlighted the role played by the anti-dumping law help in helping achieve India's national aim of creating a modern, highly industrialized, powerful state.
- i. With regards to claim regarding widespread protests against Hindusthan Chemical Company, the matter has been examined by the Hon'ble National Green Tribunal and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the company has further received environment clearance for operation.
- j. The applicants have supplied the purity as required by the consumers

J.3 Examination by the Authority.

152. The Authority underscores that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The recommendation, if any, of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is based on a detailed analysis regarding dumping, injury and the causal link between the two and is a mechanism to ensure a level playing field. It is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the presence of such measures. Far from diminishing competition, the anti-dumping measures serve to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
153. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide

relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigations, including effect of an antidumping duty on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

154. The following users registered themselves as an interested party in the present investigation.

S. No.	Importer/User
1	Asian Chemtech Private Limited
2	Bharat Rasayan Limited
3	Chemtech Intermediates Private Limited
4	DCM Shriram Industries Limited
5	Eurofine Chemicals Limited
6	Emmenar Pharma Private Limited
7	Hemani Industries LTD
8	M B Sales Corporation
9	Meghmani Organics Limited
10	Premier Intermediates Private Limited

155. From the above list of the users, only Bharat Rasayan Limited and DCM Shriram Industries Limited have filed user questionnaire response.

156. The Authority had also issued an economic interest questionnaire. The applicants and DCM Shriram Industries Limited have filed a detailed reply to this questionnaire.

157. As regards the submissions regarding impact on user industry the Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of antidumping measures is not to restrict imports from the subject countries in any way, and, to affect the availability of the products to the consumers.

158. The Authority has examined the questionnaire response filed by the user industry. It is seen that the product under consideration is used in the following product: -

DCM Shriram Industries Limited	
SN	Product
1	DL-2-(2-Chloro Phenyl) Glycine
2	DL Alpha Phenyl Glycine
3	Alpha Phenyl Glycine
4	Alpha Phenyl Glycine Chloride Hydrochloride
5	Alpha Phenyl Glycine Dane Salt
6	SIPA-2 under Contract Manufacturing
7	Valine
8	BENZYL CYANIDE

Bharat Rasayan Limited	
9	4-Acetyl 2-Methyl Benzamide (Ambad) 98%
10	Fenvalerate Technical
11	PARA-CHLORO-A-ISO (PCA POWDER)
12	Para Chloro Benzal Cyanide
13	Para Chloro Phenyl Acetic Acid (Pcpaa Powder)
14	Lambda Cyhalothrin Technical(Pw)
15	Lambda Cyhalothrin Technical(Lq)
16	Cypermethrin Technical
17	Alpha Cypermethrin Technical
18	Fluxametamide

159. The table below shows the share of the product under consideration in the total cost of downstream product and its impact on the same.

S. No.	Product	Consumption norms	Impact %	Impact Range
1	DL-2-(2-Chloro Phenyl) Glycine	***	***	1-2%
2	DL Alpha Phenyl Glycine	***	***	1-2%
3	D(-) Alpha Phenyl Glycine	***	***	Less than 1%
4	D(-) Alpha Phenyl Glycine CHLORIDE HYDROCHLORIDE	***	***	Less than 1%
5	D(-) Alpha Phenyl Glycine Dane Salt	***	***	Less than 1%
6	Valine	***	***	1-2%
7	BENZYL CYANIDE	***	***	3-4%
8	4-Acetyl 2-Methyl Benzamide (Ambad) 98%	***	***	Less than 1%
9	Fenvalerate Technical	***	***	1-2%
10	Para-Chloro-A-Iso (PCA Powder)	***	***	1-2%
11	Para Chloro Benzal Cyanide	***	***	2-3%
12	Para Chloro Phenyl Acetic Acid (PCPAA Powder)	***	***	2-3%
13	Lambda Cyhalothrin Technical(Pw)	***	***	Less than 1%
14	Lambda Cyhalothrin Technical(Lq)	***	***	Less than 1%
15	Cypermethrin Technical	***	***	Less than 1%
16	Alpha Cypermethrin Technical	***	***	Less than 1%
17	Fluxametamide	***	***	Less than 1%

160. Hence, as regards the submissions regarding impact on user industry, the Authority notes that the impact is less than 1% in more than fifty percent of the downstream products whereas for many others it is between 1% -2%.

161. The user industry had contended that the domestic industry was forced to import because the it could not supply the product with desired purity. The Authority has examined the certificate of analysis provided by the applicants and found that the product supplied by the applicants has the same purity content as the exporters. Therefore, the contention cannot be accepted.

162. The Authority notes that a recent significant investment (Rs. 500 crore) by a domestic industry demonstrates a commitment to bridging the demand-supply gap. However, the current situation of dumping forced domestic players to suspend production due to economic unviability. It is also seen that as compared to the period of investigation; the landed price of imports was higher in past. The consumers have set up their plants considering fair market conditions. It cannot be construed that the operations of the consumers would become unviable, merely because dumping is prevented by imposition of duty and fair competition is restored in the market. Anti-dumping duties can create a level playing field for domestic producers, allowing them to compete fairly and continue supplying the market.
163. It is also seen that there is no demand and supply gap in the country and the imposition of anti-dumping duty will not lead to nonavailability of the product for the consumers. In fact, the lead time for supply may be lower if the material is purchased from the domestic market and the users can maintain lower degree of inventory. Further, the anti – dumping duties will not restrict imports from the subject countries as the imports can continue to happen at fair prices.
164. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. It is also seen that the prices in the past were higher than the current prices. The imposition of anti-dumping duty will only ensure that the import prices are restored to fair prices.
165. It is also seen that the domestic industry has sourced its entire requirements from the domestic market. Therefore, the imposition of the imposition of duties will lead to increase in the demand for the upstream products and also help the upstream industry to flourish.

K. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

K.1 Submissions made by the other interested parties.

166. The other interested parties have submitted following comments to disclosure statement.
- a. There is no examination of the excessive confidentiality claimed by the domestic industry.
 - b. There is also no analysis relating to the volume of imports if they are significant in absolute as well as relative terms.
 - c. Hebei Chengxin Co. Ltd. has cited the decision of Hon'ble CESTAT in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing vs DA 2011. The Hon'ble CESTAT had examined factors such as increase in domestic sales, production and capacity utilisation, increased profits, return on capital employed and inventory does not show injury. The respondent has compared the performance of the domestic industry in the subject investigation with the performance of the domestic industry in the aforementioned case of Bridge Stone Tyre Manufacturing and has claimed that the investigation should be terminated on the same lines.
 - d. There is no analysis of the increase in the depreciation cost, interest cost, wages and overheads over the injury investigation period as a result of increase in capacity by 537% over the injury period.
 - e. The cost of production should be adjusted for unreasonable, abnormal and temporary increase in the cost of raw materials / utilities during the period of investigation on account of the Russia-Ukraine conflict so as to reflect the reasonable cost of production of the subject goods.
 - f. Considering the low volume of imports and negative price undercutting from Czech Republic, the imports from Czech Republic cannot be a cause of injury. The investigation should be terminated.
 - g. The domestic industry has submitted that they imported from non-subject countries. However, HCC has imported from Korea RP and the information has been concealed.
 - h. The Authority has noted that the imports in the past were at undumped prices. The prices in the past were at the same level and if the current prices are dumped prices, it demonstrates that the imports in the past were at dumped prices too.
 - i. The Authority is requested to calculate normated cost of production by considering 90% or monthly highest capacity utilisation and best consumption norms between the two producers since new plant will have higher consumption norms.
 - j. The impact of anti-dumping duty as calculated by the Authority is under stated.
 - k. The Authority has noted that Emmenar Pharma Pvt Ltd has purchased from the domestic industry. The purchase was made in the dire need when the users had no other options.

- l. It is not known whether the Authority has examined the records of the applicant to verify the vital fact with regard to the imports made by them or relied only on the transaction wise import data as recorded in the disclosure statement.
- m. The Authority has failed to verify how despite uncertain and irregular supply of natural gas and technological bottlenecks the domestic industry is able to conform to the 98% purity level.
- n. Determination of a suitable PCN methodology is the bounden responsibility of the Authority. It is immaterial whether and what the interested parties say and comment.
- o. The abrupt withdrawal of exporters from several countries should have triggered a deeper investigation by the Authority. This indicates an underlying shift in the market that impacts the product's economic conditions and necessitates thorough scrutiny.

K.2 Submissions made by the domestic industry.

167. The domestic industry has submitted the following comments to the disclosure statement.

- a. The Authority is requested to kindly specify all the codes in which the product is imported in the duty table or recommend duty at 4-digit level. This is particularly important because of the recent decision of the Gujarat High Court in the matter of Ajanta Pvt Ltd. v. Union of India.
- b. Normal value determined for China PR and non-participating countries is not appropriate as higher normal value for participating producers will discourage participation from the exporters.
- c. The Authority has not considered the price trend of Hebei Chengxin Co., Ltd. China and Nippon Soda, Japan over the injury period which shows selective aggressive pricing in the Indian market.
- d. While the applicants had claimed production volume ratio for allocating certain expense, the Authority has allocated them based on the production value ratio. These expenses are incurred on per unit basis and allocation on production value will not be appropriate.
- e. Net fixed assets and working capital allowed in the calculation of non-injurious price of UPL are significantly lower than as claimed by UPL and no reason has been provided.
- f. The Authority has not considered that stock piling due to dumping in the domestic market led to curtailed production which ultimately resulted in the decline in inventory in the period of investigation.
- g. The Authority has not considered calculation of contribution. The domestic industry is operating with negative contribution. While a producer may bear a loss on its fixed cost, if the selling price is below even the marginal cost to produce there is no business justification in carrying out production.
- h. Even though the other parties have said that raw material prices have declined, they continue to remain higher than base year.
- i. Examination of the post period of investigation trends would imply requirement of collection of fresh data of the domestic industry (to examine injury) and the participating producers (to examine dumping). By the time the Authority completes the entire process, the post period of investigation too would become stale, and the data provided would again not reflect market fluctuations.
- j. In case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels. Further, lead time of the domestic industry is significantly lower as compared to the imports.

K.3. Examination by the Authority

168. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
169. The Authority notes that Hebei Chengxin Co. Ltd. has compared the facts of the present case with the Bridge Stone Tyre Manufacturing vs DA 2011 in CESTAT. The Authority notes that the facts of both the cases are different. The domestic industry in the present case has suffered losses, negative return on capital employed and decline in production and capacity utilisation, which is not similar to what has been noted in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing vs. DA 2011. The only similarity is that the domestic sales of the domestic industry have increased in both the cases. However, the increase in the present case has come at a cost as the domestic industry has lowered its prices and suffered losses to increase its market share. The Authority, therefore, notes that no parallel can be drawn between the two cases and hence the request for termination of the instant case does not hold ground.

170. As regards the comments of the domestic industry on allocation of inappropriate ratios and inadequate disclosure of the non-injurious price, the Authority notes that the non-injurious price has been determined and disclosed based on the Annexure-III of the Rules and the consistent practice followed by the Authority.
171. While the Authority acknowledges its responsibility to establish a suitable PCN methodology, it emphasizes that comments from interested parties can be highly material. Industry expertise can provide crucial insights for an accurate methodology demonstrating the importance of transparency within the investigative process. The Authority notes that constructive inputs significantly enhance the robustness of an investigation. Emmennar's dismissal of this role by saying that it is immaterial whether and what the interested parties say and comment undermines the investigative process's transparency and rigor. It was only after taking into consideration the submissions made by the parties that the Authority decided not to adopt any PCN methodology in the subject investigation.
172. As regards the comments on imports made by the domestic industry, the Authority has verified it from DG Systems data and the records maintained by the domestic industry. There are no imports in the period of investigation.
173. As regards the comments on high depreciation cost, wages and interest cost on account of new plant, the Authority notes that it has examined the performance even at normated cost of production. It is seen that the domestic industry has suffered even when the plant of the domestic industry is considered operating at optimum capacity utilisation.
174. As regards the comments that the prices in the past were at the same level and if the current prices are at dumped prices, it demonstrates that the imports in past were at dumped prices too. The Authority notes the comment of the interested parties fails to take into consideration the increase in the raw material cost. The cost of raw materials has increased over the injury period but the import price has declined.
175. On the comments made by the opposing interested parties that the cost of production is required to be adjusted, the Authority notes that increase in cost of raw materials is a common factor for the applicant as well as the exporters. The question of injury to the domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions but has to be decided on prevailing condition. Under the rules, the Authority is required to consider the domestic industry as it exists and examine whether the performance of the domestic industry has deteriorated over the injury period.
176. Emmennar has submitted that several participating exporters have withdrawn from the present investigation proceedings after stating that due to the "rapid changes in business scenario exporters are not in a position to continue their business of the subject goods". Emmennar states that such statements from exporters and their consequent withdrawal needs critical examination from the Authority. It is noted that Emmennar has placed undue emphasis on the general statement made by withdrawing exporters. The decision to participate in any trade remedial investigation is a voluntary decision and is guided by commercial interest. The participating exporters who have subsequently withdrawn from the investigation merely stated this general statement and did not point out the "rapid changes" which forced them to discontinue their business of the subject goods. Unless an interested party specifically points out an issue, it is unclear how the Authority can analyse its nature. Even Emmennar who has asked for analysis of this issue, has failed to point out any factor in this regard. The Authority cannot be obliged to examine every unsubstantiated claim or mere utterance by an interested party.

CONCLUSION & RECOMMENDATION

177. After examining the submission made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - a. The application requesting anti-dumping duties has been filed by Hindusthan Chemical Company and UPL Limited.
 - b. The product under consideration in the present investigation is Sodium Cyanide regardless of its form.
 - c. The product produced by the Indian industry is a like article to the imported product.
 - d. The applicants had imported in past prior to commencement of commercial production by UPL Limited. The applicants have not imported the product under consideration in 2020-21 or in the period of investigation.
 - e. The applicants satisfy the requirement of Rule 2(b) of the anti-dumping rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the anti-dumping rules.

- f. Considering the normal value and the export price for the product under consideration, the dumping margin for the product under consideration from the subject countries has been determined, and the margins are positive.
 - g. The domestic industry has suffered injury as is established by following: -
 - i. Considering the fact that the capacity with the domestic industry is now sufficient to meet the demand, the volume of dumped imports in both absolute and relative terms in the period of investigation is considerably high.
 - ii. The imports were suppressing the prices of the domestic industry.
 - iii. The production of the domestic industry has declined in the period of investigation as the domestic industry were forced to suspend commercial production.
 - iv. The domestic industry had to sell at losses to increase its market share. The market share of the domestic industry is significantly below the level which it can cater.
 - v. The domestic industry is suffering financial losses and a negative return on capital employed.
 - h. The other interested parties had contended that the injury is due to capacity expansion. However, the domestic industry has suffered financial losses even at normated cost of production.
 - i. There is no other factor which could have caused material injury to the domestic industry. Injury suffered by the domestic industry is only attributable to the dumping of the product in the Indian market.
 - j. The domestic industry has made significant investment (Rs. 500 crore) to bridge the demand-supply gap. The current situation of dumping has forced domestic players to suspend production due to economic unviability.
 - k. There is no demand and supply gap in the country. The capacity of the domestic industry is sufficient to cater for the entire demand in the country.
 - l. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, the impact of the anti-dumping duty on the downstream industry will not be significant.
178. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules and having quantified the impact of imposition of anti-dumping duty, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of product under consideration from the subject countries.
179. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty equal to the lesser of margin of dumping or margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of such revised definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

.Duty Table

SN	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7
1	2837	Sodium Cyanide, regardless of its form	China	Any country including China	Hebei Chengxin Co. Ltd.	286
2	-do-	-do-	China	Any country including	Any producer other than mentioned in SN (1) above.	554

				China		
3	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	China	Any producer other than mentioned in SN (1) above.	554
4	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín	13
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producer other than mentioned in SN (4) above.	230
6	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	European Union	Any producer other than mentioned in SN (4) above.	230
7	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer	447
8	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	Japan	Any producer	447
9	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer	413
10	-do-	-do-	Any country other than China, EU, Japan and Korea	Korea RP	Any producer	413

The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

FURTHER PROCEDURE

180. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority